RNI NO. DELHIN/2012/48369
वर्ष 8 अंक 195
नई दिल्ली, बुधवार, 20 मई, 2020
पृष्ठ 12 मूल्य ₹ 3
नगर संस्करण

नई दिल्ली, लखनऊ, रायपुर और फरीदाबाद से प्रकाशित

पायनियर

www.dailypioneer.com

शिल्पा शेट्टी ने 'गोरे-गोरे मुखड़े...' पर किया डांस
विविध-12

श्रमिक विशेष ट्रेनों पर केंद्र सरकार सख्त, राज्यों से छीना अधिकार

- नई मानक परिचालन प्रकिया (एसओपी) जारी, अब राज्यों की मंजूरी जरूरी नहीं- हटाया प्रावधान
- गृह मंत्रालय के परामर्श से रेल मंत्रालय ही देगा अनुमति, राज्यों से कहा मुहैया कराएं ट्रेनों की मांग

वाराणसी में रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को स्वास्थ्य जांच के लिए पंक्तिबद्ध खड़े अन्य प्रदेशों से पहुंचे लोग

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

केंद्र और पश्चिम बंगाल के बीच चल रही तनातनी के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को प्रवासी मजदूरों को लेकर जाने वाली ट्रेनों के संचालन का अधिकार आपदा प्रबंधन कानून में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ में ले लिया। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किया है जिसके तहत रेलवे को श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए राज्य सरकारों से बगैर कोई परामर्श लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से परामर्श लेने की अनुमति दी गई है।

दूसरे शब्दों में ऐसी ट्रेनों के परिचालन के लिए रेलवे को गंतव्य राज्यों की सहमति लेनी जरूरी नहीं है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों पर यह जिम्मेदारी डाली है कि उन्हें रवाना होने वाली ट्रेन की समय सारिणी के बारे में प्रवासी मजदूरों को सूचना देनी होगी तथा फंसे हुए लोगों को पास के रेलवे स्टेशन तक लाना होगा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने संशोधित एसओपी जारी करते हुए कहा कि श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों को चलाने की अनुमति रेलवे मंत्रालय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर देगा। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभारी अधिकारियों को नामित करना होगा। गृह सचिव द्वारा जारी एसओपी में कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जरूरत के मुताबिक ट्रेनों के ठहराव और गंतव्य समेत उसकी समय सारिणी को रेल मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बारे में मंत्रालय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जानकारी देगा जिससे कि वे फंसे हुए मजदूरों को भेजने और उन्हें लेने के लिए उचित व्यवस्था कर सकें। इससे पहले रेलवे ने फैसला किया था कि ट्रेनों के आवंटन के बारे में राज्यों से सलाह लेकर निर्णय लिया जाएगा। समस्या तब शुरू हुई जब केंद्र ने पश्चिम बंगाल सरकार पर आरोप लगाया कि वह प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए ट्रेनों की सुचारू ढंग से आवाजाही के लिए कदम नहीं उठा रही है।

ट्रेनों की आवाजाही के लिए केंद्रीय गृह सचिव द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि रेल मंत्रालय प्रवासी मजदूरों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों का ज्यादा स्थानों पर रुकना सुनिश्चित करेगा। इसमें कहा गया कि ट्रेनों की समय-सारिणी, यात्रियों के प्रवेश और आवाजाही के लिए प्रोटोकॉल, ट्रेन के डिब्बों में दी जाने वाली सेवाएं और टिकट की बुकिंग के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के पास मौजूद व्यवस्था का रेल मंत्रालय प्रचार करे। एसओपी में कहा गया कि भेजने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा रेल मंत्रालय सुनिश्चित करे कि सभी यात्रियों की अनिवार्य रूप से जांच की जाए और केवल बिना लक्षण वाले (शेष पेज 9)

सड़कों-हाईवे पर मजदूरों के लिए होंगी अलग लेन

- हादसों में प्रवासी श्रमिकों की मौत के बढ़ते मामलों ने सड़क परिवहन मंत्रालय को कदम उठाने पर किया मजबूर
- समर्पित लेन में होगी भोजन-पानी, चिकित्सा जैसी सुविधाएं
- राज्यों को जल्द एडवाइजरी जारी कर सकता है गृह मंत्रालय

महाराष्ट्र के यवतमाल में सड़क हादसे में तीन मजदूर और एक बस ड्राइवर मारा गया

लॉकडाउन के दौरान सड़क हादसे:

24 मार्च से 19 मई	(शाम 5 बजे तक)
कुल सड़क दुर्घटनाएं	1,253
कुल मृतक संख्या	456
घायलों की संख्या	930
मृत प्रवासी मजदूर	180
जख्मी प्रवासी श्रमिक	694
मृत-जख्मी अन्य श्रमिक	30 एवं 26
मरे व घायल हुए अन्य	246 एवं 210

दीपक कुमार झा। नई दिल्ली

देश के कई हिस्सों में आए दिन घटने वाली सड़क दुर्घटनाओं में प्रवासी मजदूरों की दुखदायी मौत के बढ़ते मामलों ने सड़क परिवहन मंत्रालय को गृह मंत्रालय एवं राज्य सरकारों से पैदल यात्रियों के लिए समर्पित लेन की पहचान कराने पर बाध्य कर दिया है।

ये लेन, पैदल ही घरों-गांवों को निकले प्रवासी मजदूरों के लिए होंगी और मुश्किलों भरे उनके सफर को आसान बनाने के लिए इनमें एक निश्चित दूरी पर भोजन पानी व चिकित्सा सुविधाओं का इंतजाम करना होगा।

सूत्रों के अनुसार, घर जाने के लिए भारी तादाद में सड़कों पर उतरे प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय अलग से एक एडवाइजरी करने की प्रक्रिया पर काम कर रहा है। हैरानी करने वाली बात यह है कि एक ओर जहां देश लंबे लॉकडाउन के चलते सड़क हादसों में मृतक संख्या में भारी कमी की उम्मीद पाले बैठा है वहीं दूसरी ओर, 24 मार्च (संपूर्ण लॉकडाउन के ऐलान से एक दिन बाद) से 19 मई के बीच 1253 सड़क दुघटनाएं घटीं जिनमें 456 जानें गईं जबकि 930 लोग घायल भी हो गए। मृतकों में 39 फीसदी (180) प्रवासी मजदूर थे। सड़क सुरक्षा से जुड़े एक संगठन द्वारा केंद्र सरकार (शेष पेज 9)

देश में 24 घंटे में 134 लोगों की मौत

- कोविड-19 के 4,970 नए मामले सामने आए, मृतक संख्या 3,163 हुई

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले मंगलवार को एक लाख के पार पहुंच गए जबकि संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या 3,163 पर पहुंच गई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में सोमवार सुबह आठ बजे से लेकर पिछले 24 घंटे में कुल 134 लोगों की मौत हुई और कोविड-19 के 4,970 मामले सामने आए। मंत्रालय ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,01,139 हो गए हैं। इसने बताया कि 58,802 लोग अब भी संक्रमण की चपेट में हैं जबकि 39,173 लोग स्वस्थ हुए हैं और एक मरीज विदेश चला गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, अब तक 38.73 प्रतिशत मरीज ठीक हो चुके हैं।

मंत्रालय ने बताया कि कुल मामलों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। सोमवार सुबह से लेकर अब तक हुई 134 मौतों में, 51 महाराष्ट्र में, 35 गुजरात में, 14 उत्तर प्रदेश में, आठ दिल्ली में, सात राजस्थान में, छह पश्चिम बंगाल में, चार मध्य प्रदेश में, चार तमिलनाडु में तथा पंजाब और जम्मू-कश्मीर में दो-दो, बिहार और तेलंगाना में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है। देश में अब तक हुई कुल 3,163 मौतों में सबसे ज्यादा 1,249 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। इसके बाद गुजरात में 694, मध्य प्रदेश में 252, पश्चिम बंगाल में 244, दिल्ली में 168, राजस्थान (शेष पेज 9)

सड़क हादसों में गई 16 श्रमिकों की जान

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

अपने गांव-घर जाने की जद्दोजहद में लगे मजदूर देष भर में सड़कों पर हादसों का षिकार होकर दम तोड़ रहे हैं, लेकिन केंद्र या राज्य सरकारें उनकी परेशानियों का स्थायी हल निकालने की कोषिष नहीं कर रही हैं। बीते चौबीस घंटों में बिहार, उत्तर प्रदेष और महाराश्ट्र में हुई सड़क दुर्घटनाओं में कम से कम 16 मजदूरों की जान चली गई है।

बिहार के भागलपुर जिले में मंगलवार तड़के ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने से नौ लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब करीब दर्जन भर प्रवासी मजदूरों को लेकर कटिहार की ओर से खगड़िया की ओर जा रहे ट्रक की नौगछिया के पास एनएच 31 पर विपरीत दिशा से आ रही बस से टक्कर हो (शेष पेज 9)

मुंबई ने फिर दहलाया, स्टेशन पर मजदूरों का सैलाब, लाठीचार्ज

- श्रमिक ट्रेन से बिहार जाने को हुआ था हजार मजदूरों का पंजीकरण-उमड़ा रेला, झांसी स्टेशन पर बिस्किट-चिप्स की लूट

पायनियर समाचार सेवा। मुंबई

मुंबई के बांद्रा में ट्रेन पकड़ने के लिए प्रवासी मजदूरों की लगी भारी भीड़

लॉकडाउन के दौरान घर वापसी के लिए बेताब प्रवासी मजदूरों की दिक्कतों का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। मुंबई के बांद्रा स्टेशन के बाहर मंगलवार सुबह एक बार फिर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब श्रमिक स्पेशल ट्रेन पकड़ने के लिए पांच हजार से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए, जबकि ट्रेन से यात्रा करने के लिए सिर्फ एक हजार लोगों का रजिस्ट्रेशन था।

स्टेशन के बाहर लगातार बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। बाद में पुलिस ने सभी मजदूरों को वहां से हटा दिया। श्रमिक स्पेशल ट्रेन को बांद्रा से बिहार के पूर्णिया जाना था। इसी तरह का दृश्य उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला जहां प्रवासी मजदूरों ने जमकर बवाल काटा और स्टेशन पर लगे स्टालों से बिस्कुट और चिप्स के पैकेट लूट लिए गए। घर लौटने के लिए उमड़े प्रवासियों के इस रेले से सारी व्यवस्थाएं (शेष पेज 9)

चक्रवाती तूफान अम्फान पड़ सकता है कमजोर

- ओडिशा तट के करीब पहुंचा, कुछ हिस्सों में बारिश

पायनियर समाचार सेवा। कोलकाता, भुवनेश्वर, नई दिल्ली

महाचक्रवात अम्फान के ओडिशा तटों के करीब पहुंचने के साथ ही कुछ हिस्सों में बारिश हुई जबकि राज्य सरकार ने संवेदनशील एवं निचले इलाकों को खाली कराने के प्रयास तेज कर दिए हैं।

मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण-दक्षिणपश्चिम दीघा से 670 किलोमीटर दूर स्थित यह तूफान उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के पास उत्तर-उत्तरपूर्व दिशा की तरफ बढ़ेगा बुधवार शाम में अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान का रूप लेकर पश्चिम बंगाल-बांग्लादेश के तटों से टकराएगा। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि अम्फान 20 मई को बेहद भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच पश्चिम बंगाल-बांग्लादेश तटों से गुजर सकता है। तटों से टकराने से पहले इसकी प्रचंडता कुछ कम होगी और हवाओं की गति निरंतर 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे बनी रहेगी जो बीच-बीच में प्रति घंटे 180 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकती है।

उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से फोन पर बात की और उन्हें महाचक्रवात अम्फान से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिम मध्य और (शेष पेज 9)

बाजार

सेंसेक्स	30,196	↑	167
निफ्टी	8,879	↑	55
सोना	/10g		
चांदी	/kg		

क्विक न्यूज

कश्मीर में मुठभेड़, दो खूंखार आतंकी मार गिराए गए

श्रीनगर। श्रीनगर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में अलगाववादी संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत के अध्यक्ष अशरफ सहराई के पुत्र जुनय सहराई सहित दो आतंकवादी मारे गए। जुनय सहराई मार्च 2018 से लापता था और बाद में एके-47 थामे हुए उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। सहराई ने कश्मीर विवि से एमबीए की अपनी डिग्री पूरी की थी। यह पहला ऐसा मामला है, जहां किसी अलगाववादी नेता का बेटा आतंकी संगठन में शामिल हुआ। मुठभेड़ में सीआईपीएफ और राज्य पुलिस के एक-एक कर्मी जख्मी हुए है। अभियान में ढेर किया गया एक आतंकी हिज्बुल मुजाहिदीन का शीर्ष कमांडर था जबकि दूसरा विदेशी नागरिक है।

बसों पर सियासत जबरदस्त

उप्र कांग्रेस अध्यक्ष तथा प्रियंका के निजी सचिव पर एफआईआर

- कांग्रेस द्वारा भेजी बसों की सूची में बाइक, ऑटो-रिक्शा, ट्रैक्टर, कारों के नंबर शामिल: उप्र सरकार

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश में नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ समेत विभिन्न जगहों पर फंसे लोगों को उनके गांव-घर बसों से पहुंचाने को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। दिनभर चले राजनीतिक रस्साकसी के बाद मंगलवार शाम को लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के सचिव संदीप सिंह और उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। दोनों नेताओं पर पुलिस व सरकारी कर्मियों के काम में बाधा डालने और सरकार तथा प्रवासी लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए बसों का इंतजाम करने में एजेंसियों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है।

गृहमंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार अंतरराज्यीय बस चलाने की अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद पास जारी किया जाता है। लल्लू या संदीप ने बसों के लिए कोई आवेदन नहीं किया था। इसलिए उन्हें पास जारी नहीं किए गए थे। इसलिए (शेष पेज 9)

सपा नेता और उसके बेटे की सरेआम हत्या, दो अभियुक्त गिरफ्तार

पायनियर समाचार सेवा। संभल

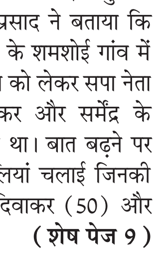

गिरफ्तार आरोपी

संभल के बहजोई क्षेत्र में मंगलवार को आपसी विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी के एक स्थानीय नेता और उसके पुत्र की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि बहजोई थाना क्षेत्र के शमशोई गांव में एक सड़क निर्माण को लेकर सपा नेता छोटे लाल दिवाकर और समेंद्र के बीच विवाद हुआ था। बात बढ़ने पर समेंद्र पक्ष ने गोलियां चलाई जिनकी चपेट में आकर दिवाकर (50) और उसके बेटे (शेष पेज 9)

उधर खुला लॉक, इधर दिल्ली हो गई जाम

- डीएनडी, कालिंदी कुंज, गाजीपुर, फरीदाबाद व गुड़गांव बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतारें
- उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, केजरीवाल ने की समझदारी से काम लेने की अपील

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

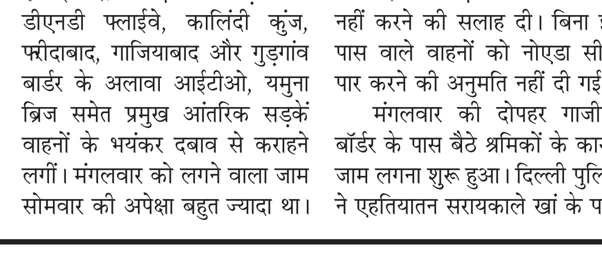

नई दिल्ली में निजामुद्दीन ओवर ब्रिज पर लंबा जाम

लॉकडाउन-4 के दूसरे दिन दिल्ली का ताला खुलते ही सड़कें तो गुलजार हुईं लेकिन देखते ही देखते जाम भी हो गई। दिल्ली-नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे, कालिंदी कुंज, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गुड़गांव बार्डर के अलावा आईटीओ, यमुना ब्रिज समेत प्रमुख आंतरिक सड़कें वाहनों के भयंकर दबाव से कराहने लगीं। मंगलवार को लगने वाला जाम सोमवार की अपेक्षा बहुत ज्यादा था। दिल्ली पुलिस ने एडवायजरी जारी कर दिल्ली-नोएडा के बीच सफर नहीं करने की सलाह दी। बिना ई-पास वाले वाहनों को नोएडा सीमा पार करने की अनुमति नहीं दी गई।

मंगलवार की दोपहर गाजीपुर बॉर्डर के पास बैठे श्रमिकों के कारण जाम लगना शुरू हुआ। दिल्ली पुलिस ने एहतियातन सरायकाले खां के पास बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक को गाजीपुर आने से रोक दिया। इसके बाद मध्य, दक्षिणी और दक्षिणी-पूर्वी दिल्ली को जाने वाली सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थमती चली गई और जाम का दायरा बढ़ता गया। कई प्रमुख सड़कों पर गाड़ियों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं। जाम बढ़ते-बढ़ते आइटीओ तक पहुंच गया। इस जाम से लक्ष्मीनगर समेत पूर्वी दिल्ली का इलाका बुरी तरह प्रभावित हुआ।

बता दें कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में मंगलवार से कई प्रकार की छूट दी है। सभी प्राइवेट और सरकारी ऑफिस खुल गए हैं। सीमित यात्रियों की संख्या की षर्त के साथ बसें, टैक्सी, ऑटो, निजी गाड़ियों को भी इजाजत दे दी गई। इस कारण पिछले करीब दो महीने से घरों में रुके अपने-अपने काम से सड़कों पर निकले। पुलिस की चुनौती बिना पास बॉर्डर पार (शेष पेज 9)

2400 किलोमीटर दूर घर जाने के लिए साइकिलों से निकल पड़े 21 युवक

मंगलवार को इंद्री के गांव खेड़ा पहुंचे, मोहाली फैक्ट्रियों में काम करते थे

पायनियर समाचार सेवा। इंद्री

लाकडाउन के चलते हर वर्ग के लोग परेशान है लेकिन इस लाकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोई सरकारी साधनों से अपने घर पहुंचने में सफल हो रहा है तो वहीं कइयों को अपने घरों में जाने के लिये अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जिसका उदाहरण मंगलवार को उस समय मिला जब मोहाली से चले लगभग 21 लोग इंद्री हल्के के गांव खेड़ा पहुंचे।

ये लोग आसाम के रहने वाले हैं। जब उन्होंने अपनी आपबीती गांव के लोगों को सुनाई तो वे सभी उनकी बातों को सुन कर दंग रह गये। प्रवासी मजदूर दिकरेशा, रामसिंह, माफू, रवि ओर बैंजामिन ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताय कि वे सभी मोहाली में फैक्ट्रियों में काम करते थे।

पिछले दो महीनों से उनको तनख्वाह नहीं मिली। फैक्ट्री मालिक कहते हैं कि जब काम ही नहीं किया तो मेहनताना कैसा। हमने कहा

साहब हम अपने घर चले जायेंगे आप कुछ व्यवस्था कर दो तो उन्होंने कोरा जवाब दे दिया। अपनी व्यथा सुनाते हुए उन्होंने कहा कि लाकडाउन के कारण बस सेवा चालू नहीं है पर घर जाना भी जरूरी था क्योंकि बिना काम प्रदेश में गुजारा नहीं हो सकता है। इसलिए घर वालों से बात की कि साइकिल खरीदनी है परंतु पैसे नहीं है। परिवार वाले बोले कि घर आना जरूरी है इसलिय उन्होंने खाते में पैसे डाल दिए।

उन पैसों से हमने साइकिल खरीदी और अपने घरों की ओर चल दिए। उन्होंने कहा कि देश में हुए लॉकडाउन के कारण उनका जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। हमने मजबूर होकर साइकिलों पर ही अपने घर जाने का मन बनाया है। इसलिए सभी मजदूर साइकिलों पर सवार होकर अपने घर के लिए चल दिए। उन्होंने बताया कि उनका घर यहां से 2400 किलोमीटर की दूरी पर है। इन प्रवासी मजदूरों की बातों को सुनकर ग्रामीणों ने इनके खाने की व्यवस्था की ओर साथ ही ग्रामीणों ने सभी मजदूरों को सूखा भोजन भी सफर के लिए दिया ताकि रास्ते मे अपना पेट भर सके। वहीं गांव खेड़ा के रहने वाले पंकज और विकास का कहना है कि देश पर इस समय कोरोना नामक संकट के बादल छाए है। हम सभी को मिलकर नि:स्वार्थ भाव से जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए क्योंकि जरूरतमंदों की सेवा करने से पुण्य मिलता है ।

युवाओं के मुद्दे पर घिरी भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार : सैलजा

बोली प्रदेश अध्यक्ष युवाओं के हकों को मार रही है सरकार

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने हरियाणा की भाजपा-जजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश के युवाओं के हकों पर कुठाराघात कर रही है। महामारी के इस दौर में भी यह सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है।

कुमारी सैलजा ने कहा कि जिन टीजीटी अंग्रेजी के 1035 व 503 अन्य पदों के परिणाम का युवा पांच साल से इंतजार कर रहे थे, सरकार अब उन्हीं भर्तियों को रद्द करने जा रही है। 523 पीजीटी संस्कृत अध्यापक के पदों का परिणाम वर्ष 2017 को आया था, उन्हें आज तक नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए हैं। इसके साथ ही पिछले दो महीनों में ही 1500 से अधिक कच्चे कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा चुका है। प्रदेश में सरकार के ऐसे जनविरोधी फैसलों की लंबी लिस्ट है। नए रोजगार तो दूर प्रदेश में जिन भर्तियों की प्रक्रिया कई वर्षों पहले शुरू हुई थी, सरकार उन्हें ही लटकाने और रद्द करने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही लोगों को नौकरी से निकालने का षडयंत्र इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री का बयान आया था कि हरियाणा सरकार अगले एक वर्ष के लिए नई सरकारी भर्तियां नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी के भारी विरोध के बाद वह अपनी बात से पलट गए थे, लेकिन असली बात तो सामने आ ही जाती है। क्या मुख्यमंत्री के इस

बयान की ही कड़ी में टीजीटी अंग्रेजी के 1035 व 503 अन्य पदों की पुरानी भर्तियों को भी रद्द किया जा रहा है, इस पर सरकार स्थिति स्पष्ट करे। कुमारी सैलजा ने कहा कि नौकरियों में पारदर्शिता का झूठा दावा करने वाली इस सरकार में दर्जनों सरकारी नौकरी के पेपर लीक हो चुके हैं। जिनमें मुख्य रूप से एचटेट, क्लर्क, एक्साइज इंस्पेक्टर, एचसीएस ज्यूडिशियल, नायब तहसीलदार, आईटीआई इंस्ट्रक्टर के पेपर शामिल हैं। इस सरकार के पारदर्शिता के छूटे ढोंग का इसी बात से पर्दाफाश होता है कि इस सरकार में 40 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। कुमारी सैलजा ने कहा कि कोरोना महामारी से पहले ही हरियाणा प्रदेश में रोजगार की संभावनाएं खत्म होती जा रही थी। वहीं अब महामारी में आई महाबेरोजगारी ने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। बीते दो महीने में ही प्रदेश में लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं और उद्योग-धंधे तबाही की ओर हैं। हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी की जो दर महामारी से पहले देश में सर्वाधिक थी, वह अब 28 प्रतिशत से बढ़कर 43.02 प्रतिशत पर पहुंच गई है। यह आंकडें बहुत ही भयावह हैं। इन आंकड़ों पर गौर किया जाए तो प्रदेश में बेरोजगारी 15 प्रतिशत तक बढ़ गई है।

प्रशासन द्वारा जरूरतमंद लोगों को राशन उपलब्ध कराने के लिए जारी की गई सूची को लेकर रोष

रादौर नगरपालिका में बीएलओ से सूचि में अपने नाम बारे जानकारी लेते लोग।

रादौर। प्रशासन की ओर से जरूरतमंद लोगों को राशन उपलब्ध कराने की जारी की गई सूची को लेकर स्थानीय लोगों में रोष देखा जा रहा है।

लोगों ने सर्वे पर सवाल उठाते हुए इसे जरूरतमंद लोगों के साथ भद्दा मजाक करार दिया है। लोगों का कहना है कि तीन-तीन बाद सर्वे करने के बाद भी जरूरतमंद लोगों को राशन उपलब्ध करवाने में देरी की गई और अब जब सूची जारी की गई तो उसमें भी केवल मात्र प्रशासन की ओर से खानापूर्ति की गई है। जिसकी जांच होनी चाहिएं और दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। पार्षदों का आरोप है कि सर्वे में अधिकारियों ने मनमानी की। जिससे जरूरतमंद लोग सरकार की योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं।

स्थानीय निवासी सीमा, संजीव, विकास, दीपिका, संजय, विजय कुमार, इंद्र, अमित आदि ने बताया कि लॉकडाऊन के समय सरकार ने जरूरतमंद लोगों को राशन उपलब्ध कराने की बात कही थी। अब जब प्रशासन की ओर से जरूरतमंद लोगों को राशन दिए जाने की सूची जारी की गई तो उसमें भी अधिकारियों ने मनमानी की है। केवल मात्र कुछेक लोगों के नाम सूची में डालकर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं।

शिविर में डेरा की साध संगत ने किया 36 यूनिट रक्तदान

शाहाबाद मारकंडा। डेरा सच्चा सौदा की साध संगत द्वारा केशो राम नराती देवी ब्लड बैंक शाहाबाद में रक्तदान शिविर लगाया गया। इस शिविर में ब्लॉक बाबैन की संगत ने रक्तदान किया। शिविर के दौरान ब्लॉक भंगीदास ऋषिपाल व 15 मेंबर संजीव इशरेहड़ी ने साध संगत का मार्गदर्शन किया।

भंगीदास ऋषिपाल ने बताया कि यह शिविर 3 दिवसीय है और पहले दिन साध संगत ने 36 यूनिट रक्तदान किया है। उन्होंने बताया कि डेरा सच्चा सौदा 134 मानव भलाई के कार्य कर रहा है और इसी के तहत यह शिविर लगाया गया है। इससे पहले पिछले सप्ताह भी ब्लॉक शाहाबाद की संगत द्वारा शिविर लगाए गए थे, जिनमें साध संगत ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया था। उन्होंने बताया कि प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डा. भास्कर गुप्ता और ब्लड बैंक इंचार्ज राकेश अंटाल ने

कोविड-19 के कारण ब्लड की कमी के चलते डेरा सच्चा सौदा की साध संगत से शिविर लगाने का आग्रह किया था। इस पर यह कैंप लगाया गया है।

शिविर में हुडा चौकी में तैनात हैड कांस्टेबल विजय कुमार ने भी रक्तदान कर रक्तदाताओं को उत्साहवर्धन किया। विजय कुमार ने बताया कि जैसे ही उन्हें पता चला कि डेरा की साध संगत रक्तदान कैंप लगा रही है, तो वह भी यहां पहुंच गए। शिविर में पंद्रह मेंबर गगन इन्सां, रोशन लाल यारा, गुरमेज इन्सां, मंगल इन्सां (डिंपल), नगरपार्षद सुखविंदर इन्सां, जनक राज इन्सां, भंगीदास अंग्रेज सिंह ने रक्तदान किया।

सरकार जरूरतमंद लोगों को डिस्टेंस राशन टोकन से पहुंचाएगी मदद

करनाल। कोविड-19 वैश्विक महामारी के इस दौर में कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन की स्थिति में राशन बिना न रहे इसके लिए हरियाणा सरकार की ओर से डिस्ट्रेंस राशन टोकन देते हुए जरूरतमंद लोगों को राशन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। करनाल जिला में अब तक करीब 20795 डिस्ट्रेंस राशन टोकन के माध्यम से लगभग 60,386 व्यक्तियों को नि:शुल्क गेहूं व दाल पहुंचाने के लिए कदम बढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही खाद्य एवं पूर्ति विभाग कार्यालय करनाल की ओर से अब तक कुल 20795 डिस्ट्रेंस राशन टोकन की मैपिंग जिला के राशन डिपो के माध्यम से हो चुकी है।

गौरतलब है कि लॉकडाउन की वजह से जरूरतमंद लोगों सहित प्रवासी श्रमिकों को मई-जून माह के लिए डिस्ट्रेंस राशन टोकन जारी किए जा रहे हैं। टोकन के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों व व्यक्तियों को पांच किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति और एक किलोग्राम दाल प्रति परिवार प्रति माह नि:शुल्क उपलब्ध करा रहे हैं।

गोविंद रसोई ने पलायन कर रहे प्रवासियों को भोजन वितरित किया

गोविंद रसोई ने 3373 प्रवासी मजदूरों को भोजन के पैकेट दिए

पायनियर समाचार सेवा। सोनीपत

गोविंद रसोई द्वारा लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद व पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों को भोजन वितरित करने का कार्य लगातार जारी है। मंगलवार को गोविंद रसोई द्वारा राई इंडस्ट्री क्षेत्र, मुरथल और सेल्टर सेंटर राई में एक हजार प्रवासी मजदूरों को भोजन खिलाया साथ ही रास्ते के लिए भोजन के पैकेट वितरित किए।

गोविंद रसोई द्वारा पलायन कर रहे करीब 30 मजदूरों व उनके बच्चों को चप्पल भी वितरित की गई, जोकि नंगे पैर ही जा रहे थे। इसके साथ ही शाम के समय उत्तरप्रदेश से बसों से वापस आये करीब 800 प्रवासी मजदूरों को शंभु दयाल स्कूल में रात्रि भोजन की व्यवस्था की। इस

जरूरतमंदों को भोजन देते गोविंद रसोई के सदस्य।

कार्य में श्याम बालाजी सेवा मंडल का विशेष सहयोग रहा। इसके अलावा सेफ इंडिया फाउंडेशन व रोटरी क्लब आफ सोनीपत एक्सीलेंस व महाराजा अग्रसेन समाज कल्याण समिति सोनीपत द्वारा संचालित गोविंद रसोई द्वारा लॉकडाउन के दौरान गरीब व लाचार लोगों के बीच 3373 लोगों को खाना वितरित किया।

सेफ इंडिया फाउंडेशन के चेयरमैन वाईके त्यागी और प्रधान संजय सिगंला ने बताया कि जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरण कार्य लगातार जारी है। इस कार्य में प्रवीण वर्मा, दीपक सिंगला, दिनेश कुच्छल, महेंद्र अरोरा, अरविंद मित्तल, मनीष बंसल, अशोक गुप्ता, संजीव अग्रवाल, शालू त्यागी, अनिपाल, हरि कौशिक, नरेश कंसल, अनिल गर्ग, प्रमोद जैन, राम अवतार वर्मा, नरेश गर्ग, कैलाश परासर, विनोद राजपाल, आंनद अग्रवाल, शशिकांत, अनिल अत्री, राजकुमार भारद्वाज, नरेश शर्मा और अंकित जैन ने सहयोग दिया।

शहर की आंतरिक सड़कों को सुदृढ़ बनाने का कार्य जोरों पर

महापौर रेणु बाला गुप्ता ने वार्ड-11 सुभाष कॉलोनी की सड़कों का कार्य कराया शुरू

पायनियर समाचार सेवा। करनाल

यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिए शहर की आंतरिक सड़कों का काम जोरों से चल रहा है। नगर निगम की ओर से मॉडल टाउन के मुख्य मार्ग, मुगल कैनाल पुलिया से सेक्टर-6 जीटी रोड तक व सेक्टर-13 की विभिन्न सड़कों को सुदृढ़ बनाने के बाद अब वार्ड-11 की सुभाष कॉलोनी की सड़कों को पेवर फिनीशर मशीन की मदद से सुदृढ़ बनाने का काम शुरू हो गया है।

इसी कड़ी में महापौर रेणु बाला गुप्ता की उपस्थिति में एडवोकेट रजिन्द्र मोहन ने नारियल फोड़कर सुभाष कॉलोनी की सड़कों के कार्य का शुभारम्भ किया।महापौर रेणु बाला गुप्ता ने कार्य की जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड-12 की सुभाष कॉलोनी में चौधरी कॉलोनी टी-प्वॉइंट से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक

विद्यालय (लड़के) रेलवे रोड व प्रेम प्लाजा होटल से माल रोड तक की सड़क का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इस कार्य को अगले चार दिनों में मुकम्मल कर लिया जाएगा, इस पर अनुमानित 15 लाख रुपये व्यय होंगे। उन्होंने बताया कि सड़क को मजबूती प्रदान करने के लिए इस पर 25 एमएम मोटी प्रिमिक्स कारपेट की लेयर बिछाई जाएगी। इस अवसर पर मेयर ने कहा कि लॉकडाउन के चलते सरकार की ओर से जारी हिदायतों के बीच सरकार जरूरी समझे जाने वाले कार्यों की अनुमति दे रही है, ताकि जनता को असुविधा न हो। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को इस बात का श्रेय देते हुए कहा कि सरकार जनता को सोशल डिस्टेंसिंग और सभी जरूरी दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करने के लिए अपील कर रही है। लोगों को सरकार की बातों पर ध्यान देकर अमल करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कोरोना अब तक लाय-इलाज बीमारी है और सावधानी ही इसका बचाव है। सभी नागरिक संयम से काम लें और आवश्यक कार्य होने पर ही अपने घर से निकलें। इस मौके पर नगर निगम के सहायक अभियंता सुनील भल्ला, कनिष्ठ अभियंता प्रदीप कुमार, मनमीत सिंह, अमित, रोजी, संजय गांधी, संजीव अत्री एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

लॉकडाउन में बिजली उपभोक्ताओं को दोहरी मार

चंडीगढ़। हरियाणा के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को कोरोना काल में दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। बिजली वितरण निगमों द्वारा बगैर रीडिंग लिए एवरेज के आधार पर भेजे गए बिलों की राशि देखकर उपभोक्ता सकते में हैं। उपभोक्ताओं ने यह मामला सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंचाया तो उन्होंने बिजली मंत्री को तुरंत कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं।

हरियाणा सरकार ने कोरोना व लॉकडाउन के चलते पिछले महीने बिजली मीटरों की रीडिंग लेने पर रोक लगाते हुए उपभोक्ताओं को एवरेज के आधार पर बिल जारी करने के लिए कहा था। इसके लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा पिछले छह माह के बिलों को आधार बनाया गया है। जानकारी के अनुसार हरियाणा के हिसार, जींद, कुरुक्षेत्र, रोहतक, पंचकूला, गुरुग्राम व रेवाड़ी सहित कई जिलों में औसत बिल इतने अधिक चले गए कि लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। कई जगहों पर बिल बहुत कम आए हैं।

30 जून तक जारी होंगे चार हजार नलकूप कनेक्शन

अब तक 12 हजार किसानों ने किया आवेदन : चौटाला

चंडीगढ़। हरियाणा में किसानों को नलकूप कनेक्शन दिए जाने को लेकर छिड़े विवाद के बीच विपक्षी दल कांग्रेस पर पलटवार करते हुए प्रदेश के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा आगामी तीस जून तक हरियाणा में किसानों को चार हजार नलकूप कनेक्शन जारी किए जाएंगे। चालू वर्ष के दौरान प्रदेश में सभी 12 हजार आवेदकों को कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे।

हरियाणा में किसानों को नलकूप कनेक्शन दिए जाने के मुद्दे पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। हुड्डा के आरोपों पर पलटवार करते हुए रणजीत चौटाला ने मंगलवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हरियाणा में अब तक कुल 12000 किसानों ने नलकूप कनेक्शन के लिए पैसे जमा कराए हैं। अब तक एक हजार किसानों को फाइव स्टार मोटर्स के कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं।

वर्तमान में अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि 30 जून तक 4000 किसानों को नलकूप कनेक्शन जारी किए जाएं। इसके लिए संबंधित जिला अधिकारियों द्वारा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि 30 जून के बाद हरियाणा में सात हजार आवेदन पैंडिंग रहेंगे। इसके फाइव स्टार मोटर खरीदने की अनुमति मिल चुकी है। संबंधित विभागीय अधिकारियों को मोटर खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। यह मोटर खरीदने के बाद इस साल 31 दिसंबर तक सभी सात हजार किसानों को नलकूप कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे।

रणजीत चौटाला ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बिजली विभाग की रिव्यू बैठक में गर्मियों के समय में बिजली की व्यवस्था पर विचार किया गया। उन्होंने कहा कि बिजली के बिलों के संबंध में जो कुछ भी त्रुटियां मिली है जिसमें घरेलू बिजली के बिलों में औसत से ज्यादा बिल मिले हैं। उसके लिए विभाग को निर्देश दिए गए हैं वे जल्द से जल्द इसका निपटान करें।

संक्षिप्त समाचार

नंदियों की सेवा में कसर न छोड़ें कर्मचारी : जैन

सोनीपत। भाजपा नेता राजीव जैन ने ठेकेदार के कर्मचारियों से आह्वान किया कि वह नंदियों की सेवा में कोई कसर न छोड़ें और उनकी देखभाल के लिए निरन्तर प्रयास करें, ताकि इन बेजुबानों को कोई परेशानी न हो। मंगलवार को हरसाना कलां स्थित नंदीशाला परिसर में नन्दियों को सूखा चारा डालने की सूचना मिलने पर पहुंचे राजीव जैन ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि नंदियों को सूखा चारे के साथ-साथ हरा चारा उपलब्ध कराने का नियम है तो कर्मचारियों को इसका पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की स्थिति में मानव के साथ-साथ बेजुबान जानवरों के सामने भी कई प्रकार की परेशानी हो रही हैं। उन्होंने कर्मचारियों से आह्वान किया कि वह इन बेजुबानों की सेवा निस्वार्थ भाव के साथ करें, ताकि उनको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

एसयूसीआई कम्युनिस्ट ने मनाया विरोध दिवस मनाया

कुरुक्षेत्र। प्रवासी मजदूरों की अनदेखी और हर रोज उन्हें मौत के मुंह में धकेलने जैसे हालात के खिलाफ अखिल भारतीय विरोध दिवस मनाया। जिला कुरुक्षेत्र में गांव सारसा की मजदूर बस्तियों में दो जगह पर मजदूरों ने विरोध दिवस मनाया। पार्टी के जिला सचिव कामरेड राजकुमार सारसा ने इस मुद्दे को लेकर पार्टी की ओर से जिला उपायुक्त के माध्यम प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी ईमेल पर भेजा। गांव सारसा में कामरेड राजकुमार के नेतृत्व में विरोध दिवस मनाया गया।

गन प्वॉइंट पर लूट करने वाला पुलिस के हत्थे चढ़ा

पलवल। कैंप थाना क्षेत्र से चालक को बंधक बनाकर गन प्वॉइंट पर कार, नकदी व मोबाइल फोन लूटने वाले दूसरे आरोपी को होड़ल की अपराध जांच शाखा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी चार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। पुलिस ने आरोपी से एक दिन की पुलिस रिमांड अवधि के दौरान एक हजार रुपये की नकदी को बरामद की और उसे मंगलवार को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सागर निवासी गांव बहीन बताया।

मेजर अभिमन्यु व उनकी आईएएस पत्नी कर रहे जन सेवा

कुरुक्षेत्र। लॉकडाउन में जरूरतमद लोगों के लिए कई लोग मदद में आगे आ रहे हैं। इस अभियान में शहर की सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के अलावा जिला के अधिकारी भी पीछे नही है। वे भी जरुरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाने में हर संभव प्रयास कर रहे है। ऐसे ही धर्मनगरी में रह रहे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय

के पूर्व रजिस्ट्रार डा. हवा सिंह के पुत्र मेजर अभिमन्यु सिंह व आईएएस पुत्रवधू इशा दुहन भी जरुरतमंद लोगों की हर संभव सहायता में जुटे है। मेजर अभिमन्यु और उनकी पत्नी इशा दुहन ने बताया कि उन्हें यह संस्कार उनके पिता से ही मिले है। इन्ही संस्कारों पर चलते हुए वे जनसेवा में लगे हैं। लॉकडाउन से जहां लोगों की आमदन का जरिया बंद होने से उन्हें रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं, ऐसे में इन दोनों अफसरों ने ड्यूटी के साथ इंसानियत का धर्म निभाना शुरू कर दिया और लोगों की मदद में हाथ बढ़ाया है।

बीपीएस मेडिकल कालेज की पांच नर्सों की रिपोर्ट पॉजिटिव

सोनीपत। उपायुक्त डा. अंशज सिंह ने कहा कि मंगलवार की देर सांयकाल बीपीएस मेडिकल कालेज खानपुर कलां की पांच नर्सों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन पांच नये केसों के आने से अब सोनीपत जिला में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों की संख्या 145 पर पहुंच गई है। उपायुक्त डा. अंशज सिंह ने यह जानकारी बीपीएस मेडिकल कालेज खानपुर से मिली रिपोर्ट के आधार पर दी। उन्होंने बताया कि इनमें दो 27 वर्षीय नर्स हैं व एक 30 वर्षीय नर्स और एक 33 वर्षीय नर्स और एक 34 वर्षीय नर्स शामिल हैं। साथ ही उपायुक्त ने कहा कि 101 पोजिटिव मरीजों ने रिकवरी भी कर ली है, जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर घर भेजा जा चुका है।

मन को दृढ़ रखने के लिए गीता जरूरी : स्वामी ज्ञानानंद

कुरुक्षेत्र। चुनौतियों का सामना करने के लिए जीवन कौशल विषय पर ऑनलाईन लैक्चर सीरीज के अन्तर्गत एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। सीरीज के अन्तर्गत माइक्रोसाफ्ट टीम के माध्यम से गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कोरोना खण्ड में भगवदगीता द्वारा तनाव मुक्त जीवन विषय पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जिस ढंग से पूरे विश्व में भय एवं तनाव का माहौल बना हुआ है, उसे देखते हुए जरूरी है कि व्यक्ति अपनी सोच सकारात्मक रखे और अपने मन को दृढ़ करे। शारीरिक इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बाजार में बहुत सी चीजे आ रही हैं, लेकिन जब तक व्यक्ति का मन मजबूत नहीं होगा, तब तक वह इस महामारी के दौर में तनाव मुक्त जीवन नहीं जी सकता। मन को दृढ़ करने का एक ही साधन है और वो है गीता। गीता ही विश्व का वो महान ग्रंथ है, जो पहले था और आज भी है। उसमें कोई भी संशोधन नहीं हुआ। गीता में ही सब समस्याओं का समाधान होने के साथ प्रश्नों के जवाब भी हैं। उन्होंने कहा कि संयोग से हम उसी भूमि पर हैं जहां पर इस महान ग्रंथ की रचना हुई थी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की कुलपति डा.नीता खन्ना ने उद्घाटन भाषण देते हुए कहा कि पूरा विश्व मानता है कि वर्तमान तनावग्रस्त जीवन में श्रीमद्भगवदगीता सभी समस्याओं का समाधान है और सभी प्रश्नों का उत्तर है। यही कारण है कि गीता का विश्व की अस्सी से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और यह विश्व के सबसे अधिक पठित ग्रंथों में से एक है तथापि हमें सरल रूप में गीता कैसे समझ में आए और व्यवहार में कैसे लाई जा सके इस दृष्टि से उसकी व्याख्या अपेक्षित है।

इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होने से बढ़ती है रोग प्रतिरोधक क्षमता

शाहाबाद मारकंडा। एसडीएम डा. किरण सिंह ने कहा कि जब व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा तो उसके अंदर रोगों से लड़ने की ताकत भी अधिक होगी। इसलिए सभी लोग आयुष पद्धति एवं होम्योपेथिक दवाई का प्रयोग करें और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ायें। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों के

अनुसार जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है उनको कोरोना वायरस जल्द अपनी गिरफ्त में ले सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर बीमारियों से बचा जा सकता है। चिकित्सकों के अनुसार होम्योपेथिक दवाई भी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने में मददगार है। शाहबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की होम्योपेथिक मेडिकल ऑफिसर डा. आशमी ने जानकारी देते हुए बताया कि एसएमओं डा. रुपिंदर सैनी के मार्ग दर्शन में होम्योपेथिक दवाई आर्सनिक एल्ब-30 रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए दी जा रही है। इसकी चार गोली व्यक्ति को प्रातः खाली पेट तीन दिन तक और बच्चों को दो गोली तीन दिन तक दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह से ही यह दवाई ले। होम्योपैथिक दवाइयां सुरक्षित और विश्वसनीय है।

दो महीने बाद-खुले दफ्तर और बाजार

दिल्ली में पटरी पर लौटने लगी जिंदगी लेकिन कोरोना के डर से अभी खुलकर जीना नहीं है आसान

संजय राय। नई दिल्ली

लॉकडाउन 4.0 में मंगलवार को छूट के दो महीने बाद दफ्तर और बाजार खुल गए। पटरी पर लौटने लगी जिंदगी लेकिन कोरोना के डर से अभी खुलकर जीना नहीं है आसान है। शर्तों के साथ चलीं डीटीसी बसें समय पर नहीं पहुंचीं।

द्वारका, पालम, उत्तम नगर, बाबरपुर समेत अन्य जगहों पर बसें बहुत कम दिखीं। जिसके चलते काम पर जाने वाले इंतजार में खड़े दिखे। लॉकडाउन में सशर्त राहत मिलने पर

● शर्तों के साथ चलीं बसें समय पर नहीं पहुंचीं, दुकानें खुलीं लेकिन ग्राहक नदारद

निमय भी टूटे। ऑटो और बाइक पर एक से ज्यादा लोग सवार दिखे। कुछ बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी सही तरीके से नहीं किया गया। यह तब था जब बसों में दो सीट के बीच में एक सीट खाली रखने का स्टीकर लगा था। करीब 54 दिन दुकानें खुलीं लेकिन ग्राहक नदारद रहे। वहीं कई इलाकों में वाहनों की लंबी कतारों लगने से सड़कें जाम हो गई थी।

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि सार्वजनिक परिवहन को बहाल करने के संबंध में विभाग सभी जरूरी सावधानी बरत रहा है और लोगों से मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने कुछ

डीटीसी बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का हुआ पालन। फोटो: रंजन डिमरी।

टर्मिनल और बस स्टैंड पर बस में चढ़ने से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग शुरू कर दी है।

सुबह बस सेवा बहाल होने के बाद से कोई बड़ी दिक्कत नहीं आई। हालांकि कुछ इलाकों में लोगों को थोड़ा लंबे वक्त तक इंतजार करना पड़ा। सूत्रों ने बताया कि ग्रामीण इलाके में कुछ क्लस्टर बसों का परिचालन नहीं हो पाया क्योंकि लॉकडाउन की अवधि का वेतन भुगतान नहीं होने के कारण चालक काम पर नहीं आए।

करीब 109 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कनॉट प्लेस 55 दिन की बंदी के बाद खुला। आने वाले दिनों में यह ऑड ईवन की तर्ज पर खुलेगा। नई दिल्ली व्यापारी संघ के अध्यक्ष अतुल भार्गव ने कहा सरकार के आदेशानुसार ऑड-ईवन के निर्देशों का पालन करते हुए दुकानें खुली लेकिन ग्राहक नदारत रहे। खान मार्केट व्यापारी संघ के अध्यक्ष संजीव मेहरा ने भी बाजार खुलने की बात कही। सरोजिनी नगर मार्केट असोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रंधावा ने बातचीत में बताया कि लॉकडाउन में ठील के बाद आज पहला दिन है। सभी नियमों का पालन करते हुए दुकान खोलने की शुरुआत की गई है। चूंकि आज पहला दिन है इसलिए वह सिर्फ दुकानों की साफ सफाई कर रहे हैं।

ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 1896 हिरासत में

लॉकडाउन के चौथे चरण में लोगों को आवाजाही की अनुमति मिलने के बाद सड़कों पर बड़ी संख्या वाहन उतर आएं। इस बीच पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 1896 लोगों को हिरासत में लिया। वहीं 76 गाड़ियों को जब्त भी किया। वहीं मास्क नहीं पहने पर 13 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मंगलवार को 351 मूवमेंट पास जारी किए गए। मालूम हो कि लॉकडाउन के बाद से ट्रैफिक पुलिस ने अपने जवानों के जरिए चालान करना बंद कर दिया था।

ट्रैफिक नियमों के अधिकांश चालान सीसीटीवी कैमरे के जरिए ही किए जा रहे थे। यह पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया था। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लॉकडाउन में 25 मार्च से लेकर 17 मई तक कुल 1,00,436 चालान नोटिस एसएमएस के माध्यम से जारी किए गए हैं। वहीं 80 नोटिस स्पीड पोस्ट स भेजे गए हैं। यह सभी नोटिस उन चालान के हैं जो कैमरे से किए गए थे।

श्रमिकों के पंजीकरण के लिए पोर्टल शुरू : मंत्री

नई दिल्ली। श्रम मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्माण कार्य में लगे विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने संबंधित विभाग को अपने यहां कम से कम कार्यकारी अभियंता स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। गोपाल राय के साथ हुई बैठक में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव, सीपीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता और तीनों नगर निगम के अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर गोपाल राय ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को बताया कि निर्माण श्रमिकों को कोरोना के दौरान होने वाले लाभों को केवल बोर्ड के माध्यम से हस्तांतरित किया जा सकता है। श्रम मंत्री ने कहा कि

निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण या नवीनीकरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू हो चुका है। दिए गए लिंक www.edistrict.delhigovt.nic.in पर 25 मई तक पंजीकरण करा सकते हैं। अप्रैल और मई महीने में लॉकडाउन के कारण हो रही कठिनाइयों को देखते हुए पहले से पंजीकृत श्रमिकों को 5-5 हजार रुपये सहायता दी थी।

दो निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस ही लेने के निर्देश

नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने यहां के दो निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस के अलावा छात्रों से किसी अन्य तरह का शुल्क नहीं लेने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि ट्यूशन फीस भी पिछले साल 31 अक्टूबर से पहले की दर के हिसाब से ली जाएगी।

न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने दक्षिणी दिल्ली के इन स्कूलों को मौजूदा दर के हिसाब से कर्मियों एवं शिक्षकों को वेतन देने का भी निर्देश दिया है। ये आदेश स्कूलों की याचिका पर आया है जिन्होंने शिक्षा निदेशालय के 22 अप्रैल के जांच परिणामों को चुनौती दी थी कि दोनों संस्थानों ने अवैध रूप से फीस बढ़ा दी है और परिजन को बकाए के साथ इसका भुगतान करने पर मजबूर किया है। साथ ही निदेशालय की उस अनुशंसा को भी चुनौती दी थी कि प्रबंधन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसके परिसर को सील किया जाए। अदालत ने याचिका पर दिल्ली सरकार, पुलिस और शिक्षा निदेशालय को नोटिस जारी कर आठ जून तक उनका जवाब मांगा है।

रियायतों के बीच कोरोना ने मारी छलांग, 500 नए केस

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

राजधानी दिल्ली में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में अब तक का सबसे बड़ा उछाल आया है। पिछले चौबीस 24 घंटों में 500 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा दस हजार के पार 10,554 पर पहुंच गए है।

इस दौरान 265 मरीज बीमारी को मात देकर अपने-अपने घरों को चले गए। साथ ही अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या 4750 हो गई है। इस वायरस के चलते 166 लोगों की मौत हुई और यहां एक्टिव मरीजों की संखया 5638 है।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में अभी 5,638 संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। विभिन्न अस्पतालों से प्राप्त केस शीट के आधार पर डेथ ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार मौत का प्राथमिक कारण कोविड-19 पाए जाने पर ही घटना की गणना इस

आंकड़े में की जा रही है। दिल्ली में अभी तक 1,45,854 टेस्ट किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार उन सभी इलाकों को हॉटस्पॉट मानकर सील किया है जहां कोरोना के 3 से अधिक मामले एक साथ पाए गए हैं।

अब कुल 70 कोरोना कंटेनमेंट जोन है। इन इलाकों को दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस की मदद से पूरी तरह सील कर दिया है। किसी भी कोरोना कंटेनमेंट जोन या हॉटस्पॉट में बाहर का कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए किया गया है ताकि कोरोना का संक्रमण इन क्षेत्रों से निकलकर अन्य इलाकों में न फैल सके।

'रोहिणी जेल में संक्रमितों को आइसोलेशन में रखा'

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनी उच्च शक्ति प्राप्त समिति को महानिदेशक (जेल) ने जानकारी दी कि रोहिणी जेल में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए 15 कैदियों और एक स्टाफ को आइसोलेशन में रखा गया है और उनका इलाज चल रहा है।

उन्होंने बताया कि इन संक्रमितों के संपर्क में आने वाले अन्य कैदियों का पता लगाने की प्रक्रिया अब भी जारी है। महानिदेशक (जेल) ने न्यायमूर्ति हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली समिति को बताया कि रोहिणी जेल समेत यहां की सभी

जेलों में संदिग्ध मामलों का पता लगाने के लिए विशेष कार्य बल (एसटीएफ) का गठन किया गया है और अगर जरूरत पड़ी तो कोरोना वायरस संक्रमित कैदियों के संपर्क में आने वाले अन्य कैदियों की कोविड-19 की जांच की जाएगी।

समिति ने सोमवार शाम को हुई बैठक की रिपोर्ट में दर्ज किया कि डीजी ने कहा कि सभी 15 कैदी के साथ ही संक्रमित पाए गए स्टाफ में संक्रमण के लक्षण नहीं थे। पिछले हफ्ते कुल 16 कैदी और जेल का एक स्टाफ कोविड-19 की जांच में संक्रमित पाया गया था। संक्रमण का पहला मामला तब सामने आया था।

जेलों को खाली करने और वहां कोविड-19 का प्रसार रोकने के मामले को देखने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेश पर गठित इस समिति ने यह फैसला किया है कि जेल में आने वाले नए कैदी को अलग वार्ड में रखा जाए ताकि वह अन्य कैदियों के संपर्क में न आए।

'कंटेनमेंट जोन से बाहर की जाएं औद्योगिक इकाइयां'

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

लॉकडाउन 4.0 में राज्य सरकार की ओर से कंटेनमेंट जोन की नई गाइडलाइन जारी की गई है। जिसमे शर्तो के साथ एक केस होने पर शहर क्षेत्र में 250 मीटर और एक से ज्यादा केस होने पर 500 मीटर का रेडियस तय किया गया है।

ऐसे में इस परिधि से बाहर औद्योगिक इकाईयों के संचालन की अनुमति दी जाए। यह बात मंगलवार को नोएडा एंट्रेन्यप्रियोर्स एसोसिएशन ने जिलाधिकारी सुहास एलवाई के समक्ष रखी। एनईए ने बताया कि एमएसएमई औद्योगिक इकाईयां बंद होने से प्रत्येक महीने सरकार को करीब 300 करोड़ रुपए का राजस्व हानि भी हो रहा है। एनईए अध्यक्ष विपिन मल्हन वर्तमान में लॉकडाउन होने के कारण एमएसएमई सेक्टर के अधिकांश उद्योग बंद है। उनमें रखा कच्चा माल खराब होने के साथ.साथ महीनों की मैंटिनेंस न होने से मशीने भी लगभग खराब होने की कगार पर है। जिसके कारण इस सेक्टर के उद्योगों को आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है।

ऐसे में राज्य सरकार की नई गाइड लाइन के अनुसार जो भी उद्योग कंटेमेन्ट जोन के बाहर उन्हें शुरू करने की अनुमति दी जाए।

● जिले में आर्थिक नुकसान को देख नई गाइडलाइन जारी

विपिन मल्हन ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र के आस.पास सेक्टर-5, 8, 9,10 व सेक्टर-11 में प्राधिकरण की अरबों रूपये की जमीन पर लोगों द्वारा झुग्गी-झोपड़ी बना कर कब्जा किया गया है।

जिसका दुस्प्रभाव औद्यौगिक इकाईयों पर पड़ रहा है। इन झुग्गियों में कोरोना संक्रमित मरीज सबसे ज्यादा निकल रहे है, घनी आबादी होने के कारण यहा कोरोना संक्रमण कम होने में समय लग सकता है। यदि औद्यौगिक क्षेत्रों को इन कंटेन्मेंट जोन से अलग नहीं किया गया तो नोएडा के काफी उद्योग चल ही नही पाएंगे।

कालिंदी कुंज पर लंबा जाम, डीएनडी पर थमे वाहन

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

लॉक डाउन-4 के दूसरे ही दिन डीएनडी पर सुबह से ही ट्रैफिक जाम लग गया। भारी संख्या में शहर की सड़कों पर वाहन उतर गए। इससे दिल्ली.नोएडा बॉर्डर पर भीषण जाम देखने को मिला।

सैकड़ों की संख्या में वाहन चालक दिल्ली-नोएडा बॉर्डर डीएनडी पर ट्रैफिक जाम में फंस गए। हालात संभालने के लिए मौके पर भारी संख्या में ट्रैफि क पुलिस को तैनात किया गया। वहीं, दूसरी तरफ कालिंदी कुंज बार्डर पर भी

हाल.बेहाल हो चुका है। ट्रैफि क पुलिस और सिविल पुलिस वाले लगातार वाहनों की जांच करके आने.जाने की अनुमति दे रहे हैं। लॉक डाउन.4 के दूसरे दिन दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली जाने वालों की भीड़ डीएनडी टोल प्लाजा पर लग गई। भारी संख्या में दोपहिया और चार पहिया वाहन चालक डीएनडी पर पहुंच गए।

लॉकडाउन के नियम तोड़ने पर वाहन जब्त

नोएडा। बादलपुर कोतवाली क्षेत्र के जीटी रोड पर लाकडाउन का उलंघन करने के मामले में पुलिस ने दस वाहन सीज किये है, जिसमें चार कार और छह बाइकें शामिल है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते सोमवार की शाम को बादलपुर कोतवाली क्षेत्र के जीटी रोड पर पुलिस वाहनो की जांच कर रही थी। जो वाहन चालक बिना किसी कार्य के लिए जीटी रोड पर बिना पास लिए आ रहे थे।

हांगकांग से आठ भारतीय पहुंचे गाजियाबाद

गाजियाबाद। देर रात हांगकांग से विशेष विमान से आठ और भारतीय गाजियाबाद पहुंचे। इन सभी को एयरपोर्ट से रोडवेज की एसी बसों से लाया गया। बाद में इन सब को गाजियाबाद के आरडीसी स्थित एक होटल में क्वॉरंटीन कर दिया है।

14 दिनों का क्वॉरंटीन समय पूरा होने के बाद ही इन सब को अपने घर जाने की इजाजत मिलेगी। वंदेमातरम स्कीम के तहत भारत सरकार विदेशों में फंसे अपने लोगों को निकालने की कोशिश में लगी है। इसी के चलते सोमवार देर रात विशेष विमान हाँगकाँग से कई भारतीयों को लेकर दिल्ली एयर पोर्ट पर उतरा।

'लैबर बैंक' से पूरी होगी श्रमिकों की कमी

● प्राधिकरण ने की पहल, रुकेगा पलायन

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

लॉकडाउन के चलते श्रमिकों का पलायन निरंतर जारी है। श्रमिकों की कमी का असर संचालित विकासीय योजनाओं पर दिखने लगा है।

इस बाबात प्राधिकरण मुख्य कार्यपालक अधिकारी के दिशा निर्देशन में नोएडा क्षेत्र में निवासित श्रमिकों का एक डाटाबेस वालंटियर्स तैयार किया जा रहा है। इसके लिए श्रमिकों को पंजीकरण कराना होगा। प्राधिकरण मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक, व्यवसायिक एवं निर्माण गतिविधियों को पालन करते हुए दोबारा शुरू करने की सशर्त अनुमति मिली है।

कार्यो को सुचारू रूप से करने के लिए बड़ी संख्या में श्रमिक व कामगार की आवश्यकता है। श्रमिकों व इकाईयों के मध्य समन्वय बनाए जाने के लिए नोएडा क्षेत्र के श्रमिकों व कामगारों का एक डाटाबेस वालंटिर्यस प्राधिकरण के कर्मचारियों के माध्यम से तैयार किया जा रहा है जो सभी औद्योगिक, व्यवसायिक एवं निर्माण संबंधित एजेंसियों को भी उपलब्ध होगा। इसके लिए गूगल पर किसी भी मोबाइल के माध्यम से लैबर बैंक में पंजीकरण करना होगा।

यहा आवेदक को नाम, आयु, अनुभव, स्किल, पता, स्थान, फ ोन नंबर, पिछले कार्य का स्थान, पहचान प्रमाण आदि भरकर अपलोड करना होगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि डाटाबेस के माध्यम से औद्योगिक, व्यवसायिक एवं निर्माण से संबंधित इकाईयां श्रमिक व कामगार परस्पर सीधे संपर्क में आ जाएंगे। साथ ही कामगारों को रोजगार भी प्राप्त होगा और श्रमिकों का पलायन कम होगा।

संक्षिप्त समाचार

कोरोना योद्धाओं की याद में कवि सम्मेलन

नई दिल्ली। हंसराज कॉलेज के हिन्दी विभाग ने कोरोना योद्धाओं के सम्मान में कॉलेज की प्राचार्या प्रो. रमा की प्रेरणा से एक ऑनलाइन युवा काव्य-गोष्ठी 'आभार' का सफल आयोजन किया। गोष्ठी का उद्घाटन वक्तव्य देते हुए प्रो. रमा ने कहा कि 'देश और दुनिया एक अदृश्य शत्रु कोरोना विषाणु से युद्धरत है। इस युद्ध में चिकित्सक, पुलिस, अन्य स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में लगे लाखों लोग कोरोना-योद्धा हैं। इस युवा काव्य-गोष्ठी में कवि के रूप में डॉ. महेंद्र प्रजापति, शैलेन्द्र 'शैल', डॉ. प्रभांशु ओझा, सुशांत शर्मा, प्रतिभा दूबे और नितेश मिश्र ने शिरकत की। गोष्ठी की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध कवि डॉ. लक्ष्मीशंकर बाजपेयी ने की। प्रभांशु ओझा की डॉक्टर्स को समर्पित कविता परनाम डॉक्टर साहब भी खूब पसंद की गई। महेन्द्र प्रजापति ने जहाँ अपनी कविताओं में चाइना की साजिश की ओर इशारा किया वहीं प्रतिभा दुबे की कविता वर्दी खूब सराही गई। बाजपेयी ने अपनी सुप्रसिद्ध कविता से दर्शकों को मंत्र-मुग्ध कर दिया। गोष्ठी में स्वागत वक्तव्य हिन्दी विभाग के प्रभारी डॉ. राजेश कुमार शर्मा ने दिया, वहीं गोष्ठी के संयोजक डॉ. मनीष ने सभी आमंत्रित कवियों एवं श्रोताओं का धन्यवाद ज्ञापन किया।

व्यापारिक प्रतिष्ठान खुलवाने पर चर्चा

पिलखुवा। पिलखुवा के व्यापारियों ने सोशल डिटेन्स का पालन करते हुए एक बैठक का आयोजन किया। बैठक का उद्देश्य नगर में लॉकडाउन के चलते व्यापारिक प्रतिष्ठान खुलने पर चर्चा करने के बाद जिलाधिकारी से फोन पर वार्ता की गई। जिलाधिकारी को व्यपारियों ने फोन द्वारा पिलखुवा के व्यपारियों की सभी समस्याओं से अवगत कराया। वस्त्र व्यापारी संघ के अध्यक्ष हरिओम सिंघल ने बताया कि लोकडाउन-4 में नियंत्रित क्षेत्र (कन्टेन्टमेंट जॉन) को छोड़कर ज्यादा से ज्यादा प्रतिष्ठान, बैंक खुलेंगे ऐसा जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है। इस दौरान नगर अध्यक्ष हरीश अग्रवाल, पूर्व नगर अध्यक्ष विपिन मित्तल, व्यापारी नेता प्रवीण मित्तल, अशोक बबली, मूलचंद गर्ग, राय साहब, अकेला आदि मौजूद रहे।

दवा व्यापारियों ने पीएम केयर फंड में दिए 18 लाख

गाजियाबाद। कैमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन उत्तर प्रदेश की जिला इकाई ने मुरादनगर विधायक अजीत पाल त्यागी के साथ डीएम अजय शंकर पाण्डेय को कोविड केयर फंड में 18 लाख से अधिक के चेक प्रदान किए। फेडरेशन के महासचिव सुरेश गुप्ता ने बताया कि दवा विक्रेता हमेशा से समय-समय पर समाज हित के कार्यो में सहयोग करते आए हैं। कोरोना महामारी से आज देश जूझ रहा है। ऐसे में फेडरेशन की हर इकाई ने अपनी क्षमता के अनुरूप अपना सहयोग प्रदान किया है। इसी के तहत डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने कोविड केयर फंड में 18 लाख, 14 हजार,400 रुपए के चेक प्रदान किए हैं। इस मौके पर कोषाध्यक्ष राजीव त्यागी आदि मौजूद रहे।

महापौर ने बांटे मास्क व सैनिटाइजर

नई दिल्ली। कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए महापौर अंजू कमलकांत और स्थायी समिति अध्यक्ष, संदीप कपूर ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को फेस मास्क और सैनिटाइजर बांटे। इस मौके महापौर ने कहा कि ईडीएमसी अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील है और संक्रमण से बचाव को लेकर कर्मचारियों के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। निगम कार्यालय में केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों और मानकों का पालन किया जा रहा है। मुख्यालय में प्रवेश से पहले सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और उनके हाथों को भी सैनिटाइज कराया जा रहा है। संदीप कपूर ने कहा सभी कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है। ताकि कोरोना से बचाव किया जा सके।

गाजियाबाद में नहीं थम रहा श्रमिकों का सैलाब

जिला प्रशासन ने लोगों को जगह-जगह पर रोका- शेल्टर होम पहुंचाया, महाराजपुर बॉर्डर सील

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

जिले से श्रमिकों के लिए बस व ट्रेन चलने के बाद से श्रमिकों के आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। श्रमिक अपने गृह राज्य जाने के लिए अब जिले का रूख कर रहे हैं।

औरेया की घटना के बाद जिले में श्रमिकों को पैदल चलने से पुलिस द्वारा रोका जा रहा है, जगह-जगह पुलिसकर्मियों ने श्रमिकों को रोक कर उनके खाने-पीने की व्यवस्था कर उन्हें शेल्टर होम भेजा जा रहा है, जहां से चिन्हित कर उन्हें ट्रेनों से उनके घरों की ओर रवाना किया जा रहा है। श्रमिक पैदल सड़क पर न चले इसके लिए डीएम अजय शंकर पाण्डेय व एसएसपी कलानिधि

गाजियाबाद में जमा हुए प्रवासी मजदूर।

नैथानी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं तो अन्य पुलिस व प्रशासन के अधिकारी खुद सड़कों पर उतर कर श्रमिकों को बसों द्वारा शेल्टर होम भेज रहे हैं।

वहीं दूसरी तरफ श्रमिकों के आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को भी करीब छह हजार से अधिक मजदूरों को ट्रेनों से रवाना किया गए। वहीं डीएम अजय शंकर पाण्डेय ने कड़े निर्देश दिए हैं कि एक भी श्रमिक सड़क पर नहीं दिखना चाहिए।

लगातार प्रवासी मजदूरों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन द्वारा महाराजपुर बॉर्डर को पुलिस ने पूरी तरह सील कर दिया। इस दौरान किसी को भी महाराजपुर बॉर्डर से आने जाने की इजाजत नहीं दी गई है।

घंटाघर रामलीला मैदान में लगाया गया ताला

गाजियाबाद। घंटाघर रामलीला मैदान से श्रमिकों को भेजे जाने की खबर के चलते पिछले चार दिन से हजारों की संख्या में मजदूरों का वहा पहुंचना शुरू हो गया था, जिसके बाद मंगलवार को प्रशासन ने उन्हें रामलीला मैदान से भेजे जाने के बजाए सीधे शेल्टर होम से भेजने का निर्णय लिया।

इसके बाद मैदान में ताला लगाकर बैनर लगा दिया गया है कि यहां कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। साथ ही तैनात पुलिसकर्मी भी अब किसी को मैदान के आसपास खड़ा नहीं होने दिया।

मास्क न लगाने पर पुलिसकर्मियों ने दिखाई बेरहमी, दो हुए निलंबित

पायनियर समाचार सेवा। हापुड़

मंगलवार को पुलिस द्वारा दी गई एक अनोखी सजा की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई।

रेलवे फाटक पर पुलिस द्वारा दो युवकों से दंडवत लगवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। घटना सोमवार सुबह 18 मई की बताई गई हैं। जिससे चारों तरफ हापुड़ पुलिस की इस करतूत से खासी किरकिरी हुई। आपको बता दे कि हापुड़ सिटी कोतवाली क्षेत्र की केशव नगर चौकी पर तैनात दो पुलिसकर्मी द्वारा चमरी रेलवे फाटक पर दो युवको को लॉकडाउन के दौरान घूमने पर व मास्क न लगाने पर डयूटी पर तैनात दो सिपाही अशोक मीणा व

सराफत अली ने उन्हें रोकक फाटक पर ही तपती धूप में दंडवत लगवाना शुरू कर दिया।

पुलिसकर्मियों द्वारा उनपर लाठी भी भांजी गई। किसी व्यक्ति द्वारा पूरी घटना मोबाइल में कैद कर ली गई और उत्पीड़न की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मामला उच्च अधिकारियों के सज्ञान में आने के बाद दोनों पुलिसकर्मी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है।

सीएमवाईके प्रिंटेक लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक चन्दन मित्रा द्वारा नं. 6, गुलाब भवन के पीछे, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष: 011-40110455 से प्रकाशित तथा बीएफएल इन्फोटेक लिमिटेड सी-9 सेक्टर-3, नोएडा-201301 (उ.प्र.) से मुद्रित। सम्पादक: चन्दन मित्रा, स्थानीय सम्पादक: उषा श्रीवास्तव।
पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं।
पत्रवार्ता ऑफिस- एफ-31, सेक्टर 6, नोएडा, गौतमबुद्धनगर-201301, उत्तर प्रदेश, दूरभाष- 120-4879800-4879900।

सरपंच पर बच्चों के नाम से फर्जी जॉबकार्ड बनाकर करोड़ों के गबन का आरोप

मोहम्मद मुस्तफा। नूंह

सरकार भले ही भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लाख दावे करती हो, लेकिन नूंह जिले में पंचायत विकास कार्यों में हो रही धांधली से नहीं लगता कि सरकार भ्रष्टाचार को रोकने में सफल हो रही है।

मामला नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका अंतर्गत मोहमदबास उर्फ बूचाका गांव का है, जहां पर सरपंच ने पंचायत विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत करके मनरेगा के विकास कार्यों में करोड़ों रुपये का घोटाला किया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव की सरपंच तसलीमा ने छोटे-छोटे बच्चों, अपने देवर जेठ, सास, ससुर, नंद, पंच व कुछ दिव्यांग व्यक्तियों के नाम से फर्जी तरीके से सैकड़ों जॉब कार्ड बनवाकर करोड़ों रुपये की राशि हड़पने का काम किया है।

खास बात ये है कि जॉब कार्ड बनाने वाले ने भी जॉब कार्ड बनाने से पहले तनक भी ध्यान नहीं दिया कि वह जॉब कार्ड बच्चों के नाम पर बना रहा है या बड़ों के नाम। शिकायतकर्ता नसीम अहमद निवासी बूचाका ने बताया कि उनकी पंचायत में करीब 700 जॉब कार्ड़ हैं, जिनमें आधे फर्जी तरीके से बने हुए हैं।

फर्जी जॉब कार्ड दिखाते बच्चे।

आरोप है कि सरपंच दो प्लानों से पूरे गांव के मजदूरों के नाम से पैसों को हड़प रहा है। सरपंच के परिवार से कई लड़कियां ऐसी हैं, जिनकी कई साल पहले शादी हो चुकी है, लेकिन उनके नाम से आज भी जॉब कार्ड बना हुआ है। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह इस मामले की शिकायत पुन्हाना एसडीएम, डीडीपीओ व जिला उपायुक्त को भी कर चुका है, लेकिन अभी तक धांधली करने वाले सरपंच के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

आरोप है कि शिकायत करने पर सरपंच उसे जानसे मारने तक की धमकी भी दे रहा है और शिकायत वापस लेने का भी दबाव बना रहा है। शिकायतकर्ता ने जिला उपायुक्त से मामले की जांच कराकर दोषी सरपंच के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है।

डिस्ट्रिक्ट राशन कूपन योजना में रहीशजादों के नाम, गरीब हुए दरकिनार

नरेश कुमार। सोहना

सोहना शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बांटें गए 1683 लगभग डिस्ट्रिक्ट राशन कूपन (कोविड-19) पर सवालियां निशान उठ रहे हैं। वार्ड पार्षदों ने भी राशन कूपनों की सूची को गलत बताते हुए सूची में अमीर घराने के लोगों का नाम होने का दावा किया है।

सरकार के आदेश पर हाल ही में खंड की सभी 38 ग्राम पंचायत और नगरपरिषद के 21 वार्डों में रहने वाले गरीब परिवारों का सर्वे किया गया था। सर्वे में ऐसे परिवारों को चुना था। जिन्हें कोविड-19 के कार्यकाल में सरकार की किसी भी योजना से लाभ नहीं मिला है। हाल ही में सोहना नगर परिषद और बीडीपीओ कार्यालय से ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत सरपंच और शहरी क्षेत्र में वार्ड पार्षदों को डिस्ट्रिक्ट राशन कूपन के तहत 1683 कूपन दिए गए है। जिमसें 1400 के लगभग शहरी क्षेत्र में तथा शेष ग्रामीण क्षेत्र में रह रहने वाले गरीब परिवारों को बांटे गए हैं।

कूपन पर लग रहे सवाल : डिस्ट्रिक्ट राशन कूपन के तहत बांटें गए कूपनों पर वार्ड पार्षद सहित स्थानीय निवासी भी सवालियां निशान लगा रहे है। वार्ड-18 के पार्षद विरेन्द्र कुमार लठ का कहना है कि उनके वार्ड में 15 कूपन आए है। जिसमें 5 से 6 ऐसे अमीर घराने के लोगों के नाम है। जिनके पास जमीन, कोठी, क्रेसर मशीन आदि है। वार्ड 11 के पार्षद असगर हुसैन ने बताया कि उसने एक सौ लोगों के नाम की सूची सर्वे के तहत प्रशासन को सौंपी थी। लेकिन उसे मात्र 6 कूपन मिले है। जिनमें उसके द्वारा दिए गए नामों में मात्र दो ही परिवार है। गांव सरमथला सरपंच सपना राघव का कहना है कि उन्हे 15 कूपन मिले है। वे ऐसे परिवारों के है। जिनका सर्वे में नाम दिया गया था।

क्या कहते हैं अधिकारी : खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर उमेद सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में दिए गए कूपनों पर किसी प्रकार का सवाल नहीं उठ रहा है। लेकिन शहरी क्षेत्र में सर्वे के तहत लिए गए नामों को नहीं चूना है। जिसको लेकर उन्होंने बीडीपीओ और एसडीएम को जानकारी देते हुए गलत नामों को कटवाने का आग्रह किया है। ताकि गरीब परिवारों का हक उन्हे मिल सके।

लॉकडाउन में प्रदेश के टैंट डीलर्स को हुआ 300 करोड़ का नुकसान

संजय कुमार मेहरा। गुरुग्राम

पूरे हरियाणा में ढाई महीने में 60 हजार शादियां हुई कैंसिल

आने वाले छह महीने में भी टैंट हाउस का काम प्रभावित रहने के आसार

टैंट डीलर्स ने प्रधानमंत्री से की राहत पैकेज की मांग

कोरोना महामारी के चलते किए गए लॉकडाउन में हरियाणा के टैंट हाउस संचालकों को 300 करोड़ का नुकसान है। क्योंकि ढाई महीने के इस लॉकडाउन में पूरे हरियाणा में टैंट हाउस की 60 हजार से अधिक शादियों की बुकिंग कैंसिल हुई हैं। अब टैंट डीलर्स की मांग है कि केंद्र सरकार टैंट हाउस संचालकों के लिए भी राहत पैकेज दे, ताकि वे अपने बिजनेस को संचालित कर सकें।

पूरे हरियाणा में 5000 से भी अधिक टैंट हाउस हैं। इन सभी के पास इस सीजन में 60 हजार शादियों की बुकिंग थी। ढाई माह के लॉकडाउन में जिस तरह से हर कोई प्रभावित हुई, उनके साथ शादियों की तैयारी करके बैठे लोग भी प्रभावित हुए। टैंट हाउस डीलर्स के पास करवाई गई बुकिंग भी कैंसिल हो गई। एक टैंट से कई लोगों का रोजगार जुड़ा है। जैसे टैंट, लाइट, फूल, कैटर्स आदि। इन सभी का रोजगार भी बंद हो गया। एक अनुमान के मुताबिक एक व्यक्ति शादी में 5 लाख रुपए गार्डन में टैंट व अन्य सुविधाओं के लिए खर्च करता है। जो कि इस बार नहीं हो पाया। इस तरह से 60 हजार टैंट हाउस संचालकों को सीधे-सीधे 300 करोड़ का नुकसान हरियाणा में हो गया। यह बहुत बड़ा नुकसान है। एक टैंट हाउस सीजन में 12 शादियों की बुकिंग कर लेता है। यह एवरेज रहती है।

लॉकडाउन के बाद शादियों का इंतजार

हरियाणा टैंट डीलर्स एसोसिएशन के महासचिव एवं ऑल इंडिया टैंट डीलर्स एसोसिएशन के सचिव दिलबाग सिंह सैनी का कहना है कि जो पीछे नुकसान हो गया, वह तो अलग है। अब भविष्य में भी करीब छह महीने तक उनके बिजनेस की ग्रॉथ होने में संशय है। क्योंकि लोग भी डरे हुए हैं। लोग सार्वजनिक रूप से शादियों के आयोजन करने में परहेज कर रहे हैं। जिन लोगों की बुकिंग कैंसिल हुई हैं, यह जरूरी नहीं कि अब वे लॉकडाउन खुलने के बाद शादियां करने के इंतजार में हैं। बहुतों ने सरकारी नियमों को मानकर कम व्यक्ति ले जाकर शादियां कर भी ली हैं और बहुत से तैयार हैं। टैंट डीलर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मांग की है कि टैंट डीलर्स के लिए भी आर्थिक पैकेज जारी किया जाए। प्रति टैंट हाउस 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए, ताकि उन्हें कुछ राहत मिले।

सीएम के नाम ज्ञापन देकर फूल किसानों ने की मुआवजे की मांग

फर्रूखनगर। इलाके के किसानों ने सोमवार को फर्रूखनगर तहसील के तहसीलदार नायब तहसीलदार रणसिंह गोदारा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में इलाके किसानों ने मुख्यमंत्री से किसानों के लिए मुआवजा के लिए मांग की है।

किसान नेता राव मानसिंह ने बताया कि सरकार की योजनाओं से प्रेरित होकर क्षेत्र के किसानों ने करीब 200 एकड भूमि पर मोतिया, चमेली, चम्पा, गुलदावरी, गुलाब, गैंदा आदि के फूलों की खेती की तरफ रुख किया। लेकिन लॉकडाउन के चलते बागवानी व फूलों की खेती वालों किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बागवानी की खेती करने वाले किसानों की हालत बद से बत्तर होती जा रही है। क्योंकि मोती की फसल पैदा करने के लिए लोग दूसरे प्रदेश से आकर यहा बटाई पर खेत लेकर उसमे मोती या अन्य फूलों की खेती करते है। लेकिन लॉकडाउन के चलते दिल्ली की आजादपुर मंडी व गाजीपुर मंडी में फूलों को लेकर जाने के लिए साधन नही होने के कारण फसल खेतों में ही खराब हो रही है। पौधों में मार्च से फूलों का उत्पादन शुरु होता है। लेकिन इस वर्ष के मार्च माह में ही कोरोना के चलते लॉक डाउन शुरु हो जाने के कारण फूलों की खेती खेतो में ही नष्ट हो रही है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि फूलों की खेती करने वाले किसानों के या तो सरकार भावांतर योजना के तहत फूलों को खरीद करके इत्र, अगरबती आदि में उपयोग के लिए खरीदे या फिर किसानों को प्रति एकड़ एक लाख रुपसे का मुआवजा दिया जाए।

गुरुग्राम के खंड फर्रूखनगर में नायब तहसीलदार को ज्ञापन देते किसान।

संक्षिप्त समाचार

इंफोर्समेंट टीम ने प्रगति विहार में सील किए अनाधिकृत निर्माण

गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम के जोन-3 क्षेत्र की इंफोर्समेंट टीम ने मंगलवार को डीएलएफफेज-4 के प्रगति विहार में अनाधिकृत रूप से निर्मित किए जा रहे दो भवनों को सील किया गया है। निगमायुक्त विनय प्रताप सिंह के निर्देश पर जोन-3 क्षेत्र के सयुंक्त आयुक्त हरिओम अत्री के नेतृत्व में इंफोर्समेंट टीम ने प्रगति विहार में पहुंचकर सीलिंग की करवाई पूरी की। टीम में सहायक अभियंता कुलदीप सिंह, कनिष्ठ अभियंता सन्दीप हुड्डा, सचिन कुमार, महबूब एवं हरिओम उपस्थित थे। बता दें कि नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में स्थित किसी भी प्रकार के निर्माण से पूर्व स्वीकृति लेनी आवश्यक है। बिना स्वीकृति के किए जाने वाले निर्माणों पर कार्रवाई के लिए निगमायुक्त द्वारा जोन वाइज अलग-अलग टीमों का गठन किया हुआ है। ये टीमें अपने-अपने क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माणों पर नजर रख रही हैं।

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों की जांच कर बांटी दवाइयां

नूंह। सरकार के आदेशानुसार मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पाठखोरी (चैनपुरी) गांव में लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें मुफत में दवाईयां उपलब्ध करवाई। इस कार्यक्रम में ग्रामीणों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया और थर्मल स्क्रेनिंग से अपने स्वास्थ्य की जांच करा दवाईयां ली। विभाग की टीम ने घर-घर जाकर लोगों की जांच कर हर बीमारी की इवाईयां बांटी। डाक्टर सवाती ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के आदेशानुसार पूरे जिले में लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 11 टीमें काम कर रही हैं, प्रत्येक टीम को एक रोडवेज बस दी हुई है। जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर पहले तो लोगों के स्वास्थ्य की जांच करती है और फिर उसे हर बीमारी की दवा भी जाती हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया, क्योंकि लॉकडाउन के चलते लोग अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लॉकडाउन में लोग घरों से बाहर ना निकलें, इसलिए स्वास्थ्य विभाग की टीम हर गांव में जाकर लोगों को मुफत में दवाईयां उपलब्ध करवा रही हैं। पाठखोरी गांव में लोगों को दवाईयां बांटते समय चंद्र शेखर सरपंच, शुष्मा, डाक्टर सवाती, आशा वर्कर पूनम, सरोज हेल्पर, साजिद हुसैन समाजसेवी सहित काफी लोग मौजूद रहे।

मंगलवार को कोरोना के 9 केस आए, कुल हुए 220

गुरुग्राम। जिला में मंगलवार को कोरोना के 9 नए केस आए। इसके साथ ही अब कुल केस 220 हो गए हैं। मंगलवार को चार लोग यहां से ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो गए। मंगलवार को आए 9 केसों में 2 केस रवि नगर से, 2 केस सेक्टर-10ए से, 1 केस सेक्टर-10 से, 1 केस पालम विहार से, 1 केस सरहोल से, 1 केस दौलताबाद से और 1 केस शिवाजी नगर से है।

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने को आयुर्वेदिक दवाओं का वितरण

गुरुग्राम। आयुष विभाग द्वारा जिला में बड़े स्तर पर लोगों के बीच आयुर्वेदिक दवाएं जैसे गिलोय घनवटी, संशमनी, वटी अणु तेल जैसी दवाओं को लोगों के बीच निशुल्क वितरित किया जा रहा है। अब तक जिला में 31 हजार लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक दवाओं का वितरण किया जा चुका है। यह जानकारी जिला आयुर्वेद अधिकारी डा. मंजू बांगड़ ने दी।

जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉ. मंजू बांगड़ के मुताबिक गुरुग्राम के शिवाजी पार्क, खांडसा मंडी में रह रहे लगभग 2 हजार लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें जैसे गुडूची घनवटी, गिलोय घनवटी, संशमनी वटी, अणु तेल आदि आयुर्वेदिक दवाएं वितरित की गई। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद का प्रयोजन ही व्यक्ति को स्वस्थ रखते हुए उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है। आयुष विभाग द्वारा प्रतिदिन बड़े स्तर पर लोगों को रोग प्रतिरोधक दवाई दी जा रही है, ताकि वे कोरोना संक्रमण से बचे रहे।

आयुर्वेदिक दवाओं का वितरण करते आयुर्वेद विभाग के कर्मचारी।

मजदूरों व दिहाड़ीदारों के सामने संकट

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

कोरोना की महामारी के मद्देनजर जो लॉकडाउन घोषित किया है, उससे उपजे हालात में गरीब जनता, खासकर मजदूरों, दिहाड़ीदारों के सामने भयंकर विकट समस्या पैदा हो गई हैं। अनेक बेघर हैं।

एआईटीयूसी की हरियाणा प्रदेश कमेटी के सचिव व श्रमिक नेता हरिप्रकाश ने कहा कि रोज कमाकर खाने वाले दिहाड़ीदार, ठेका श्रमिक, रिक्शा व ऑटो चालक, पल्लेदार, खेत मजदूर, मनरेगा व भवन निर्माण श्रमिक, मंडी-सड़क-पटड़ी, रेहड़ी-खोमचा व दुकानों पर काम करने वालों और घूम-घूम कर सामान बेचने वाले वैन्डरों को सबसे ज्यादा मुसीबत झेलनी पड़ रही है। अब सरकार ने राहत के लिए जो घोषणा की है वह अपर्याप्त है। परन्तु इससे भी जरूरी यह है कि यह पूरी राशि वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंचे। सरकार व जिला प्रशासन को इसके पुख्ता इंतजाम करने व पारदर्शिता के लिये आवश्यक कदम उठाने चाहिएं। सरकार ने फैक्ट्री मजदूरों, घरों में काम करने वाली महिलाओं व मालिकों के लिए घर से माल तैयार करने वालों व कैजुअल श्रमिकों बारे उनके मालिकों से लाकडाउन के दौरान उनकी तनखा में कटौती ना करने, उन्हें वेतन का पूरा भुगतान करने और उन्हें बर्खास्त न करने की जो एडवाइजरी जारी की है वह भी अपर्याप्त है।

गुरुग्राम में मजदूरों, दिहाड़ीदारों को सहायता की मांग को लेकर प्रदर्शन करते एआईटीयूसी के कार्यकर्ता।

दोस्त ने किया 11वीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म

गुरुग्राम। एक निजी स्कूल की 11वीं कक्षा की छात्रा से उसके दोस्त ने दुष्कर्म किया। वह उसे बहला-फुसलाकर ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। छात्रा कि मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मंगलवार को आरोपी को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है। किशोरी कि मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 2 साल पहले आरोपी और उनकी 16 वर्षीय बेटी एक ही स्कूल में पढ़ते थे। इस दौरान आरोपी ने उनकी बेटी से दोस्ती हो गई। कुछ समय बाद छात्र ने स्कूल बदल लिया था। इसके बावजूद दोनों सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत करते रहते थे। लॉकडाउन में छात्रा घर पर ही थी।

पहली बस से 28 यात्री पंचकूला भेजे

मंगलवार को पूरे नियमों के साथ बस को बस स्टैंड से किया गया रवाना

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

लॉकडाउन लागू होने के बाद गुरुग्राम से मंगलवार को हरियाणा राज्य परिवहन की पहली बस पंचकूला के लिए रवाना हुई। यह बस सुबह 8 बजे गुरुग्राम के बस-स्टैंड से 28 यात्रियों को लेकर गई है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया।

परिवहन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर 29 व्यक्तियों ने गुरुग्राम से पंचकूला जाने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। उनमें से मंगलवार की सुबह 28 व्यक्ति पंचकूला जाने के लिए बस स्टैंड पहुंचे। एक व्यक्ति किसी कारणवश नहीं पहुंच पाया। हरियाणा सरकार के परिवहन विभाग द्वारा लॉकडाउन के कारण फंसे लोगों को राहत देने के लिए 18 मई से राज्य परिवहन की बसें चलाने का निर्णय लिया है। इन बसों में यात्रा करने के लिए केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही बुकिंग की जा सकेगी।

हरियाणा राज्य परिवहन गुरुग्राम डिपो की महाप्रबंधक अन्नू श्योकंद के मुताबिक केवल कंफर्म बुकिंग वाले यात्रियों को ही बस अड्डों में प्रवेश की अनुमति होगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखते हुए प्रत्येक बस में अधिकतम 30 यात्रियों को ही बिठाया जाएगा। अगर किसी कारणवश किसी मार्ग पर बस परिचालन संभव नहीं होगा तो प्रस्थान के समय से दो घंटे पहले सूचना के साथ बस परिचालन रद्द कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में यात्री द्वारा दिया गया किराया उसे वापस कर दिया जाएगा।

गुरुग्राम के बस स्टैंड पर बस में सवार होने से पहले स्क्रीनिंग करवाते यात्री।

बाजारों में उमड़ी भीड़ सामाजिक दूरी की उड़ीं धज्जियां

सोहना। लॉकडाउन चार में मामूली छूट क्या मिली कि लोग सामाजिक दूरी के नियम को तार-तार करने लगे हैं। बाजार की सड़कों पर खरीदारी करने वालों की भीड़ हो रही है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन को लेकर जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश सरकार ने भी कुछ हद तक छूट देने का फैसला लिया है। लेकिन लोगों को सामाजिक दूरी बनाने और मुंह पर मास्क लगाना अति आवश्यक किया है। मंगलवार को स्थानीय बाजारों में दुकानों दुकानों पर लोगों की भीड़ देखी गई। फल व सब्जियों की रेहड़ी-ठेलों पर लोगों की भीड़ रही। बिरयानी, गन्ना जूस और रसोई में उपयोग होने वाले मशालों की रेहड़ियों पर भी खरीदने वालों की जमकर भीड़ रही।

कोरोना वॉरियर्स का पुष्प वर्षा से किया सम्मान

गुरुग्राम। एसजीटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल और रिसर्च इंस्टीट्यूट में मंगलवार को कोरोना वॉरियर्स का फूल-मालाओं से स्वागत किया गया। इन कोरोना वॉरियर्स में डॉक्टर, नर्स, हाउस कीपिंग, वार्ड ब्वॉयज तथा आया शामिल थे। एसजीटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल और एसजीटी यूनिवर्सिटी के स्टाफ उपस्थित थे।

ये वे वॉरियर्स थे, जिन्होंने एसजीटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोरोना संक्रमितों के वार्ड में ड्यूटी की थी। कोरोना वॉरियर्स ने दो भागों में एसजीटी अस्पताल के कोरोना संक्रमितों के वार्ड में ड्यूटी की थी। अपनी ड्यूटी के दौरान इन्होंने भारत सरकार और हरियाणा सरकार की गाइडलाइंस को पूरी तरह से पालन किया। पहले भाग में 12 कोरोना वॉरियर्स ने निर्धारित सुरक्षात्मक सूट पहनकर सात दिनों तक 24 घंटे ड्यूटी की। 14 दिन के लिए क्वारेंटाइन किया। उसके बाद 12 कोरोना वॉरियर्स की ड्यूटी फिर से वार्ड में लगी। एसजीटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डा. एसपीएस कोचर के मुताबिक सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार इन्हें भी 7 दिन की ड्यूटी के बाद 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया।

50 दिन तक 50 हजार वंचितों को वितरित किया भोजन

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

गुरुग्राम। समाजसेवी संस्था श्रीश्याम नटखट परिवार द्वारा लॉकडाउन के बीच लगातार 50 दिन तक 50 हजार वंचितों को भोजन वितरित किया। यहां अशोक विहार फेस 3 में श्री श्याम नटखट परिवार के सदस्यों ने पूरी श्रद्धा के साथ यहां मिलकर भोजन वितरण का कार्य किया।

संस्था के अध्यक्ष सुनील भारद्वाज ने बताया कि सबने ने मिलकर जो संकल्प लिया था कि कोरोना नामक इस वैश्विक महामारी से जूझ रहे हमारे साथी उनके लिए भोजन की सेवा करेंगे। 50 दिनों तक लगातार प्रतिदिन 900 से 1000 लोगों को भोजन कराना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अशोक विहार फेस 3 की श्याम वाटिका में यह पूरा सेवा कार्य किया गया। सुनील भारद्वाज शैलेन्द्र यादव, राकेश गुप्ता, दिनेश चंदर, संजय बॉबी), चंद्रशेखर, वजय शर्मा, सतपाल रावत, जगबीर देशवाल, महेश शर्मा, अर्जुन सिंह, रजनीश आनंद, धर्मवीर सिंह, रवि जांगरा, कर्मवीर सिंह, राजू सैनी, टोनी के मुताबिक 50 दिन से यह पुण्य कार्य कर रहे हैं, जिसमें हमें असीम सुख मिला है। अब फिर उन्होंने ऐसी विपदा की घड़ी में श्री श्याम नटखट परिवार ने लगातार निर्धन एवं असहाय व्यक्तियों की सेवा की है। बहुत ही सुंदर तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करते हुए भोजन वितरित किया है। जिला खेल अधिकारी राज यादव और अर्जुन अवार्डी प्रशांता करमाकर ने भी यहां पहुंचकर कार्य की सराहना की।

गुरुग्राम के अशोक विहार फेज-3 में अंतिम दिन भोजन वितरित करते श्रीश्याम नटखट परिवार के सदस्य।

कालका जी मंदिर में भंडारे में प्रसाद वितरित करते समाजसेवी देवेंद्र गोयल।

मां कालका मंदिर में समाजसेवी देवेंद्र गोयल ने किया भंडारा : कालका जी मंदिर नेहरू प्लेस में गुरुग्राम के समाजसेवी देवेंद्र गोयल व मधु गोयल ने भंडारा आयोजित किया। इस दौरान सेंकड़ों की संख्या में लोगों को भोजन कराया। मां कालका के भक्त देवेंद्र गोयल की तरफ से लॉकडाउन में करीब 40 दिन तक गुरुग्राम में मां कालका रसोई से भोजन आवंटित किया गया। गुरुग्राम में मां कालका रसोई 27 मार्च 2020 से ही उन्होंने यहां पर शुरू कर दी थी। 3 मई को समापन किया गया। अब मां कालका के मंदिर में जाकर देवेंद्र गोयल एवं मधु गोयल ने भंडारा किया। इस दौरान मौजूद लोगों को प्रसाद आवंटित किया गया।

नर्सों का योगदान अतुलनीय : मधुमिता ढल

आरजीसीआईआरसी ने अंतरराष्ट्रीय नर्स सप्ताह मनाया

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

हमारे देश को स्वस्थ रखने में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो पूरी लगन और प्रतिबद्धता के साथ लोगों की सेवा करती हैं। कैंसर के उपचार में, नर्सों की भूमिका कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कीमोथेरेपी जैसी प्रक्रियाओं को उचित देखभाल की आवश्यकता होती है।

नर्स समुदाय के योगदान को ध्यान में रखते हुए राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एवं रिसर्च सेंटर (आरजीसीआईआरसी) ने 'अंतरराष्ट्रीय नर्स वीक' का आयोजन किया। सप्ताह भर चले कार्यक्रम में नर्सों के काम और योगदान को विभिन्न गतिविधियों वेबिनार, विचार-विमर्श, वार्ता, प्रस्तुतिकरण, प्रश्नोत्तरी आदि के माध्यम से मनाया गया, जिसमें पूरी नर्सिंग टीम की सक्रिय भागीदारी देखी गई। कार्यक्रम के दौरान कैंसर रोगियों बनाम कोविड-19 पर एक पैनल डिस्कशन और नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ पर एक चर्चा सत्र विशिष्ट आकर्षण था। नर्स वीक के दौरान अस्पताल की सभी नर्सों ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल शपथ भी ली। इस वर्ष सरकार द्वारा जारी कोविड-19 दिशा-निर्देशों के चलते नर्स सप्ताह का आयोजन ऑनलाइन किया था। सत्रों के दौरान नर्सों को अधिक सार्थक जीवन जीने के लिए विभिन्न चुनौतियों और समाधानों पर भी चर्चा हुई। डीएस नेगी (सीईओ, आरजीसीआईआरसी) ने कहा, स्वास्थ्य सेवा की दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक, नर्सों के बिना कोई व्यक्ति उपचार के सहज निष्पादन के बारे में नहीं सोच सकता है। नर्सों के योगदान का जश्न मनाने के लिए इस तरह की गतिविधि का हिस्सा होना अच्छा अनुभव है।

पायनियर
नई दिल्ली, बुधवार, 20 मई, 2020

कोविड-19: दो कैदी और पत्रकार समेत सात पॉजिटिव, आंकड़ा 163

जेल में दो बंदियों के पॉजिटिव आने से मचा हडकंप, 14 की करवाई जांच

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

जिले में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को चौकाने वाले आंकड़े सामने आए। जिला जेल में बंद दो कैदियों के पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। उनके साथ के कैदियों के सैम्पल लेकर उन सभी को अलग-अलग बैराकों में क्वारेंटाइन किया गया। इसके अलावा जिले में एक पत्रकार भी पॉजिटिव पाया गया है। उसे होम क्वारेंटाइन किया गया। इसके साथ मंगलवार को सात पॉजिटिव होने की घोषणा जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई।

मच गया हड़कंप : जेल सुपरीटेंड संजीव कुमार ने बताया कि जिला जेल में गत 15 और 16 मई को दो कैदियों को कई आपराधिक मामलों में लिप्त होने पर जेल भेजा गया था। उनकी मेडिकल रिपोर्ट के साथ-साथ कोविड-19 की जांच कराई थी। 22 और 49 वर्षीय दोनों कैदियों को दो बैराकों में बंद किया गया था। जिसमें एक कैदी के सम्पर्क में आठ और दूसरे के सम्पर्क में छह लोग आए थे। रिपोर्ट पॉजिटिव आने से कैदियों में हडकंप मच गया। जिस पर दोनों बैराकों को खाली करवा कर उन्हें सैनिटाइज करवाया गया और दोनो कैदियों को अस्पताल में दाखिल करवा कर बाकि 14 कैदियों के सैम्पल जांच के लिए भेज दिए गए। वहीं सभी 14 कैदियों को 14 दिनों के लिए विभिन्न बैराकों में क्वारेंटाइन कर दिया गया है।

पत्रकार समेत अन्य : पिछले दिनों दिल्ली के एक न्यूज चैनल में 28 पत्रकार पॉजिटिव पाए गए थे। जिस पर फरीदाबाद की पल्ला स्थित जमराम सरपंच कालोनी में रहकर नोएडा में नौकरी कर रहे एक 25 वर्षीय पत्रकार ने भी अपनी जांच कराई तो वह पॉजिटिव पाया गया। जिस पर विभाग ने उसे होम आईसोलेट कर दिया है। इसके अलावा एनएच-पांच निवासी एक 62 वर्षीय व्यक्ति सेक्टर 20 के एक निजी अस्पताल में भर्ती हुआ था। उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। वहीं सेक्टर 16 के एक निजी अस्पताल का 21 वर्षीय स्वास्थ्य कर्मी भी पॉजिटिव पाया गया है। वह अस्पताल में भर्ती एक पॉजिटिव के संपर्क में आने से संक्रमित हुआ है। डीग गांव का 18 वर्षीय युवक संक्रमित भी है। वह प्याला स्थित फैक्ट्री में एक संक्रमित के संपर्क में आया था। डबुआ कालोनी निवासी 60 वर्षीय एक महिला भी पॉजिटिव पाई गई है। इन सभी को ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में दाखिल किया गया है।

यह है आंकड़े

कोरोना के नोडल अधिकारी डा. रामभगत ने बताया कि जिले में अब तक 8066 यात्रियों को सर्विलांस पर लिया जा चुका है, जिनमें से 2032 लोगों का निगरानी में रखने का 28 दिन का पीरियड पूरा हो चुका है। शेष 6028 लोग अंडर सर्विलांस हैं। कुल सर्विलांस में रखे गए लोगों में से 7903 होम आइसोलेशन पर हैं। अब तक 7678 लोगों के सैंपल लैब में भेजे गए थे, जिनमें से 6801 की नेगेटिव रिपोर्ट मिली है तथा 714 की रिपोर्ट आनी शेष है। अब तक 163 लोगों के सैंपल पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें से 65 लोगों को अस्पताल में दाखिल किया गया है तथा छह पॉजिटिव मरीजों को घर पर आइसोलेट किया गया है। इसी प्रकार ठीक होने के बाद 86 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब तक छह मरीजों की मौत हो चुकी है।

विदेश से लौटे नागरिकों की हुई कोरोना जांच

कविता। फरीदाबाद

पॉजिटिव मरीज बढ़ने के साथ ही जिला स्वास्थ्य विभाग सर्तक हो गया है। विभाग द्वारा विदेश से लौटे नागरिकों की कोविड-19 की जांच गहनता के साथ की जा रही है। जिसके तहत मंगलवार को 44 विदेश से लौटे भारतीय नागरिकों के सैम्पल लिये गए। इन्हें विभिन्न देशों से लाकर फरीदाबाद में 14 दिनों के लिए क्वारेंटाइन किया गया है। विदेश से लौट रहे इन लोगों की कोविड-19 की जांच का नोडल अधिकारी कोविड हेल्पलाइन के ऋषिराज गौतम को बनाया गया। मंगलवार को उन्होंने सभी के सैम्पल लेकर उन्हें क्वारेंटाइन कर दिया गया।

इन देशों के नागरिक : ऋषिराज गौतम ने बताया कि गत 13 मई को 44 नागरिक फिलीपींस, यूएसए तथा यूके से आए है। जिनमें 40 फिलीपींस नागरिकों को नेशनल हाइवे पर स्थित एक निजी होटल में ठहराया गया है। वहीं चार अन्य नागरिकों को एक अन्य निजी होटल में ठहराया गया है। जिसमें एक यूएसए से और बाकि तीन यूके से आए है। इन सभी के सैम्पल लेकर मंगलवार को जांच के लिए भेजे हैं।

विदेश से लौटे नागरिकों को जांच के लिए बीके ले जाते ऋषिराज गौतम।

गर्भवती भी शामिल : ऋषिराज गौतम ने बताया कि फिलीपींस से आए यात्रियों में एक परिवार भी शामिल है। जिसमें दम्पति के अलावा एक चार वर्षीय बच्ची भी है। उन्होंने बताया कि महिला आठ माह की गर्भवती है। यह सभी सेक्टर-दो के निवासी है। इसके अलावा जिले के नौ लोग है। जिसमें ग्रीन फिल्ड कालोनी, सेक्टर-56 ए स्थित राजीव कालोनी, सीही गांव, डबुआ कालोनी, सेक्टर-22 और सेक्टर-नौ के यात्री शामिल है।

ज्यादातर विद्यार्थी

गौतम की माने तो विदेश से लौटो लोगों में ज्यादातर विद्यार्थी शामिल है। जो विभिन्न देशों में एमबीबीएस, एमडी, होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे है। उन्होंने बताया कि 40 में प्रदेश के कुछ हिस्सों के लोग भी शामिल है। जिसमें पानीपत, जींद से चार, हिसार से तीने, झज्जर, हसनपुर तावडू, नारनौल, महेन्द्रगढ़ से तीन, रोहतक से चार, भिवानी, नूहं, फतेहाबाद, कुरूक्षेत्र से तीन, चरखी दादरी, अम्बाला, कैथल से तीन, करनाल, पलवल से तीन लोगों के अलावा यमुनानगर से एक व्यक्ति शामिल है।

एनएसयूआई ने सीएम को पत्र लिख दी चेतावनी

युवाओं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे सरकार

फरीदाबाद। प्रदेश की भाजपा-जजपा सरकार द्वारा आए दिन कोई न कोई युवा विरोधी नीति को लागू कर लाखो छात्रों-युवाओ के भविष्य से खिलवाड़ किया जाता है। यह कहना एनएसयूआई के जिला उपाध्यक्ष विकास फागना का। उन्होंने प्रदेश की मनोहर-दुष्यंत सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाला जा रहा है व उनकी कई सालों की मेहनत पर पानी फेरा जा रहा है।

विकास फागना का कहना है कि दिन रात मेहनत कर, दूसरे प्रदेशों में जा कई सालों से कोचिंग लेकर तैयारी कर रहे गरीब परिवारों के बच्चों की भावनाओ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सैकड़ों किलोमीटर दूर बसों में लटक कर गए व साढ़े 5 सालों से नियुक्तियों व रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे युवाओं के लिए यह फैसला किसी भद्दे मजाक से कम नहीं होगा। फागना का कहना है कि प्रदेश सरकार नौकरियों के नतीजे लटकाने-ज्वाईनिंग न देने में असक्षमता का परिचय दे रही है जोकि बेहद निंदनीय है।

संक्षिप्त समाचार

बुजुर्ग को दिलवाया परिवार

फरीदाबाद। मानव एकता जनहित संस्था ने नवजन मोर्चा समिति ताऊ देवीलाल वृद्धाश्रम में रह रही एक वृद्धा को उसके परिवार से समझौता कराने की एक अच्छी पहल की शुरूआत की। वृद्धा कांता पिछले कई दिनों से आश्रम में रह रही थी और उसके दो बेटे एनआईटी में ही रहते है। मानव एकता जनहित संस्था की पदाधिकारी तरसेम शर्मा ने आश्रम के संचालक किशन लाल बजाज को विश्वास दिलाया कि वो कांता और उसके परिवार में सुलह कराने के लिए ही ले जा रही है। जिससे कि इनका आपसी मन मुटाव खत्म हो और इनके परिवार पर बुजुर्गो का आर्शीवाद हमेशा बना रहे, यहीं मेरी भगवान से प्रार्थना है। संस्था की इस पहला पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए किशन लाल बजाज ने कहा कि यदि सभी इसी तरह से बुजुर्गो के बारे में सोचेगें तो वह दिन दूर नहीं जब बुजुर्गो को दर दर भटकना नहीं पड़ेगा और वृद्वाश्रमों में मुसाफिर बनकर नहीं रहना पड़ेगा।

आज से बल्लभगढ़ बंद, डबुआ व सेक्टर 16 मंडी खुलेगी

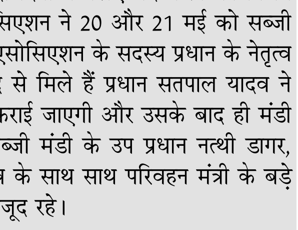

फरीदाबाद। सब्जी मंडियों से आढ़ती, पल्लेदारों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाये जाने पर जहां डबुआ और सेक्टर-16 की सब्जी मंडियों ने 16 से 19 मई तक बंद कर दिया गया था। वहीं सभी की स्क्रीनिंग और मंडी को सैनिटाइज किया गया। अब दो ही मंडियों को बुधवार को खोल दिया जाएगा। लेकिन बल्लभगढ़ मंडी को एतिहात बरतते हुए जिला प्रशासन की तरफ से बल्लभगढ़ के एसएमओं डॉ. मान सिंह के किए गए अनुरोध पर दो दिनों के लिए बंद करने का निर्णय लिया है। सब्जी मंडी बल्लभगढ़ एसोसिएशन ने 20 और 21 मई को सब्जी मंडी बंद करने का फैसला लिया है। एसोसिएशन के सदस्य प्रधान के नेतृत्व में बल्लभगढ़ के एसडीएम त्रिलोकचंद से मिले हैं प्रधान सतपाल यादव ने बताया है कि मंडी की साफ सफाई कराई जाएगी और उसके बाद ही मंडी में काम शुरू होगा। इस मौके पर सब्जी मंडी के उप प्रधान नत्थी डागर, कुलविंद्र, कृष्ण मुरारी, तेजपाल यादव के साथ साथ परिवहन मंत्री के बड़े भाई टिपरचंद शर्मा, पारश जैन भी मौजूद रहे।

यमुना में डूबकर किशोर की मौत

फरीदाबाद। यमुना नदी में गांव छांयसा के निकट नहाने गया 16 साल का एक किशोर की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए बीके अस्पताल भेज दिया है। थाना छांयसा पुलिस के मुताबिक छांयसा गांव निवासी कृष्ण का 16 साल का बेटा प्रेम सोमवार शाम को अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ यमुना नदी में नहाने चला गया। यमुना नदी गांव के पास से ही गुजर रही है। नहाते समय प्रेम अचानक गहरे पानी में चला गया। जिस वजह से वह पानी में डूब गया। प्रेम के पानी में डूबने पर उसके साथियों ने शोर मचा दिया। शोर सुनकर गांव के लोग आ गए। जिन्होंने फायर बिग्रेड व पुलिस को सूचना दी। मंगलवार सुबह प्रेम का शव छांयसा से करीब 2 किलोमीटर दूर यमुना किनारे पर मिल गया। शव पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है।

इंदु व भारती बांट रही जरूरतमंदो को भोजन

फरीदाबाद । देश के विकास में बेटियों का महत्वपूर्ण योगदान है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी काबलियत सिद्व कर चुकी है। देश पर जब जब विपदा आई है महिलाएं भी घरों से बाहर निकलकर मैदान में डटी रही है। आज जब पूरे देश पर कोरोना महामारी का प्रकोप है ऐसे में बाल्मीकि समाज की दो बेटियां इन्दु व भारती भी देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हुए घर बैठने की बजाय गरीबों को भोजन बांटने में लगी हुई है। इन्दु और भारती दोनो सगी बहनें है। जिसमें इन्दु आईएएस की तैयारी कर रही है और भारती एमबीए करके पीएचडी की तैयारी कर रही है। दोनो बेटियां सुबह होते ही बाल्मीकि आश्रम धर्माथ सुधार ट्रस्ट गांधी कालोनी, वाल्मिकी मोहल्ला एनआईटी फरीदाबाद द्वारा संचालित भगवान वाल्मिकी मंदिर के प्रांगण में अपनी अन्य महिला सदस्यों के साथ भोजन तैयार करने में जुट जाती है। भोजन बनने के बाद दोनो बहने पूरे सोशल डिस्टेंस से लोगों की लाईन लगवाकर भोजन बांटती है।

नहर पार के अधिग्रहण जमीन का मामला निपटाये सरकार : वशिष्ठ

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

मास्टर रोड की कई साइटों पर लॉकडाउन के चलते रूका हुआ साइटों पर निर्माण कार्य फिर शुरू कर दिया गया है। सरकारी विभाग की तरफ़ से अपने प्राजेक्ट पर अब निर्माण कार्यों को रफ़्तार दी जा रही है।

ग्रेटर फ़रीदाबाद में मास्टर रोड की कई साइटों पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है इसी तर्ज़ पर किसान संघर्ष समिति ग्रेटर फ़रीदाबाद के अध्यक्ष शिवदत्त वशिष्ठ एडवोकेट ने सरकार से मांग की है कि लॉकडाउन की वजह से किसानों के परिजनों की हालत बहुत ख़राब हो गई है ज़मीन अधिग्रहण होने की वजह से किसान अपनी ज़मीन पर खेती करके अपनी आय विकसित नहीं कर पाए। इसलिए इस लॉकडाउन में किसानों के पास जो जमा पूंजी थी वो भी खर्च हो गई व परेशानी बढ़ गई है। वशिष्ठ ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद नहर पार के अधिग्रहण ज़मीन का मामले निपटाऐ जाए। लॉकडाउन के चलते हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने अपने प्राजेक्ट पर निर्माण कार्य बंद किया हुआ था अब लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद सरकार की शर्तों के अनुसार विकास का फिर शुरू कर दिए हैं। सेक्टर 88-89 की डिवाइडिंग रोड पर काम शुरू कर दिया है। वहीं टूटी हुई की सड़कों की मरम्मत करने के साथ अब सेक्टर 72 और 73 के निर्माण कार्य शुरू कर दिए हैं। कुछ किसानों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि नहर पार

गोली मारने वालों की पहचान हुई

फरीदाबाद। तिगांव गांव में सोमवार को एक युवक को गोली मारने वाले आरोपियों की पहचान हो गई है। घायल के बयान पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

थाना तिगांव मे दर्ज मामले के मुताबिक तिगांव के बड़ा मोहल्ले में रहने वाले धर्मेंद्र उर्फ कालू ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह गांव में ही कूलर सप्लाई का काम करता है। पिछले दिनों उसकी दोस्ती तिगांव में रहने वाले लोकेंद्र से थी। लेकिन किसी कारण उनकी दोस्ती टूट गई। इस रंजिश को रखते हुए लोकेन्द्र अपने दोस्त गौरव के साथ उसे मारने के लिए उसके घर पर आया था। बाइक पर आए दोनों युवकों ने चेहरे पर नकाब बांधा हुआ था। लोकेंद्र व उसके दोस्त गौरव ने उसके पैरों में गोली मारी दी। गोली लगने से घायल युवक को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। थाना प्रभारी जसवीर सिंह ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है।

हुडा कर्मियों ने किया गेहूं का एडवांस देने की मांग को लेकर प्रदर्शन

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

सेक्टर-12 के ओपन एयर थिएटर में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन रजिस्ट्रेशन नंबर 1266 ने मंगलवार को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को गेहूं का एडवांस देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इसकी अध्यक्षता यूनियन के सर्कल सेक्रेटरी धर्मवीर वैष्णव ने की। इस मौके पर सीटू के ज़िला उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह डंगवाल विशेष रूप से उपस्थित थे।

उन्होंने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए बताया कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। लेकिन सरकार कर्मचारियों को समय पर अनाज खरीदने के लिए ब्याज रहित ऋण नहीं दे रही है। जिसकी वजह से कर्मचारियों को काफी आर्थिक परेशानी हो रही है। क्योंकि यदि सरकार ने समय पर लोन मंजूरी के आदेश नहीं दिए तो मण्डी में गेहूं मिलना काफी कठिन हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने पहले ही महंगाई भत्ते की किस्त पर रोक लगा दी। इसके बाद नई भर्ती बंद कर दी। एलटीसी और अन्य सुविधाओं को बंद किया जा रहा है इसलिए सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ कर्मचारियों में काफी नाराजगी व्याप्त है सरकार की मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ सीटू के आह्वान पर कोरोना वायरस की महामारी के चलते मजदूरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धर्मवीर वैष्णो ने बताया कि मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल ही अपने घरों को जा रहे हैं रास्ते में वाहनों और रेल से लगभग डेढ़ सौ मजदूरों की दुर्घटनाओं में मृत्यु हो गई है। लेकिन सरकार इन मजदूरों को मुआवजा नहीं देना चाहती है। सरकार के पास यातायात के साधन है, लेकिन मजदूरों को रेल से भी नहीं भेजा गया। लेकिन असहाय और दुर्बल मजदूरों की सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। सरकार केवल भाषण से काम चलाना चाहती है। इसलिए सरकार की इस नीति का यूनियन डटकर विरोध करती है।

आज बिहार जाएगी ट्रेन, अंतिम चरण में पहुंची तैयारी

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

बिहार के लिए बुधवार को एक और ट्रेन ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। इसको लेकर जिला प्रशासन व रेलवे की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई है। जिला प्रशासन की तरफ से इससे पहले दो ट्रेने फरीदाबाद से बिहार के लिए रवाना कर दी थी। यह तीसरी बिहार स्पेशल ट्रेन होगी।

जानकारी के मुताबिक कोरोना और लॉकडाउन में लगातार कोविड-29 के बढ़ते मरीजों की संख्या और खाने व आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण लोगों ने अपने घरों को लौटने की गुहार जिला प्रशासन के सामने लगानी शुरू कर दी है। जिसे देखते हुए सरकार भी अब बढ़ते कोरोना के खतरे को लेकर गंभीर हो चुकी है। पैदल लौट रहे मजदुरों के लिए जिला प्रशासन अब बस व ट्रेनों से मजदूरों को अलग-अलग प्रांतों में भेज रहा है।

यहां गई ट्रेने : जिला प्रशासन और रेलवे की तरफ से सबसे पहले 12 मई को मध्यप्रदेश के लिए ट्रेन रवाना की गई थी। इसके बाद 15 मई को बिहार के बनौली और कटिहार जिले के लिए 2 ट्रेन गई थी, जिनमें करीब 3 हजार यात्री सवार थे।

अब भागलपुर ट्रेन

जिला प्रशासन की तरफ से बिहार के भागलपुर शहर के लिए एक और ट्रेन बुधवार को रवाना की जाएगी। जिसमें करीब 1500 यात्री सवार होंगे। इन यात्रियों को मंगलवार की शाम शेल्टर होम में ठहराया जाएगा। जहां उनके खाने-पीने की व्यवस्था के अलावा स्वास्थ्य जांच होगी। यह सब कार्य होने के बाद बुधवार को फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर मजदूरों को बसों से पहुंचाया जाएगा। इसके बाद सभी मजदूरों को टिकट देकर व तमाम औपचारिकताएं पूरी करते हुए ट्रेन में बैठाया जाएगा। स्टेशन अधीक्षक एके गोयल का कहना है कि बुधवार शाम के वक्त ट्रेन चलाई जाएगी।

बैठक में रखी बिजली कर्मचारियों की समस्याएं

फरीदाबाद। एचएसईबी वर्कर यूनियन की सर्कल कार्यकरिणी ने सर्कल सचिव सन्तराम लाम्बा की अगुआई में अपनी चारों यूनिटों के प्रधानों ने बैठक की। बैठक में लेखराज चौधरी, कर्मवीर यादव, सुनील चौहान व विनोद शर्मा सहित ट्रान्सफर होकर आये डीएचबीवीएन सर्कल फरीदाबाद के (एसई) अधीक्षक अभियन्ता नरेश कक्कड़ से परिचय बैठक कर अनेकों मुद्दों पर कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए चर्चा की। शुरुआती दौर की मुलाकाती चर्चा पर सर्कल सचिव सन्तराम लाम्बा ने कहा कि कोविड-19 विपदा के ऐसे समय मे जिस प्रकार सर्कल कार्यालय में व सबडिवीजन नम्बर तीन में कर्मचारियों के लिये कॉन्टेक्ट लैस हैंड सेनिटाइजर मशीन लगवाई गई है। ठीक इसी तरह की मशीन जल्द ही सभी दफ्तरों में कर्मचारी के लिये लगवाई जाये ।

अब टोकन के माध्यम से उपलब्ध होगा राशन: डीसी यशपाल

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

उपायुक्त यशपाल ने बताया कि कोरोना जैसी परिस्थितयों में हर जरूरतमंद व्यक्ति या परिवार तक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से डिस्ट्रेस राशन टोकन के माध्यम से राशन उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई। इस योजना के तहत जिला में 38 हजार 111 परिवारों को डिस्ट्रेस राशन टोकन वितरित किए गए हैं तथा इनका राशन डिपो होल्डर्स को जारी कर दिया गया है। जल्द ही सभी परिवारों को राशन उपलब्ध करा दिया जाएगा।

उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा उन जरूरतमंद परिवारों को डिस्ट्रेस राशन टोकन के माध्यम से राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिनके पास किसी भी प्रकार का राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है तथा वे गरीब परिवार की श्रेणी में आते हैं। इसके लिए यूनिट कमेटियों के माध्यम से सर्वे करवाया गया तथा जरूरतमंद परिवारों की पहचान की गई। जिला में अब तक 38 हजार 111 परिवारों की पहचान कर डिस्ट्रेस राशन टोकन वितरित किए गए हैं, जिनके माध्यम से करीब 78 हजार से अधिक लोगों को राशन उपलब्ध होगा। जिला के विभिन्न राशन डिपो पर इन टोकन की मैपिंग करते हुए पहले चरण में गेहूं व दाल एलोकेट की गई है। इस कूपन के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को नि:शुल्क गेहूं व दाल मिलेंगी। उन्होंने बताया कि ये डिस्ट्रेस राशन टोकन गरीब व प्रवासी श्रमिकों को मई व जून माह के लिए जारी किए गए हैं। इन टोकन के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को 5 किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति तथा एक किलोग्राम दाल प्रति परिवार प्रति माह निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।

उपायुक्त ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की ओर से जारी निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे परिवार अथवा व्यक्ति जिनके द्वारा गरीबी रेखा से नीचे अर्थात बीपीएल राशन कार्ड हेतू आवेदन किया हुआ है और वे जिला स्तरीय कमेटी द्वारा वैरिफाइड किए जा चुके हैं, परंतु बीपीएल कार्ड अभी जारी नहीं हुआ है, साथ ही मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत जिनको पूर्व में एपीएल कार्ड जारी किए गए थे, जिला प्रशासन द्वारा गठित लोकल कमेटी द्वारा किए गए सर्वे उपरांत चयनित परिवार, व्यक्तियों की सूची तथा मुख्यमंत्री ट्वीटर हैंडल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों की सूची जो जिला प्रशासन से प्राप्त हुई है, की श्रेणियों के परिवारों अथवा व्यक्तियों को डिस्ट्रेस राशन टोकन जारी किए जा रहे हैं।

सभी कूपन पर डिपो धारकों के नाम अंकित

जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक केके गोयल ने बताया कि डिस्ट्रेस राशन टोकन के लिए चयनित 38 हजार 111 परिवारों के लाभार्थियों को टोकन वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों को कूपन मिल चुके हैं, वे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए संबंधित डिपो धारक के माध्यम से राशन प्राप्त कर चुके हैं। सभी कूपन पर डिपो धारक का नाम अंकित है। उन्होंने बताया कि राशन का वितरण डिपो धारकों द्वारा पीओएस मशीन के माध्यम से किया जाएगा। राशन प्राप्त करते समय डीआरटी लाभार्थी को डिपो धारक को मूल डीआरटी व आधार पहचान पत्र दिखाना होगा। इसके लिए सभी डिपो धारक राशन वितरण के लिए अलग से मैनुअल रजिस्टर जरूर लगाएंगे तथा राशन वितरण के सभी इंद्राज किए जाएंगे, जिसमें लाभार्थी का पूर्ण आधार नंबर भी दर्ज किया जाएगा। लाभार्थी द्वारा मई व जून मास का राशन प्राप्त करने के बाद डीआरटी कूपन की मूल प्रति डिपोट धारक के पास जमा कराना होगा। डिस्ट्रेस राशन टोकन का वितरण संबंधित एसडीएम की देखरेख में किया जाएगा।

राहत: अब खुल सकेंगी दुकाने, नियम लागू

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

जिले में अब सभी प्रकार की दुकानों को खोलने के आदेश जिला प्रशासन के द्वारा जारी कर दिए गए है। यह दुकाने विभिन्न दिनों में दायें और बाये आधार पर खोली जाऐंगी। इसके लिए हुडा मार्केट में सभी दुकाने विभिन्न दिन ऑड ईवन की तर्ज पर खोली जाएगी। सरकार के आदेशानुसार प्रतिदिन 50 प्रतिशत दुकाने की खोली जा सकेंगी।

जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार जिल बाजारों में सड़क के दोनों और दुकाने है, उनमें सोमवार, बुधवार औश्र शुक्रवार को दाए और मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार के बाएं तरफ की दुकाने खोली जा सकेंगी। इसी तरह हुडा मार्केट में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सम और मंगलवार बृहस्पतिवार और शनिवार को विषम नम्बर की दुकाने खोली जा सकेगी। रविवार को सभी दुकाने पूरी तरह से बंद रहेंगी। जिला प्रशासन के द्वारा सभी दुकानों को खोलने का समय सुबह नौ से शाम छह बजे तक रहेगा। वहीं दूसरी तरफ आटा चक्की, मेडिकल स्टोर, दूध और सब्जी की दुकानों के लिए किसी तरह का कोई नियम लागू नहीं है। यह दुकाने रविवार को भी खुल सकती हैं और इनके लिए समय की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। शॉपिंग मॉल, होटल, स्पा, सैलून खोलने की अनुमति नहीं होगी। होटल व रेस्टोरेंट अपने यहां बिठाकर खाना नहीं खिला सकते, मगर वह होम डिलीवरी के लिए रसोई चला सकते हैं।

वित्तमंत्री की घोषणाएं

अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रयास

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने टुकड़ों-टुकड़ों में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए आर्थिक बूस्टर पैकेजों की घोषणा इस सप्ताहान्त तक की, लेकिन तथ्य है कि यह स्टीमुलस शायद ज्यादा प्रभावी नहीं होगा। किसी अन्य परिस्थिति में ये नीति-संचालित ढांचागत व परिवर्तनकारी घोषणायें दीर्घकालीन परिणाम दे सकती थीं। लेकिन यह वर्तमान समय में एजेंडा निर्धारित करने के उपयुक्त नहीं हैं जब कोविड-19 वैश्विक महामारी ने पहले से सुस्त अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका दिया है और ऐसे में बड़े पैमाने पर नकदी हस्तांतरण की आवश्यकता थी। इससे अर्थव्यवस्था को ज्यादा गति मिलती। प्रवासी श्रमिकों, स्वरोजगार प्राप्त लोग तथा छोटे बिजनेसों के मालिक कर्ज प्रक्रिया का पालन करने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसे में यह सहायता बहुत कम व बहुत देर से आई है। राज्यों को भी अपनी स्थिति सुधारने के लिए सहायता चाहिए। हालांकि, राज्यों द्वारा कर्ज लेने की सीमा बढ़ा कर उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद-जीएसडीपी के तीन प्रतिशत से पांच प्रतिशत की गई है। लेकिन इसे अनेक सुधारों से जोड़ा गया है जिनमें राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी, बिजली वितरण सुधार तथा बिजनेस सुगमता शामिल हैं। इस प्रकार निर्णय केन्द्रीय आंकलन पर आधारित होगा और इसका प्रयोग राजनीतिक औजार की तरह हो सकता है। इनमें से कोई उपाय मांग बढ़ाने व बेरोजगारी दूर करने की दिशा में लक्षित नहीं लगते हैं। ढांचागत विकास पर समग्र रूप से जोर दिए बिना रोजगार सृजन तथा आय या मांग बढ़ने की ज्यादा उम्मीद नहीं है। सरकार शायद डूबे कर्जों के भय से बड़े बैंक हस्तांतरणों से बचना चाहती है, लेकिन यदि वर्तमान स्थिति

सुधारने के लिए कुछ नहीं किया गया तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो सकती है। तमाम बड़ी-बड़ी बातों के बावजूद वास्तविक आर्थिक योगदान जीडीपी के एक प्रतिशत से थोड़ा अधिक है जो अभूतपूर्व संकट से निपटने के लिए काफी नहीं है क्योंकि अर्थव्यवस्था के 12.5 प्रतिशत सिकुड़ने की आशंका है। सभी पैकेजों का उद्देश्य सरकारी गारंटी के आधार पर बैंकों को कुछ क्षेत्रों को ज्यादा कर्ज देने को प्रेरित करना या कंपनियों में नकदी प्रवाह सुधारना है, जबकि अर्थव्यवस्था की सामूहिक समस्याओं को संबोधित करने की जरूरत है। वित्त मंत्री ने स्टीमुलस को 20 लाख करोड़ बताया है, पर वास्तव में इसका वित्तीय प्रभाव 1.7 लाख करोड़ होगा। कुछ धनराशि का प्रयोग दीर्घकालीन रूप से कृषि व संबंधित गतिविधियों के लिए ढांचागत निर्माण में होगा। नीतिगत रूप से कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर जोर दिया गया है जिनमें सामाजिक ढांचा, ग्रामीण रोजगार, कृषि को जीवन्त बिजनेस माडल में बदलना, जिला अस्पतालों में संक्रामक रोग ब्लाक बना कर स्वास्थ्यरक्षा सुविधाओं में सुधार तथा उपग्रह चैनलों के माध्यम से ई-लर्निंग कार्यक्रमों में सुधार शामिल हैं। ये सभी काम सार्वजनिक-निजी साझेदारी माडलों से हो सकते हैं। उद्यमियों को निवेश बढ़ाने के लिए नियामक सहायता के साथ रणनीतिक क्षेत्रों के अलावा अन्य में सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार घटाने की घोषणा की गई है। कोयला, खनिजों, रक्षा उत्पादन, नागरिक उड्डयन, बिजली वितरण, अंतरिक्ष व आणविक ऊर्जा में ढांचागत सुधार स्वागत योग्य हैं। एफडीआई सीमा बढ़ाने से उम्मीद है कि विदेशी व भारतीय फर्में स्थानीय उद्योग स्थापित कर कुछ तकनीक हस्तांतरण कर सकती हैं। मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ के अतिरिक्त आबंटन से पलायन कर रहे प्रवासी श्रमिकों को सहायता मिलेगी।

संकट ढांचागत सुधार का विरला अवसर होता है और सरकार को लीक से हट कर सोचना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में निवेश आकर्षित करने के बजाय मांग बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था ताकि विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याओं से निपटा जा सके और पूरी अर्थव्यवस्था को गति मिले। सरकार किसी भी समय वादे कर सकती है, पर उनमें से कितने रातोंरात जमीन पर उतरेंगे? वर्तमान संकट में सरकार का खर्च बढ़ाना कारगर उपाय है तथा दुनिया के अनेक देश यही कर रहे हैं।

कोविड-19 से संघर्ष करता भारत

कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में नेतृत्व करने का केन्द्र का निर्णय संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप है। राज्यों को कोरोना संकट से निपटने में उसका साथ देना चाहिए।

ए. सूर्यप्रकाश
लेखक लोकतांत्रिक अध्ययनों के विशेषज्ञ हैं

शायद हमारे देश में कोविड-19 वैश्विक महामारी पर पूर्ण नियंत्रण करने तथा इसका अंततः सफाया करने में कुछ और समय लग सकता है। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि कोरोनावायरस ने भारत के संघीय ढांचे तथा केन्द्र व राज्यों के बीच संबंधों को पुनः परिभाषित करने का रास्ता खोल दिया है। हालांकि, पूरा देश वायरस से निपटने को एकजुट राष्ट्रीय प्रयास की तरह ले रहा है, पर जहां-तहां कुछ असहमत स्वर हैं जो राज्यों को दिशा देने के केन्द्र सरकार के अधिकार पर सवाल उठाते हैं। देश ने कभी पहले ऐसा राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट नहीं देखा है, इसलिए इस प्रकार के आपातकाल से निपटने के लिए अपरिहार्य रूप से संवैधानिक व विधिक उपाय लागू करने हैं। इसका अर्थ 'एकीय झुकाव' है जिसका प्राविधान संविधान में है और वह इन परिस्थितियों में लागू होता है।

संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अंबेडकर ने खासकर आपात स्थितियों में भारतीय संघ व अन्य संस्थानों की प्रकृति पर विचार किया था। इस बारे में संविधान सभा में 25 नवंबर, 1949 को उनकी समापन टिप्पणी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि अत्यधिक केन्द्रीकरण का आरोप लगा है और कहा गया है कि राज्यों को नगरपालिकाओं के स्तर तक गिरा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह विचार न केवल अतिरंजित है, बल्कि यह संविधान के लक्ष्यों के प्रति गलत समझदारी पर आधारित है।

संघवाद का मूल सिद्धान्त यह है कि केन्द्र व राज्यों के बीच विधायी व कार्यकारी अधिकारों का विभाजन होता है। इसके लिए केन्द्र कोई कानून नहीं बनाता, बल्कि यह स्वयं संविधान द्वारा परिभाषित होता है। यह सिद्धान्त संविधान में अंतर्निहित है। इसलिए उन्होंने कहा कि केन्द्रवाद द्वारा संघवाद को पराजित करने का आरोप निरर्थक है। दूसरा आरोप यह था कि केन्द्र के पास राज्यों पर वर्चस्व का अधिकार है। अंबेडकर ने कहा था कि वे इस आरोप को 'स्वीकार' करते हैं। उन्होंने व्याख्या की कि यह वर्चस्व की शक्तियां संविधान का सामान्य अंग नहीं हैं। उन्होंने कहा, 'उनका प्रयोग व कार्रवाई स्पष्ट रूप से केवल आपात स्थितियों में ही होगा।'

स्पष्ट रूप से उनके दिमाग में न केवल आपातस्थिति घोषित करने संबंधी संविधान के अनुच्छेद थे, बल्कि वे अन्य चीजों के साथ ही आपातस्थितियों से निपटने के मामले में सातवीं अनुसूची की संघीय व समवर्ती सूची के बारे में भी सोच रहे थे। उदाहरण के लिए, सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची का 23वां बिंदु केन्द्र सरकार को कानून बनाने की शक्ति देता है जिसका संबंध 'एक राज्य से दूसरे में फैलने वाली संक्रामक व फैलने वाली बीमारियों अथवा मनुष्यों, जानवरों व पेड़-पौधों को प्रभावित करने वाले कीटों से हो।' वर्तमान वैश्विक महामारी तथा इससे निपटने के समन्वित राष्ट्रीय प्रयासों के संदर्भ में आपदा प्रबंधन कानून-डीएमए पर गौर किया जा सकता है जो केन्द्र को वर्तमान कोविड-19 से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति व कार्ययोजना बनाने का अधिकार देता है। यह कानून विभीषिका को 'एक भयानक घटना, दुर्घटना, आपदा या गंभीर घटना' के रूप में परिभाषित करता है। इसके अनेक प्राविधान केन्द्र को आपदा आने पर नियंत्रण अपने हाथ में लेने, निर्देश देने तथा उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का अधिकार देते हैं जिनमें धारा 6, 10 व 35 शामिल हैं।

राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष केन्द्रीय गृह सचिव द्वारा लाकडाउन व उसके

> **कोविड-19 के संदर्भ में केंद्र का निर्णय आंबेडकर व उनके साथियों द्वारा सात दशक पहले निर्धारित संवैधानिक योजना के अनुरूप था। संविधान आपातस्थिति से निपटने के मामले में केंन्द्र सरकार को कुछ अतिरिक्त शक्तियां तथा राज्यों पर वर्चस्व की शक्ति देता है। प्रख्यात संविधान विशेषज्ञ के.सी. व्हेरे के अनुसार, भारतीय संविधान सरकार की ऐसी व्यवस्था बनाता है जो छद्म संघीय है।**

क्रियान्वयन के संबंध में दिए जाने वाले आदेश डीएमए के इन प्राविधानों से निकलते हैं। उदाहरण के लिए, 29 मार्च के अपने आदेश में गृह सचिव ने देश के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में प्रवासियों के पलायन तथा सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लाकडाउन उपायों के उल्लंघन का हवाला देते हुए कहा था कि इन निर्देशों का उल्लंघन होने की स्थिति में राज्यों व संघशासित क्षेत्रों की सरकारों को आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। इस आदेश में पूर्णतः स्पष्ट किया गया था कि जिलों के जिला मजिस्ट्रेड व पुलिस सुपरिंटेंडेंट 'व्यक्तिगत रूप से इन निर्देशों व उपरोक्त आदेशों के अंतर्गत निर्देशित लाकडाउन उपायों को क्रियान्वित करने के जिम्मेदार होंगे।'

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आदेशों का उल्लंघन न हो क्योंकि आमतौर से जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस सुपरिंटेंडेंट केन्द्रीय सेवाओं से होते हैं और वे ऐसे मामलों में आदेश न मानने के नतीजे अच्छी तरह जानते हैं। समवर्ती सूची व डीएमए के प्राविधानों के साथ ही इपीडेमिक डिजीजेज़ एक्ट, 1897 भी केन्द्र को ऐसी महामारियों से निपटने की शक्तियां देता है।

लेकिन पश्चिम बंगाल राज्य ने केन्द्र द्वारा अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय टीमें भेजने के निर्णय का विरोध किया जो राज्य के कुछ जिलों में जमीनी स्थिति का आंकलन करने गई थीं जिनके कोविड-19 हाटस्पाट होने का संदेह था। कुछ राजनीतिक पार्टियां भी इस विरोध में शामिल हो गईं और उन्होंने केन्द्र सरकार के दृष्टिकोण पर आपत्ति जताई। लेकिन कोविड-19 के संदर्भ में केंद्र का निर्णय अंबेडकर व उनके साथियों द्वारा सात दशक पहले निर्धारित संवैधानिक योजना के अनुरूप था।

संविधान आपातस्थिति से निपटने के मामले में केन्द्र सरकार को कुछ अतिरिक्त शक्तियां तथा राज्यों पर वर्चस्व की शक्ति देता है। प्रख्यात संविधान विशेषज्ञ के.सी. व्हेरे के अनुसार, भारतीय संविधान सरकार की ऐसी व्यवस्था बनाता है जो छद्म-संघीय है। यह 'सहायक एकीय संरचनाओं वाले संघीय राज्य के बजाय सहायक संघीय संरचनाओं वाला एकीय राज्य है।' इवोर जेनिंग्स ने भी कहा है कि भारतीय संविधान 'मजदूत केन्द्रीकरण प्रवृत्तियों वाला संघ है।'

अपनी समापन टिप्पणियों में अंबेडकर ने कुछ आपात स्थितियों में मजबूत केन्द्र की ओर झुकाव का डट कर समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि बहुसंख्य लोगों की राय में आपातस्थिति में नागरिक की अतिरिक्त जिम्मेदारी संघटक राज्यों के बजाय केन्द्र के पास होनी चाहिए। उनके विचार से केवल केन्द्र ही सामान्य रूप से पूरे देश के हितों को समग्र रूप से साझा उद्देश्य के लिए आगे बढ़ा सकता है। आपातकाल में केन्द्र को कुछ वर्चस्ववादी अधिकार देने का यही औचित्य है। अंबेडकर ने कहा था, 'संघटक राज्यों पर इन आपातकालीन शक्तियों का पालन करने की कितनी जिम्मेदारी है?

आपातस्थिति में उनको अपने स्थानीय हितों का ध्यान रखने के साथ ही समग्र रूप से पूरे देश के दृष्टिकोण व हितों का ध्यान रखना होगा। केवल वही लोग शिकायत कर सकते हैं जिन्होंने समस्या समग्र रूप से नहीं समझी है।'

अंबेडकर के इन विचारों को पढ़ने के बाद ही उनकी समझदारी और दूरदृष्टि स्पष्ट होती है। वे इस देश और इसकी जनता को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वे उन समस्याओं का अनुमान लगा सकते थे जो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में राष्ट्रीय आपातकाल जैसी स्थिति में पैदा हो सकती थीं। वर्तमान समय में 42 राजनीतिक पार्टियां राज्यों व संघशासित क्षेत्रों का संचालन कर रही हैं तथा इस वैश्विक महामारी से निपटने की योजनाओं के मामले में विभिन्न दिशाओं पर जोर दे रही हैं। ऐसे में केवल एक केन्द्रीकरण वाली शक्ति केन्द्र व राज्यों से समुचित विचार-विमर्श कर इस स्थिति से निपट सकती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बारे में मुख्यमंत्रियों से कई बार चर्चा की है। हमें संविधान निर्माताओं का आभारी होना चाहिए कि उन्होंने इस वैश्विक महामारी व राष्ट्रीय आपातस्थिति से निपटने की संवैधानिक व्यवस्था बनाई थी।

संकट काल में विपक्षी दलों का नकारात्मक रवैया

हरीश चंद्र श्रीवास्तव
(लेखक सामाजिक व राजनीतिक विश्लेषक हैं)

इतिहास में संभवतः यह पहला अवसर है, जब पूरा संसार एक महामारी से त्रस्त होकर ठप पड़ा है। ऐसी आपदा में जहां देश के नागरिकों का व्यवहार राष्ट्रीय चरित्र की झलक देता है, वहीं राजनीतिक दलों, सामाजिक व धार्मिक संगठनों एवं समाज के उच्च पायदान पर बैठे व्यक्तियों के कार्य व आचरण समाज को दिशा देकर चेतना व आत्मबल का संचार करने में सहायक होते हैं। पर दुर्भाग्य यह है कि जनता की ओर से इस महामारी से निपटने में जितनी समझदारी, संयम और सहयोग मिला है, विपक्षी राजनीतिक दलों की ओर से उतना ही असंवेदनशील एवं असहयोगी रुख रहा है। ऐसे समय में जब एकजुट होकर जनता के साथ खड़े रहकर, सरकार द्वारा इस महामारी से निपटने के लिये उठाये जा रहे कदमों में सहयोग देकर और एक राजनीतिक दल के रूप में अपने तंत्र का प्रयोग जन समस्याओं को दूर करने के लिये होना चाहिये था, अधिकांश विपक्षी दल राजनीतिक बयानबाजी और जनता में भ्रम फैलाते रहे। लोकतंत्र की शक्ति अक्षुण्ण रखने और लोकतंत्र के उद्देश्य को पूरा करने के लिये आवश्यक है कि आपद काल में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलीय विसंगतियों से ऊपर उठकर साथ मिलकर दलीय तंत्र का उपयोग जनहित व जनता के संकट को दूर करने में करें। पर दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि ऐसा करने के बजाय अनेक विपक्षी दल निंदा व टांग खिंचाई में अधिक व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। जबकि यह समय सरकार व जनता के साथ खड़े होकर सुझाव देने और दलतंत्र के बजाय समाजतंत्र बनकर जनता की पीड़ा को कम करने में अधिकाधिक योगदान देने का है। वैसे उत्तर प्रदेश, ओड़िशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम और उत्तरपूर्व के राज्यों ने इस महामारी से निपटने में तत्परता व सकारात्मक कदम उठाये हैं, उससे कांग्रेस व उन अन्य दलों को सीखना चाहिये जिनका उद्देश्य जनता की सहायता के बजाय केवल और केवल छुद्र राजनीति रहा।

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार दूसरे प्रांतों के 13 लाख से अधिक श्रमिकों को लाकर उनके घर तक पूरी सतर्कता, राशन व आवश्यक वस्तुएं देकर पहुंचाया, वह सराहनीय है। योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में योगदान देने के लिये जिस प्रकार कमर कसी है और संकट के इस अवसर को राज्य के विकास व जनता के कल्याण का अवसर बनाने का प्रयास कर रहे हैं तथा अन्य राज्यों से आये प्रवासी श्रमिकों के लिये उत्तर प्रदेश में ही 50 लाख रोजगार सृजन की दिशा में कार्यरत हैं, वह प्रशंसनीय है। इसी प्रकार भाजपा की उत्तरप्रदेश इकाई ने भी जिस प्रकार पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं को लगाकर जरूरतमंदों तक भोजन, मास्क व अन्य सहायता निरंतर पहुंचा रही है तथा प्रवासी श्रमिकों के लिये शिविर लगाकर उनकी सहायता कर रही है, वह भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल की सार्थकता को प्रकट करती है।

यद्यपि लोकतंत्र की इस दलीय व्यवस्था का पक्ष आशा की किरण भी दिखाता है। विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल होने की जिम्मेदारी पूरी गंभीरता से निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने लॉकडाउन में देशभर में गरीबों, जरूरतमंदों व आपद स्थिति में फंसे श्रमिकों, परिवारों को भोजन पहुंचाने का अभिनंदनीय कार्य सफलतापूर्वक किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा करने के साथ ही मार्मिक अपील की थी कि सक्षम व समर्थ लोग अपने आसपास के गरीबों, मजबूरों, मजदूरों और प्राणियों की चिंता करें, जिससे कि न तो कोई मनुष्य भूखा रहे और न ही पशु—पक्षी।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के निर्देश पर 18 लाख भाजपा कार्यकर्ता लॉकडाउन की अवधि में देश भर में लोगों की सेवा कर रहे हैं। भाजपा ने अब तक दो करोड़ जरूरतमंद परिवारों को भोजन सामग्री वाला राशन किट और छह करोड़ से अधिक परिवारों को भोजन के पैकेट वितरित किये हैं। इसके अतिरिक्त भाजपा विभिन्न राज्यों से अपने गृह प्रांतों को जा रहे श्रमिकों व उनके परिवारों के लिये मार्ग में भोजन व अन्य आवश्यक वस्तुओं को पहुंचा रही है, साथ ही प्रवासी श्रमिकों के लिये शिविर लगा रही है। भाजपा ने 'फीड द नीडी' (जरूरतमंद को भोजन कराएं) कार्यक्रम चलाकर सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि देश के किसी भाग में कोई व्यक्ति लॉकडाउन में भूखा न रहे तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत 10 करोड़ लोगों को हाथ से बने फेस मास्क प्रदान किए जा रहे हैं। साथ ही भाजपा ने अंबेडकर जयंती पर झुग्गी-झोपड़ियों में %मेरी बस्ती, कोरोना मुक्त बस्ती% अभियान चलाया। इस अभियान के अंतर्गत भाजपा ने देश के सभी मंडलों में न्यूनतम दो गरीब बस्तियों के सभी घरों में महीने के भोजन सामग्री की किट बांटी।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे, ''राजनीति की धारा बदलनी होगी। प्रदर्शनात्मक राजनीति का मार्ग उचित नहीं है। जनतंत्र की सफलता और दल की सफलता के लिये सामान्य जन का कल्याण ही उद्देश्य होना चाहिये।'' दीनदयाल जी ने कहा है, ''राजनीतिक दल का उद्देश्य इदं न म अर्थात समाज के दीन, दलित, वंचित, जरूरतमंदों के प्रति ममत्व की भावना की प्रतिबद्धता होनी चाहिये, जिससे समाज के कल्याण के मार्ग में परिवर्तन किया जा सके। जनसंघ से भाजपा तक पहुंचने की यात्रा के पथ में राजनीतिक दल के रूप में भाजपा की राजनीति का मूल उद्देश्य यही रहा है। कोरोना महामारी के इस आपद काल में भाजपा ने यह देखे बिना कि राज्य में उसके दल का शासन है या नहीं, जिस प्रकार सरकार व प्रशासन का साथी बनकर जनता का दुख हरने में योगदान दिया है, वह दीनदयाल जी के उसी मंत्र इंद न मम् का प्राकट्य व प्रतिबद्धता है। अच्छा यह होता कि अन्य राजनीतिक दल भी इस आपद काल में आरोप—प्रत्यारोप का दौर छोड़कर एकाकार होते। यदि ऐसा होता तो आज श्रमिकों के पलायन से दारूण दृश्य उत्पन्न हुये हैं और और इस समस्या के समाधान के बजाय भड़काने व भ्रमित करने की जो राजनीति हो रही है, उससे बचा जा सकता था। मोदी सरकार द्वारा श्रमिकों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिये विशेष ट्रेनें चलायी गयी हैं, किंतु दुर्भाग्य से संवेदनहीन राजनीति का कुचक्र इसमें भी प्रवेश कर गया है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र राजस्थान, दिल्ली आदि प्रदेशों में जिस प्रकार प्रवासी श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार व अव्यवस्था हुई है तथा इन प्रदेशों की सरकारों ने जिस प्रकार संकट काल में ओछी राजनीति कर श्रमिक ट्रेनों की व्यवस्था का लाभ प्रवासी श्रमिकों तक पहुंचाने में न केवल असहयोग किया है, बल्कि प्रवादों के माध्यम से श्रमिकों को प्रदेश को छोड़ने के लिये अमानवीय परिस्थितियां उत्पन्न कीं, वह लोकतंत्र की दलीय व्यवस्था के उद्देश्यों के विरुद्ध है।

एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोरोना महामारी को परास्त करने में भारत को विश्व का नेतृत्वकर्ता बनाने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को स्थापित कर एक शक्तिशाली व समर्थ राष्ट्र का भव्य प्रासाद निर्मित करने का प्रयास कर रहे हैं तो वहीं विपक्ष के राजनीतिक दलों की यह जिम्मेदारी बनती है कि कोरोना संकट से निपटने में ओछी राजनीति के बजाय जनता के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करें। भारत का लोकतंत्र आशा के प्रकाश में उजाले की ओर बढ़ता रहा है तो यह अपेक्षा अनुचित नहीं होगी कि अब तक जो हुआ वो हुआ, पर अब आगे सभी राजनीतिक दल मिलकर राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य के पथ में सहायक बनेंगे।

आप की बात

लॉकडाउन महामारी

वैश्विक महामारी के चलते देश में लाक डाउन लगा हुआ है इस महामारी के चलते देश में तीन लॉक डाउन लगाए जा चुके हैं, फिर भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चौथा लॉक डाउन लगाया गया है लेकिन लॉक डाउन वैश्विक महामारी कोरोना को रोकने के लिए अति आवश्यक है, लेकिन अत्यधिक लंबा लॉक डाउन देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करता है यह लॉक डाउन अप्रवासी मजदूरों दिहाड़ी कामगारों बेरोजगारो और किसानों के लिए कठोर हालात पैदा करने वाला है, अत्यधिक लम्बा लॉक डाउन चलने की वजह से देश में भुखमरी और अकाल जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। अगर सही मायनों में देखा जाए तो सामुदायिक स्तर की जागरूकता ही हमें इस वैश्विक महामारी से बचा सकती है क्योंकि जागरूकता की वजह से स्वास्थ्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं देना अत्यधिक आसान हो जाता है सरकार को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म ओं का समुचित प्रयोग करके लोगों को अत्यधिक जागरूक करना चाहिए। इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए सबसे बढ़िया माध्यम टेस्टिंग है भारत में काफी सुस्त गति से टेस्टिंग का काम चल रहा है ऐसे में कोरोना महामारी को रोकना बहुत ही मुश्किल है।

– **योगेंद्र गौतम**, उन्नाव

सुस्ती में अर्थव्यवस्था

कोरोना के वर्तमान वैश्विक संकट नें पूरे विश्व की ही रफ़्तार पर ब्रेक लगा दिया है। लोग घरों में ही कैद होकर रह गए हैं। ऐसे में उत्पादन कार्य भी लगभग ठप है। लिहाज़ा पहले से ही सुस्ती की मार झेल रही भारतीय अर्थव्यवस्था अब संकट के दौर में प्रवेश कर चुकी है। हमारा ऋण जीडीपी का अनुपात पहले से ही अच्छा नहीं है। सरकार जीडीपी का 66.8 प्रतिशत कर्ज ले चुकी है। जो 136 लाख करोड़ से भी अधिक की राशि है। अर्थात आज के समय में प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए तो हर भारतीय नागरिक पर एक-एक लाख का कर्जा है। वित्त वर्ष 2020-21 के अपने बजट अनुमानों के हिसाब से भी सरकार को अपने खर्चों की भरपाई के लिए लगभग 7.8 लाख करोड़ की उधारी लेनी थी। इसके साथ ही सरकार को सार्वजनिक कम्पनियों के विनिवेश से भी 2.1 लाख करोड़ मिलने का अनुमान था। शेयर के मूल्य में आई भारी गिरावटों नें विनिवेश के इस लक्ष्य को भी मुश्किल बना दिया है। पिछले दो महीनों के लॉकडाउन से ही सरकार को लगभग 4 लाख करोड़ के राजस्व से भी हाथ धोना पड़ा है। यह सिलसिला आगे भी लॉकडाउन बढ़ते रहने के साथ कमोबेश जारी ही रहेगा।

– **वीरेंद्र बहादुर पांडेय**, गोंडा

पर्यावरण सुरक्षा जरूरी

कोरोनावायरस संक्रमण की वजह से से पैदा हुई वैश्विक महामारी से अभी पूरा विश्व परेशान है। इससे बचाव को लेकर हुए लाक डाउन में देखा गया कि पर्यावरण को इससे काफी फायदा पहुंचा। इसी बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा कि पर्यावरण नियम में सकती हो, सचमुच यह बहुत ही अच्छा प्रयास है। लॉक डाउन में हमने देखा कि पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में भी कमी आई है और पर मौसम भी साफ सुथरा रहा, हवा की गुणवत्ता भी सुधरी है। कई जगहों पर प्रदूषण की मात्रा में भी कमी आई है। साथ ही साथ जल की गुणवत्ता में भी काफी सुधार आया है, गंगा नदी जो कि पिछले कई वर्षों से प्रदूषित रहती थी वह अब बिल्कुल साफ सुधरी है। इतना सब कुछ सुधार सिर्फ एक लाक डाउन की वजह से ही हो पाया। यह हमेशा के लिए कायम रहे इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आशा है कि आगे भी हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा और हम एक जागृत और सशक्त होकर अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे।

– **सुदर्शन सोराड़ी**, नानकमता

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

फरमाया

जब कभी हमारी धरती पर आतंकी हमला होता है, पाकिस्तान चिंतित हो जाता है। उसे आतंक को बढ़ावा देना बंद कर चिंतामुक्त हो जाना चाहिए।

– **वायु सेना प्रमुख**
आरकेएस भदौरिया

मैं कांग्रेस पार्टी द्वारा घर वापस लौटते हमारे भाई-बहनों को 1000 बसें उपलब्ध कराने की अनुमति देने पर धन्यवाद देती हूं।

–**प्रियंका वाड्रा**
कांग्रेस महासचिव

प्रवासियों को कांग्रेस शासित राज्यों से सीधे घर वापस भेजने की व्यवस्था करने के बजाए उन्होंने सीमाओं पर बसें क्यों भेज दीं।

– **चंद्रमोहन**
उप्र भाजपा प्रवक्ता

यूपी के श्रमिकों से ट्रेन का किराया न लें दूसरे राज्यः योगी

● क्वेरंटाइन सेन्टर में पल्स आक्सीमीटर की व्यवस्था की जाए

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भी राज्य सरकार यूपी के प्रवासी श्रमिकों से ट्रेन से किराया न ले। उत्तर प्रदेश सरकार अपने सभी प्रवासी श्रमिकों का ट्रेन का किराया वहन करते हुए इन्हें प्रदेश में निःशुल्क ला रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश वापस आने के इच्छुक प्रवासी कामगारों तथा श्रमिकों को लाने के लिए सभी सम्बन्धित राज्यों से ट्रेन संचालित की जाए।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को लोक भवन में टीम.11 के साथ लाकडाउन व्यवस्था की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब तक राज्य सरकार ने 16 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों की प्रदेश में सकुशल व सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की है। विभिन्न राज्यों से 8.52 लाख प्रवासी श्रमिकों को लेकर 656 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें प्रदेश में आ चुकी हैं। अगले दो दिन में 258 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें और आएंगी। इस प्रकार कुल 914 ट्रेनों की व्यवस्था कर दी गयी है। राज्य सड़क परिवहन निगम की 12 हजार बसों के माध्यम से प्रवासी कामगारो व श्रमिकों को उनके गृह जनपद में भेजने की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा प्रत्येक जिलाधिकारी के निवर्तन पर 200 बसें रखते हुए इस प्रकार सभी 75 जनपदों में 15 हजार बसें अतिरिक्त रूप से उपलब्ध करायी गयी हैं। 16 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के बाद लगभग इतनी संख्या में प्रवासी श्रमिक अभी और आ सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्वारंटीन सेन्टर तथा कम्युनिटी किचन व्यवस्था को वर्तमान की भांति आने वाले समय में भी सुचारू और व्यवस्थित बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्वारंटीन सेन्टर तथा कम्युनिटी किचन व्यवस्था को और सुदृढ़ करते हुए आवश्यकतानुसार सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएं। क्वारंटीन सेन्टर में पल्स आक्सीमीटर की व्यवस्था की जाएए जिससे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा की जांच की जा सके। उन्होने निर्देश दिए कि क्वारंटीन सेन्टरध्आश्रय स्थल तथा कम्युनिटी किचन में कार्यरत कर्मियों को संक्रमण से बचाव के साधन उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा कि जनपदों में भेजे गए नोडल अधिकारी प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए वहीं कार्य करेंगे।

योगी ने कन्टेनमेन्ट जोन में होम डिलीवरी सुविधा को जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हाटस्पाट क्षेत्रों, क्वारंटीन सेन्टर तथा होम क्वारंटीन वाले लोगों के घरों को सेनिटाइज किया जाए। हाटस्पाट क्षेत्र के प्रत्येक घर को सेनिटाइज किया जाए। उन्होंने लाकडाउन के दौरान पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि हाई-वे, एक्सप्रेस-वे पर पीआरवी 112 के माध्यम से तथा बाजारों आदि में फुट पेट्रोलिंग की जाए। ग्रामीण इलाकों में सघन पेट्रोलिंग के लिए होमगार्ड तथा पीआरडी कार्मिकों के साथ साथ 60 वर्ष से कम आयु के भूतपूर्व सैनिकों की सेवाएं ली जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जनपद में एक टेस्टिंग लैब स्थापित होगी। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री कार्यवाही को आगे बढ़ाएं। उन्होंने टेस्टिंग क्षमता में वृद्धि के निर्देश देते हुए कहा कि इस सम्बन्ध में पूल टेस्टिंग को अपनाया जाए। दस-दस के भी पूल टेस्ट कराये जाएं। सभी जनपदों से पीपीई किट, एन.95 मास्क, ट्रिपल लेयर मास्क, ग्लव्स, सेनिटाइजर, दवाई, बेड शीट आदि लॉजिस्टिक्स की उपलब्धता की नियमित रिपोर्ट प्राप्त की जाए। उन्होंने अल्ट्रा रेड थर्मामीटर तथा पल्स आक्सीमीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये।

उन्होने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा अनुमोदित टेस्टिंग लैब ही कोविड.19 के संक्रमण की जांच कर सकती है। आईसीएमआर की अनुमति के बगैर कोविड.19 की जांच करने पर टेस्टिंग लैब के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सहयोग प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग एक वरिष्ठ अधिकारी को भेजने की व्यवस्था करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण से बचाव के उद्देश्य से मण्डियों में ग्राहक तथा व्यापारी सहित सभी लोग अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करें। उन्होंने मण्डियों में इंफेक्शन से बचाव के लिए सेनिटाइजर आदि साधनों की व्यवस्था के निर्देश भी दिए। शहरी व ग्रामीण इलाकों में गठित निगरानी समितियों के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से नियमित संवाद बनाते हुए समिति के कार्यों की जानकारी ली जाए। उन्होंने पुलिस को ग्राम प्रहरियों से संवाद स्थापित करने के निर्देश दिये।

पंद्रह फीसदी से कम लाइन हानि वाले गांवों को भी मिलेगी 24 घंटे बिजली

पायनियर समाचार सेवा, लखनऊ

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पंद्रह फीसदी से कम लाइन लास वाले गांवों को भी 24 घंटे बिजली दी जाएगी। इन गांवों के जर्जर तार प्राथमिकता के आधार पर बदले जाएंगे। विभागीय समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि अब ऐसे गांवों को भी 24 घंटे निर्बाध बिजली मिलेगी जहां लाइन हानियां 15 फीसदी से कम होंगी। राज्य सरकार गांवों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने तथा ओडीओपी के जरिए गांवों के अर्थव्यवस्था को सुदृढ करने में जुटी है। गांवों में कुटीर उद्योगों की स्थापना से रोजगार के साधन बढ़ेंगे, बिजली की निर्बाध उपलब्धता इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार ग्राम पंचायतों, प्रबुद्ध लोगों एवं युवाओं को इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करती है। ग्राम पंचायतें इस प्रतिस्पर्धा में शामिल होकर अपने गांव को 24 घंटे की आपूर्ति व्यवस्था का हिस्सा बना सकती हैं। ऊर्जा विभाग अब उपकेन्द्रवार अपने उपक्रमों की समीक्षा करेगा।

बगास से बनी बिजली का भुगतान करने की मांग

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश की निजी चीनी मिलों के संगठन यूपी शुगर मिल्स एसोसिएशन यूपी इस्मा ने यूपी पावर कारपोरेशन के चेयरमैन को पत्र लिखकर खरीदी गई बिजली का भुगतान जल्द से जल्द करने की मांग की है। यह बिजली इन चीनी मिलों में गन्ने की खोई से बनाकर पावर कारपोरेशन को बेची गई है। कारपोरेशन पर इन मिलों का करीब 1500 करोड़ रुपये का बकाया है। यूपी इस्मा के महासचिव दीपक गुप्तारा ने अपने पत्र में कहा है कि पावर कारपोरेशन ने करीब 15 महीनों से चीनी मिलों को उनके द्वारा बेची गई बिजली का भुगतान नहीं किया है। यह करीब 1500 करोड़ रुपये की राशि है। कोरोना संकट की वजह से राज्य की निजी चीनी मिलें इन दिनों भारी आर्थिक तंगी का सामना कर रही हैं। बाजार बंद होने और निर्यात न होने की वजह से चीनी की मांग न के बराबर रह गई है। इसलिए मिलें किसानों को उनसे खरीदे गये गन्ने का मूल्य समय से अदा नहीं कर पा रही हैं। यूपी एस्मा ने कहा कि यूपी पावर कारपोरेशन को निजी चीनी मिलों के बकाया 1500 करोड़ रुपये का भुगतान तत्काल करना चाहिए ताकि मिलों को किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान करने में सहूलियत हो सके।

कोरोना संकट की चुनौतियों से निपटने की सरकारी कवायद

● सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की पगार पर निर्धारित समय के लिए हो सकती है आंशिक कटौती

कमल दुबे। लखनऊ

कोरोना संकट के चलते पैदा आर्थिक चुनौतियों को देखते योगी सरकार ने आर्थिक प्रबंधन के प्लान-टू पर काम शुरू कर दिया है। वित्तमंत्री सुरेश खन्ना की देखरेख में शुरू हुई इस कवायद को सरकार के आपातकालीन प्लान के रूप में देखा जा रहा है। प्लान-टू के निशाने पर बड़े अफसर और कर्मचारियों की पगार हैं। जिसमे एक निर्धारित समयसीमा के लिये आंशिक कटौती हो सकती है। उच्चपदस्थ सूत्रों का कहना है कि सरकार की कुल राजस्व आय और खर्च का संतुलन बनाने के लिये प्लान-टू के ब्लूप्रिन्ट का खाका खींचा जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर इसे लागू करके आर्थिक चुनौतियों से निपटा जा सके।

आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि वित्तीय प्रबंधन का प्लान लागू किया जाना है या नहीं इस पर वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही की राजस्व आय और आगे की संभावनाओ का आंकलन करने के बाद योगी कोई सरकार फैसला लेगी। वैसे तो सीएम योगी कोरोना की चुनौती को अवसर के रूप में बदलने के लिये राज्य में विदेशी पूंजी निवेश लाने की कोशिशों में जुटे हैं। इसके लिये नीतियों और नियमों में विदेशी निवेशकों के अनुरूप कार्ययोजना तैयार करायी जा रही है। सीएम योगी को उम्मीद है कि कोरोना महामारी के चलते चीन से नाराज कम्पनियां यहां आएगी। विदेशी निवेश की उम्मीदों के बीच फिलहाल वित्तीय प्रबंधन के नये प्लान पर भी काम चल रहा है। कोरोना संकट के चलते राज्य सरकार की आय में सत्तर से अस्सी फीसदी की भारी गिरावट आयी है जबकि सरकार के खर्चे बढ़े हैं। कोरोना की जंग में पीड़ितों के इलाज और जांच से लेकर तमाम अन्य कार्यो पर उसे बड़ी धनराशि अपने बजट से खर्च करनी पड़ रही है। इन खर्चों से निपटने के लिये मंत्रियों और विधायकों के वेतन में तीस फीसदी की कटौती, विधायक निधि को निलंबित करने, पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी बढ़ाने तथा सरकारी कर्मचारियों के कई तरह के भत्तों में कटौती करने का फैसला सरकार पहले ही ले चुकी है। इसके अलावा सरकार ने हवाई यात्रा के लिए अधिकृत अधिकारियों की बिजनेस क्लास यात्रा, विभागों में नए वाहनों की खरीद तथा चालू वित्तीय वर्ष में कोई नया पद सृजित करने पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।

जानकारों का कहना है कि कोरोना संकट शुरू होने से पहले राज्य सरकार की कुल राजस्व का की अस्सी फीसदी से अधिक धनराशि कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और अन्य अधिष्ठान खर्च में चली जाती थी। केन्द्र सरकार से मिलने वाली धनराशि पर अधिकतर सरकारी योजनाएं और विकास कार्य निर्भर होते थे। सूत्रों का कहना है कि जुलाई और अगस्त माह तक सरकारी खजाना राज्य के खर्चो का उठा पाने की स्थिति में है। कोरोना की जंग ज्यादा लम्बी चलने और राजस्व आय के न बढ़ने पर आगे चलकर उसे और सख्त आर्थिक कदम उठाने की जरूरत पड़ सकती है। जिसे देखते हुये योगी सरकार अभी से कई बिन्दुओं पर काम कर रही है।

पात्र किसानों को बांटे जाएं अल्पकालीन ऋण

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

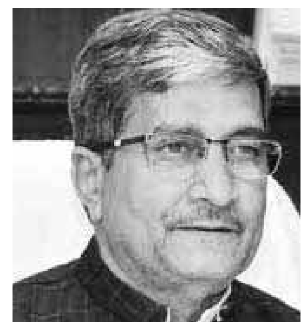

सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा कि जिला सहकारी बैंकों द्वारा अल्पकालीन ऋण वितरण व सहकारी देयों की वसूली का कार्य किया जाये। पात्र किसानों को अल्पकालीन ऋण वितरण करते हुए लाभान्वित किया जाये।

यह बातें श्री वर्मा ने मंगलवार को विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक के माध्यम से जिला सहकारी बैंको को दिये जाने अल्पकालीन ऋण वितरण एवं वसूली, यूपीसीबी के द्वारा ऋण वितरण एवं वसूली की समीक्षा के दौरान कहीं। उन्होने कहा कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाना चाहिए। किसानों को ऋण वितरण में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए और ऋण वितरण में किसानों को ऐसा नही महसूस हो कि उन्हें जिला सहकारी बैंक से ऋण प्राप्त करने में कोई समस्या हो रही है। उन्होंने समीक्षा के दौरान कहा कि सहाकरी देयों की वसूली का कार्य भी नियमानुसार किया जाये इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

श्री वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत त्रिस्तरीय साख व्यवस्था में एपेक्स स्तर पर कोआपरेटिव बैंक, केन्द्रीय स्तर पर जिला सहकारी बैंक तथा न्याय पंचायत स्तर पर कृषि ऋण सहकारी समितियों द्वारा कृषकों एवं अन्य ग्राहकों को कृषि निवेश एवं अन्य सहवर्ती आर्थिक क्रियाकलापों हेतु साख सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही है। उन्होंने कहा कि सहकारी समिति को बैंकिग सर्विस सेंटर के रूप में स्थापित किया जायेगा और इस सेवा केन्द्र पर डिजिटल अवास्थापना का विकास कर दूरस्थ गॉवों में डोर-टू-डोर सेवाये उपलब्ध करायी जायेगी जिससे जहॉ एक ओर वित्तीय समावेशन होगा तथा डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा मिलेगा वही दूसरी ओर समितियॉ भी आर्थिक रूप से सश्रम एवं स्वाश्रयी होगी। इस अवसर पर बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता एमवीएस रामीरेडडी, आयुक्त एवं निबन्धक एसवीएस रंगाराव, प्रबन्ध निदेशक यूपीसीबीए सहित अन्य सम्बधित अधिकारी आदि उपस्थित थे।

अराजकता की भेंट चढ़ गया है उत्तर प्रदेशः अखिलेश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश अराजकता की भेंट चढ़ गया है। कानून व्यवस्था से लेकर हर व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अपराधियों द्वारा लोगों को सरेआम गोलियों से भूना जा रहा हैं। मजदूर और कामगार त्राहि त्राहि कर रहे हैं। दबंगों और अपराधी तत्वों के हौसले आसमान पर हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। लॉकडाउन में जबकि हर जगह पुलिस तैनात है उसके बाद भी अपराधी तत्व हत्या कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने जनपद सम्भल के चंदौसी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम शमशोई में हुए दोहरे हत्या काण्ड पर आक्रोश व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता छोटेलाल दिवाकर एवं इनके पुत्र सुनील दिवाकर की नृशंस हत्या की घोर निंदा की है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के समय राज्य में अपराधों पर कोई रोक नहीं है। जौनपुर और आजमगढ़ में भी हत्यायें हुई है। अखिलेश ने कहा कि मजदूर भूखे प्यासे प्रदेश की सड़कों पर भटक कर रहे हैं। पुलिस मजदूरों पर लाठीचार्ज कर रही है। सरकार के लोगों को जनता की जरूरतों और समस्याओं की कोई चिंता नहीं है ।

कांग्रेस के पास वास्तव में 1000 बसें हैं तो भेजने में देर न करेः मायावती

लखनऊ। प्रवासी मजदूरों के लिए 1000 बसों के कांग्रेसी प्रस्ताव पर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी के पास वास्तव में 1000 बसें हैं तो उन्हें लखनऊ भेजने में कतई भी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी श्रमिक प्रवासी लोग भारी संख्या में अपने घरों में जाने का काफी बेसब्री से इन्तज़ार कर रहें हैं। मंगलवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा कि केन्द्र सरकार से अपील है कि वह राज्यों की आर्थिक स्थिति को खास ध्यान में रखकर तथा मानवता व इन्सानियत के नाते भी खुद अपने खर्च से श्रमिक प्रवासियों को बसों व ट्रेनों आदि से सुरक्षित भिजवाने के लिए जरूर सकारात्मक कदम उठाए।

मानक पर खरा न उतरने पर आयरन सुक्रोज दवा की सप्लाई पर रोक

● उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन की जांच में हुआ खुलासा, कंपनी ब्लैक लिस्टेड

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन ने खून की कमी से जूझ रहे गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली आयरन सुक्रोज की दवा के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। कारपोरेशन की तरफ से यह रोक प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट के आधार पर लगाई गई है। साथ ही कंपनी की दवा को 3 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। इस बाबत कारपोरेशन की तरफसे प्रमुख सचिव

प्रमुख सचिव को रिपोर्ट

स्वास्थ्य को रिपोर्ट भेज दी गई है। जिन गर्भवती महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है, उनमें आयरन सुक्रोज की दवा चढ़ाई जाती है। यह 5 से लेकर 20 एमएल के इंजेक्शन में आती है। कई बार कम हिमोग्लोबिन वाले दूसरों मरीजों को भी यह इंजेक्शन दिया जाता है। सरकारी अस्पतालों में इस इंजेक्शन की सप्लाई उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन द्वारा की जाती है। कारपोरेशन के सूत्रों के मुताबिक इंजेक्शन में क्वालिटी की शिकायत मिलने पर कारपोरेशन की तरफ से दवा की गुणवत्ता परखने के लिए बैच नम्बर एएजी-9004 और एएजी 9006 की जांच कराई गई। इसकी जांच प्रदेश की अलग-अलग तीन प्रयोगशालाओं में कराई गई। तीनों प्रयोगशालाओं ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें इंजेक्शन को मानकों के अनुरूप नहीं माना गया। जिसके बाद कारपोरेशन ने क्वालिटी को लेकर इंजेक्शन सप्लाई करने वाली कंपनी से शिकायत की। शिकायत पर कंपनी की तरफसे सप्लाई के दौरान क्वालिटी की चेन बरकरार रखने की बात कही गई। साथ ही यह भी कहा गया कि संभव है दवा के रखरखाव में किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई हो।

फिलहाल कारपोरेशन ने इस दवा के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। पूरे मामले की रिपोर्ट प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद को भेज दी है। बता दें कि कारपोरेशन की तरफ से सोलन की एक कंपनी को इस दवा की सप्लाई का कार्य मई 2018 में दिया गया था।

परीक्षा के दौरान छात्र या कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर एकेटीयू कराएगा इलाज

● 6 जुलाई से परीक्षाएं आयोजित करने के प्रस्तावित शेड्यूल पर मुहर

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

लॉक डाउन के हिसाब से यदि सब कुछ ठीक रहा तो डॉ एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की सत्रांत परीक्षाएं 6 जुलाई से शुरू हो जाएंगी। लॉक डाउन को लेकर यदि परिस्थितियां बदलती हैं तो फिर उसके आधार पर विश्वविद्यालय के कुलपति निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। परीक्षा के दौरान यदि कोई स्टूडेंट्स या कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिलता है तो फिर उसका इलाज विश्वविद्यालय प्रशासन अपने खर्च पर कराएगा। मंगलवार को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक की अध्यक्षता में संपन्न हुई परीक्षा समिति की 67 वीं बैठक के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षा संबंधी निर्णय लिए गए। बैठक में परीक्षा समिति ने परीक्षा केंद्रों के लिए आईपी आधारित सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य कर दिए हैं। साथ ही परीक्षा विभाग ने अपने संभावित कैलेंडर भी जारी कर दिए हैं। बैठक में समिति ने निर्णय लिया कि उपस्थिति के आधार पर इस बार किसी भी विद्यार्थी को डिटेन नहीं किया जायेगा। समिति द्वारा परीक्षा करवाए जाने के सम्बन्ध में प्रस्तावित किया गया कि यदि लॉकडाउन की तत्समय की स्थिति के आधार पर 30 जून के उपरान्त संस्थान खुलते हैं तो 6 जुलाई से प्रस्तावित शेड्यूल के अनुरूप परीक्षाएं संचालित की जायेंगी। यदि लॉकडाउन 30 जून के बाद भी नहीं खुलता हैए तो विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा। सत्रांत परीक्षाओ में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों को आरोग्य सेतु एप डाउन लोड करना अनिवार्य होगा। समिति ने निर्णय लिया है कि यदि परीक्षा के दौरान कोई भी विधार्थी, कर्मचारी एवं अधिकारी कोरोना पोसिटिव हो जाता है तो उसके पूरे इलाज का खर्च विवि के छात्र कल्याण एवं कर्मचारी कल्याण निधि से वहन किया जायेगा।

कोरोना के साथ ही सरकार के सामने जेई एईएस और डेंगू से निपटना भी चुनौती

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

● कोरोना के चलते संचारी रोग नियंत्रण माह की कार्य योजना अभी फाइलों तक सीमित

जिस कोरोना महामारी को सरकार वर्तमान में चुनौती मान कर चल रही है, उसी कतार में एक्यूट इन्सेफ्लाइटिस सिन्ड्रोम, जापानी इन्सेफ्लाइटिस, डेंगू तथा अन्य वेक्टर वार्न भी खड़ी हैं। यह बात दीगर है कि वर्तमान समय में इस ग्लोबल बीमारी से निजात पाने के लिए सरकार ने पूरी मशीनरी को लगा रखा है पर जेई, एईएस और डेंगू जैसी बीमारियों पर नियंत्रण पाने के लिए पिछले दो वर्ष से जारी प्रयास को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ऐसे में सरकार के समक्ष यह दोहरी चुनौती है, जिससे पार पाने के लिए सरकार को कड़ी मशक्कत करनी होगी। पिछले दो वर्षों से सरकार द्वारा जेई और एईएस पर नियंत्रण पाने के लिए प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक संचारी रोग नियंत्रण माह तथा 18 जनपदों में दिमागी बुखार से निपटने के लिए जागरूकता हेतु दस्तक अभियान का संचालन किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 विभागों की समन्वय समिति का गठन कर स्वास्थ्य विभाग को नोडल बना रखा है। इन विभागों में नगर विकास, पंचायती राज, बाल विकास एवं पुष्टाहार, चिकित्सा शिक्षाए ग्राम्य विकास, कृषि, पशुपालन, सिंचाई, शिक्षा, स्वच्छ भारत, सूचना जैसे कई अन्य विभाग शामिल हैं। दिमागी बुखार के मामलों के लिए 18 जनपद संवेदनशील के रूप में चिन्हित हैं जिनमें गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, बस्ती, लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर एवं बाराबंकी शामिल हैं। वहीं प्रदेश में चिन्हित 38 जनपदों में व्यापक पैमाने पर टीकाकरण के भी कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। मगर इस वर्ष कोरोना के चलते अभी तक संचारी रोग नियंत्रण माह की कार्य योजना फाइलों तक ही सीमित है। जबकि मई खत्म होने को है। इसके बाद सरकार के सामने केवल जून माह बचा है।

फरवरी तक चला अभियानः जेई तथा एईएस पर नियंत्रण को लेकर दिसम्बर 2019 से फरवरी 2020 तक अभियान संचालित किया गया। इसके तहत टीकाकरण, दस्तक अभियान, जागरूकता हेतु प्रचार-प्रसार मच्छर रोधी छिड़काव, वेक्टर नष्ट करने जैसे अभियान चलाए गए। सघन मिशन इन्द्रधनुष 2.0 अभियान में चुने गए प्रदेश के 425 ब्लाकों के अतिरिक्त इन 38 जनपदों के छूट रहे ब्लाकों को भी टीकाकरण अभियान में शामिल कर जेई और एईएस की दृष्टि से संवेदनशील गोरखपुर जनपद में भी शतप्रतिशत टीकाकरण कराया गया।

रंग लाई थी सरकार की मेहनतः सरकार के प्रयासों का नतीजा रहा कि वर्ष 2018 में माह जुलाई में प्रदेश स्तर पर 1271 केस एईएस के संज्ञान में आये थे। जिनमें 107 लोगो को नहीं बचाया जा सका था, ये मृत्युदर 08.42 प्रतिशत थी। जबकि वर्ष 2019 माह जुलाई में कुल 615 केस ही एईएस के संज्ञान में आये, जिनमें से 26 लोगो को नहीं बचाया जा सका। यह मृत्यु दर घटकर 4.23 प्रतिशत हुई थी। जो वर्ष 2018 की तुलना में लगभग आधी रह गई। इसी प्रकार वर्ष 2018 जुलाई माह में जेई के 72 केस संज्ञान में आये जिनमें 4 लोगों की मृत्यु हो गयी। वर्ष 2019 माह जुलाई में 39 केस ही संज्ञान में आये जिनमें 3 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई थी।

सरकार और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर

कांग्रेस महामारी में कर रही है क्रूर मजाकः डॉ. दिनेश शर्मा

लखनऊ। प्रदेश सरकार का पक्ष रखते हुए उपमुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा ने कहा कि पूरे देश में श्रमिकों को लाने का कहीं काम किया गया है तो वो यूपी सरकार ने किया है। इस समय सभी को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए लेकिन कांग्रेस ने गुमराह करने का काम किया, इनका आचरण सामने आ गया। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को लाने, ले जाने के लिए जिलों के बॉर्डर पर 200 बसें रखी गईं हैं। जिला अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसा काम पूरे देश में सिर्फयोगी सरकार ने किया है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह व्यवधान लगाना और जनता को गुमराह करना जानती है। ये आपराधिक कृत्य है। कांग्रेस नाइंसाफी कर रही है। काम की बजाय टिप्पणी करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। उपमुख्यमंत्री डा. शर्मा ने कहा कि यूपी में बसों और बाकी चीजों की कोई कमी नहीं है। सबसे ज्यादा प्रवासियों को यूपी सरकार लाई है और अभी ला रही है।

राहुल व प्रियंका की कांग्रेस फर्जीवाड़ा पार्टीः सिद्धार्थ नाथ

लखनऊ। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रियंका वाड्रा ने जो बसों की सूची भेजी हैए उसमें थ्रीव्हीलरए आटो रिक्शाए एंबुलेंस व टाटा मैजिक निकल रही है। कांग्रेस द्वारा सौंपी गई लिस्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने एक वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर का जिक्र किया है। 10 नंवबर 2016 को रजिस्टर हुई वाहन संख्या यूपी83टी1006 की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि ये बस नहीं बल्कि एक थ्री व्हीलर है। इसी तरह आरजे 14टीडी1446 एक बस न होकर कार है। इसी तरह एक वाहन का जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी 85टी 6576 है, जांच करने पर ये वाहन स्कूटर है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के वाहन पोर्टल पर राहुल और प्रियंका के फर्जीवाड़ा का खुलासा हो चुका है। कांग्रेस को श्रमिकों से कोई संवेदना नहीं, कोई सेवाभाव नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल और प्रियंका की कांग्रेस फर्जीवाड़ा पार्टी है। इनके अंदर कोई संवेदनशीलता नहीं है।

जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही कांग्रेसः स्वतंत्र देव

लखनऊ। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी को संकटकाल में लोगों की मदद करनी चाहिए लेकिन वह मदद की बजाय लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। मजदूरों की मदद के नाम पर कांग्रेस ने बस की सूची बनाने में भी घोटाला कर दिया। प्रवासी श्रमिकों के लिए बसों की व्यवस्था के नाम पर कांग्रेस द्वारा उपलब्ध सूची को कांग्रेस बस घोटाला बताते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र में यूपी बिहार झारखंड के लोगों को बसें नहीं दे पा रही। वहां लोग पैदल चलने को मजबूर हैं। केवल सियासत करने के लिए इन्होंने यूपी सरकार से मजदूरों की मदद करने के लिए बसें उपलब्ध कराने और उनकी अनुमति की मांग की। जब राज्य सरकार ने अनुमति दे दी तब बसों के नाम पर स्कूटर, आटो रिक्शा, एम्बुलेंस, मालवाहक गाड़ियों की सूची भेज दी। इतना ही नहीं सूची में बड़ी संख्या में ऐसी गाड़ियां भी हैं जो ब्लैकलिस्टेड हैं।

आजादी से आज तक कांग्रेस ने बड़े घोटाले किएः महेंद्र सिंह

लखनऊ। जलशक्ति मंत्री डॉ महेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता को देखकर कुछ नेता बैखला गए है। उन्होंने कहा कि घोटालाए भृष्टाचार ए झूट बोलना कांग्रेस के ब्लड में है। जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने यह बात मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि भारत के मजदूरों से कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिएए आजादी से आज तक कांग्रेस ने बड़े घोटाले किये है आज एक बस का नया घोटाला किया हैए सरकार इस मामले पर कार्रवाई करेगी। महेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 10 लाख मजदूरों को ट्रेनों के माध्यम से घर तक पहुँचने का काम किया हैए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भारत को कलंकित कर चुकी हैए उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा पढ़ी में छूट दिया था और कांग्रेस ने लिखा पढ़ी में झूठ बोला है।

सरकार तकनीकी तौर पर उलझाकर नहीं दे रही बसें चलाने की अनुमति

लखनऊ। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बार्डर पर लाखों की संख्या में श्रमिक अपने घरों को आना चाहते हैं जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने 1000 बसों की व्यवस्था कराई है। जिसे प्रदेश की योगी सरकार तकनीकी तौर पर उलझाकर चलाने की अनुमति नहीं दे रही है। उन्होने कहा कि पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने 16 मई को पत्र लिखकर 1000 बसें चलाने की अनुमति मांगीं थीं। उस पत्र को प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू एवं नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा मोना के नेतृत्व में पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र ले जाकर दिया गया जिस पर दो दिन बाद सरकार के अपर गृह सचिव अवनीश अवस्थी ने प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह को पत्र भेजकर बसों का विवरण, फिटनेस, चालक एवं परिचालक के नामों की सूची मांगी। जिसे कांग्रेस पार्टी ने तत्काल 1000 से अधिक बसों की सूची सरकार को उपलब्ध करा दिया।

चीन की सेना ने लद्दाख और उत्तर सिक्किम में उग्र रुख अपनाया

भाषा। नई दिल्ली

भारत और चीन के बीच गैर चिह्नित सीमा पर उत्तर सिक्किम और लद्दाख के पास कई इलाकों में तनाव बढ़ता जा रहा है और दोनों पक्ष वहां अतिरिक्त बलों की तैनाती कर रहे हैं। दोनों पक्ष के बीच इन इलाकों में कुछ दिनों पहले दो बार हिंसक झड़प हो चुकी है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि भारत और चीन दोनों ने डेमचक, दौलत बेग ओल्डी, गलवान नदी तथा लद्दाख में पैंगोंग सो झील के पास संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की है। गलवान के आसपास के इलाके दोनों पक्षों के बीच छह दशक से अधिक समय से संघर्ष का कारण बने हुए हैं। 1962 में भी इस इलाके को लेकर टकराव हुआ था। सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्षों ने गलवान नदी और पैंगोंग सो झील के आसपास अपने सैनिकों की तैनाती की है। इन इलाकों में दोनों पक्षों की ओर से सीमा गश्ती होती है।पता चला है कि चीन ने गलवान घाटी इलाके में काफी संख्या में तंबू गाड़े हैं जिसके बाद भारत वहां कड़ी नजर बनाए हुए है।पैंगोंग सो लेक इलाके में पांच मई को भारत और चीन के करीब 250 सैनिकों के बीच लोहे की छड़ों, डंडों से लड़ाई हुई और पथराव भी हुआ जिसमें दोनों पक्षों के सैनिक जख्मी हुए थे। एक अन्य घटना में सिक्किम के नाकू ला दर्रा क्षेत्र में नौ मई को भारत और चीन के करीब 150 सैनिक आमने-सामने हो गए। सूत्रों के मुताबिक घटना में दोनों पक्ष के करीब दस सैनिक जख्मी हुए थे। दोनों सेनाओं के बीच तनाव पर न तो सेना, न ही विदेश मंत्रालय ने कोई टिप्पणी की है। विदेश मंत्रालय ने तनातनी पर पिछले हफ्ते कहा था कि चीन के साथ सीमा पर वह शांति और धैर्य बनाए रखने का पक्षधर है और कहा कि सीमा के बारे में अगर साझा विचार होता तो इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता था। यह पता चला है कि उत्तर सिक्किम के कई इलाकों में अतिरिक्त सैनिकों को भेजा गया है। चीन के सरकारी मीडिया ने सोमवार को खबर दी थी कि अक्साई चिन क्षेत्र की गलवान घाटी में चीन के सैनिकों ने सीमा नियंत्रण उपाय मजबूत किए हैं। सरकारी ग्लोबल टाइम्स ने सेना के अज्ञात सूत्रों के हवाले से खबर दी, गलवान घाटी क्षेत्र में चीनी क्षेत्र में हाल में भारत द्वारा अवैध रक्षा निर्माण के बाद चीन ने यह कदम उठाया है।

उत्तराखंड में धारचूला को लिपुलेख दर्रे के साथ जोड़ने वाली सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क पर निर्माण को लेकर नेपाल और भारत के बीच बढ़ते सीमा विवाद के बीच दोनों पक्षों के बीच तनातनी की खबर आई है। लिपुलेख दर्रा कालापानी के पास स्थित है जो नेपाल और भारत के बीच विवादित सीमावर्ती क्षेत्र है। भारत और नेपाल दोनों कालापानी पर अपना दावा करते हैं। भारत में सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद उनके नेपाल दौरा करने की परंपरा रही है लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि जनरल एम एम नरवणे नेपाल का दौरा जल्द करेंगे या नहीं। उनसे पहले जनरल बिपिन रावत ने सेना प्रमुख बनने के तीन महीने के भीतर नेपाल का दौरा किया था। चीन ने मंगलवार को कहा कि कालापानी भारत और नेपाल के बीच का मुद्दा है और उम्मीद जताई कि दोनों पड़ोसी एकतरफा कार्वाई करने से बचेंगे और दोस्ताना सलाह-मशविरा से अपने विवादों का उचित समाधान करेंगे।

जालंधर में लॉकडाउन में फंसे उप्र के प्रवासी लोग लाइन लगाकर बस से सवार होकर रेलवे स्टेशन जाते हुए।

फड़णवीस का पवार पर निशाना, महाराष्ट्र सरकार से आर्थिक पैकेज देने को कहा

मुंबई। भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेन्द्र फड़णवीस ने आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज को लेकर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखने के लिए राकांपा प्रमुख शरद पवार पर निशाना साधते हुए महाराष्ट्र की शिवसेना नीत सरकार से भी ऐसी ही मांग की। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए विपक्षी पार्टी के विधायकों से पूछा कि अगर उन्हें महाराष्ट्र की इतनी ही चिंता है तो उन्होंने अपनी विधायक निधि को पीएम-केयर्स फंड के बजाय मुख्यमंत्री राहत कोष में दान क्यों नहीं दिया। महाराष्ट्र में कोविड-19 संक्रमण और मौत के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं।

महाराष्ट्र में शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के गठबंधन महा विकास आघाड़ी (एमवीए) की सरकार है। फड़णवीस ने भाजपा के अन्य नेताओं के साथ राज्यपाल से हुई मुलाकात के बाद कहा, उद्धव ठाकरे नीत एमवीए सरकार को केन्द्र की तरह पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। राकांपा प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को कई बार पत्र लिखे। उन्हें इसी तरह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी पत्र लिखने चाहिए।

पवार ने हाल ही में प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा था कि केंद्र के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में लॉकडाउन अवधि के दौरान किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रावधानों का अभाव है। किसानों के पास नकदी नहीं बची है। कांग्रेस ने फड़णवीस पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा महाराष्ट्र विरोधी है और हर मुद्दे पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस की राज्य इकाई के प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा, भाजपा विधायकों ने अपनी विधायक निधि को पीएम-केयर्स फंड में दान कर दिया। उन्होंने इसे मुख्यमंत्री राहत कोष में दान क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि भाजपा कोविड-19 के खिलाफ जंग में राज्य सरकार का साथ देने के बजाय राजनीति में व्यस्त है। सावंत ने कटाक्ष करते हुए कहा राज्य सरकार को केंद्र सरकार की तर्ज पर किसी भी आर्थिक पैकेज की घोषणा नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह "खोखले वादों से भरा हुआ" है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही लोगों की समस्याओं को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र... राज्य सरकार के कामकाज में समस्याएं पैदा कर रहा है।

कोविड-19 के कारण मप्र की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है: शिवराज

भाषा। भोपाल

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोविड-19 के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है लेकिन राज्य सरकार ने जरूरतमंदों की सहायता के लिए 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खातों में डाली है। चौहान ने सोमवार रात दूरदर्शन के माध्यम से प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए कहा, कोरोना वायरस के कारण जब प्रदेश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, तब हमने गरीबों, मजदूरों, किसानों, बच्चों, माताओं, बहनों आदि की सहायता के लिए 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खातों में डाली है, जिससे समाज के किसी भी वर्ग को दिक्कत एवं तकलीफ न होने पाए। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना वायरस संकट से ध्वस्त अर्थव्यवस्था को पुन: खड़ा करने के लिए विभिन्न आर्थिक पैकेज दिए हैं। हम इन्हें आदर्श रूप से जमीन पर उतारेंगे।

चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया है, हम उस पर चलकर मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसके लिए खाका तैयार किया जा रहा है तथा उसे शीघ्र ही आपके समक्ष रखा जाएगा। सब मिलकर मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लें। हमें अभी कुछ समय और कोविड-19 के साथ जीना है तथा अपनी अर्थव्यवस्था को भी गति देना है। चौहान ने कहा, हमें पूरी सावधानी के साथ एवं संतुलित रूप से चलना होगा जिससे कोरोना वायरस संक्रमण फैले नहीं और जिन्दगी भी रफ्तार पकड़े। काम कठिन है परंतु हमारा हौसला बुलंद है।

प्रदेश सरकार द्वारा जनता के हित में उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे प्रवासी मजूदर भाई-बहन बिल्कुल भी चिंता न करें। सभी को बसों एवं ट्रेनों के माध्यम से उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। इस काम के लिए 91 से अधिक ट्रेन तथा हजारों बस लगाई गई हैं। साथ ही प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले तक भी मजदूरों को पहुंचाया जा रहा है।

चौहान ने कहा, जिन मजदूर भाईयों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी नि:शुल्क राशन दिया जा रहा है। जो कार्य करना चाहते हैं तथा जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है, पंचायतों के माध्यम से उनका जॉब कार्ड बनवाकर उन्हें काम दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि ए संबल योजना के भी पात्र होंगे। संबल योजना गरीब का सुरक्षा कवच है जो उनकी हर आवश्यकता की पूर्ति करता है। चौहान ने कहा कि प्रदेश में गेहूँ उपार्जन के अंतर्गत अभी तक 90 लाख टन से अधिक गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है तथा किसानों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान भी किया जा चुका है। उन्होंने कहा, किसान भाई बिल्कुल चिंता न करें हम उनका एक-एक दाना खरीदेंगे। किसान भाई एसएमएस मिलने पर ही अपनी उपज बेचने उपार्जन केन्द्र पर आएं तथा एक-दूसरे से दो गज की दूरी रखें एवं सभी सुरक्षा उपाय अपनाएं।

चौहान ने बताया कि चना, मसूर एवं सरसों का समर्थन मूल्य पर खरीद का कार्य भी जारी है। चौहान ने कहा, मध्यप्रदेश में हम काफी हद तक कोरोना वायरस को नियंत्रित करने में सफल रहे हैं। कोरोना वायरस के मामलों के दोगुना होने की दर एक अप्रैल को तीन दिन थी, जो कि एक मई को बढ़कर 14 दिन हो गई। वर्तमान में यह दर 17.2 दिन है, जो जल्दी ही 20 दिन हो जाएगी। मध्यप्रदेश में अब तक कोविड-19 से संक्रमितों का आंकड़ा 5,236 तक पहुंच गया है। इनमें से कुल 2,435 मरीजों को इलाज के बाद स्वस्थ होने पर अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है, जबकि 252 लोगों की मौत हो चुकी है और 2,549 लोग अब भी संक्रमण की चपेट में हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है।

जम्मू-कश्मीर में आवास संबंधी नए नियम शरणार्थियों कश्मीरी पंडितों को लंबित अधिकार देगा: नड्डा

नई दिल्ली। भाजपा ने जम्मू-कश्मीर में निवास संबंधी नए नियमों को अधिसूचित किए जाने की मंगलवार को सराहना की और पार्टी के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने कहा कि ए नए नियम सभी शरणार्थियों के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश से बाहर रह रहे कश्मीरी पंडितों को उनके लंबित अधिकार दिलाएगा। जम्मू-कश्मीर प्रशासन की तरफ से सोमवार को जारी नए नियमों के तहत पश्चिम पाकिस्तान के लोगों, वाल्मिकियों, समुदाय के बाहर शादी करने वाली महिलाओं, गैर-पंजीकृत कश्मीरी प्रवासियों और विस्थापित लोगों को जल्द ही आवास अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। उन्होंने ट्विटर पर कहा, आवास संबंधी नए नियमों का जम्मू-कश्मीर में अधिसूचित होना स्वागत योग्य कदम है। यह पश्चिम पाकिस्तान के लोगों समेत अन्य शरणार्थियों, दशकों से जम्मू-कश्मीर में बसे अनुसूचित जाति के कर्मी, जम्मू-कश्मीर से बाहर रह रहे कश्मीरी पंडितों के बच्चों को अब आवास का दावा करने का लंबे समय से अटका अधिकार प्राप्त हो जाएगा। सभी के लिए समानता एवं गरिमा होगी। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने आवास संबंधी नए नियमों को अब अधिसूचित कर दिया है। अधिसूचित किए गए अधिवास संबंधी नए नियम अब जम्मू-कश्मीर के स्थाई निवासी संबंधी पूर्व के नियमों को हटा देंगे जो कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए के प्रावधानों को निरस्त किए जाने के साथ ही रद्द हो गए थे। भारत इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था।

राज्यसभा सदस्य ने असम के राज्यपाल पर लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप लगाया

नई दिल्ली। असम में भाजपा के सहयोगी बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) के नेता एवं राज्यसभा सदस्य विश्वजीत दैमरी ने मंगलवार को दावा किया कि प्रदेश के राज्यपाल जगदीश मुखी ने विभिन्न संगठनों की बैठक करके लॉकडाउन से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को लिखे पत्र में असम से दो बार के राज्यसभा सदस्य दैमरी ने कहा कि मुखी ने मंगलवार को कोकराझार का दौरा किया और 29 राजनीतिक दलों, सामाजिक धार्मिक संगठनों के सदस्यों को बातचीत के लिए बुलाया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर के भीतर रहेंगे। मुखी की उम्र 70 साल से अधिक है। सरकार के दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए दैमरी ने कहा कि सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक एवं धार्मिक समारोह जैसी गतिविधियां नहीं होंगी। सवाल किया कि क्या राज्यपाल का विभिन्न संगठनों के लोगों को बुलाना और बातचीत करना सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं है? दैमरी ने कहा कि 29 संगठनों के सदस्यों की बैठक में सामाजिक दूरी को बरकरार रख पाना मुश्किल है।

ताडोबा अभयारण्य में बाघ के हमले में महिला की मौत

चंद्रपुर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में ताडोबा अंधारी बाघ अभयारण्य में बाघ के हमले में 63 साल की एक महिला की मंगलवार को मौत हो गई। अभयारण्य के मुख्य वन संरक्षक एनआर प्रवीण ने बताया कि कोलारा गांव की निवासी लीलाबाई जीवतोडे तेंदू की पत्तियां तोड़ने के लिए तड़के सतारा जंगल (संरक्षित वन क्षेत्र) में गई थी, तभी यह घटना हो गई। उन्होंने बताया कि महिला का शव बरामद कर लिया गया है। अधिकारी ने कहा कि कई बार चेतावनी दी गई थी कि इलाके में बाघ छुपे रहते हैं, फिर भी ग्रामीण तेंदू पत्तियां लेने के लिए जंगल जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह सतारा गांव क्षेत्र में मानव-पशु संघर्ष की दूसरी घटना है। चंद्रपुर जिले में बाघ के हमले में इस साल कम से कम 11 लोगों की मौत हो चुकी है।

राजस्थान के झुंझुनूं में भूकंप के झटके

जयपुर। राजस्थान के झुंझुनूं जिले में मंगलवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप से जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। जयपुर के मौसम केंद्र के निदेशक शिव गणेश ने बताया कि भूकंप का केंद्र जमीन में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। सुबह नौ बज कर 21मिनट पर भूकंप आया था जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.2 मापी गई। जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष के अनुसार भूकंप के कारण कहीं से जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है।

मंगलवार को पश्चिम बंगाल के नाडिया में एक बाग में लीची खाता हुआ तोता

कांग्रेस विधायक ने अहमदाबाद में कोविड-19 के मरीजों की मौत को लेकर एनएचआरसी को पत्र लिखा

अहमदाबाद। गुजरात के कांग्रेस विधायक गयासुद्दीन शेख ने मंगलवार को आरोप लगाया कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल में कोविड-19 के मरीजों के अनुपयुक्त उपचार एवं लापरवाही के कारण बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं और उन्होंने इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप की मांग की। आयोग को भेजे पत्र में शेख ने दावा किया कि ऐसा ही परिदृश्य अन्य सरकारी अस्पतालों में भी है, जहां वरिष्ठ डॉक्टर कोविड-19 के मरीजों के इलाज से दूर रह रहे हैं और जिम्मेदारी जूनियर डॉक्टरों एवं अर्धचिकित्साकर्मियों को सौंप दे रहे हैं।

सोमवार तक सिविल अस्पताल समेत अहमदाबाद के विभिन्न अस्पतालों में कोविड-19 से 555 मरीजों की जान जा चुकी थी। विपक्षी विधायक ने कहा, अहमदाबाद में कोरोना वायरस की उच्च मृत्युदर अनुपयुक्त उपचार तथा डॉक्टरों एवं अधिकारियों की लापरवाही के चलते है। शेख ने एक वीडियो संदेश में कहा, मेरे संज्ञान में आया है कि डॉक्टर मरीज की मौत के तीन घंटे बाद भी इससे अनभिज्ञ रहते हैं। रिश्तेदारों को मरीजों के उपचार या उसके स्वास्थ्य में प्रगति के बारे में नहीं बताया जाता है।

इन्हीं तरीकों की वजह से सिविल अस्पताल में बड़ी संख्या में कोरोना वायरस के मरीज मर गए। कांग्रेस विधायक ने कहा, मरीजों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए मैंने आज एनएचआरसी को पत्र लिखा और उससे हस्तक्षेप की मांग की। मैंने सिविल अस्पताल के समूचे कामकाज की जांच की भी मांग की है। अहमदाबाद में दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक शेख ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि कुछ मरीजों की मौत के बारे में उनके रिश्तेदारों को करीब एक सप्ताह बाद जानकारी दी गई। गुजरात में कोरोना वायरस के कुल 11,746 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 8,683 मामले अकेले अहमदाबाद के हैं।

केरल से उप्र और बिहार पैदल लौट रहे प्रवासी कामगारों को रोककर शिविरों में भेजा गया

भाषा। कन्नूर (केरल)

केरल से उत्तर प्रदेश और बिहार स्थित घरों को जाने के लिए पैदल ही निकले कम से कम 100 प्रवासी कामगारों को पुलिस ने मंगलवार को रोककर उन्हें उनके शिविरों में वापस भेज दिया। कामगारों का आरोप है कि उन्हें शिविरों में पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिल रहा है और न ही सरकार उनके लौटने के लिए रेलगाड़ियों की व्यवस्था कर रही है।

उत्तर प्रदेश और बिहार के कामगारों ने कहा, हम अपने गृह प्रदेशों को लौटना चाहते हैं। दिन में एक बार खाना दिया जा रहा है और हमारे पास पैसे नहीं है। कोई काम भी नहीं है। पानी की बोतल और अपना कुछ समान लेकर ए कामगार प्लाईवुड उद्योग के केंद्र वल्लापटनम से घरों के लिए निकले थे लेकिन रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवानों ने उन्हें देखा और इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी।

कुछ मजदूरों ने आरोप लगाया कि चार व्यक्तियों के परिवार को केवल दो किलो गेंहू मिल रहा है और सवाल किया कि ऐसे में वे कैसे गुजारा करें। सुशील कुमार नामक कामगार ने कहा, हम घर जाना चाहते हैं। हम यहां तक कि घर पैदल जाने को तैयार हैं। कामगारों के इन समूहों को पुलिस ने रोका और पूछताछ के बाद शिविरों में वापस भेज दिया। बाद में इन प्रवासी कामगारों को केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों से संबंधित शिविरों में भेजा गया।

इस बीच, जिले के अधिकारियों ने कहा कि कामगारों की शिकायतों पर गौर किया जाएगा। 15 मई तक 29 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से करीब 33 हजार प्रवासी कामगारों को केरल से उनके गृह प्रदेश भेजा गया है।

इंदौर में कर्फ्यू तोड़ सड़क पर उतरी भीड़, खदेड़े गए कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंके

इंदौर (मध्यप्रदेश)। कर्फ्यू के उल्लंघन के मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिए जाने के विरोध में मंगलवार को यहां लोगों का समूह कर्फ्यू तोड़कर सड़क पर उतर आया और पुलिस-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर जुलूस निकाला। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण प्रशासन ने इंदौर की शहरी सीमा में 25 मार्च से कर्फ्यू लगा रखा है। इस बीच, सोशल मीडिया पर सामने एक वीडियो में पुलिस लाठी चार्ज कर लोगों को खदेड़ती दिखाई दे रही है, जबकि बल प्रयोग के दौरान तितर-बितर होकर सड़क पर दौड़ रहे समूह में शामिल तीन व्यक्ति रुक कर पुलिस कर्मियों पर पत्थर चलाते नजर आ रहे हैं। वीडियो के मुताबिक पुलिस पर दूर से एक-एक पत्थर फेंकने के बाद तीनों भाग गए।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि रावजी बाजार क्षेत्र में मोहम्मद यूसुफ नाम के व्यक्ति ने एक कब्रिस्तान में करीब 50 लोगों को शुक्रवार को जमा किया था। इस पर यूसुफ के खिलाफ कर्फ्यू के उल्लंघन को लेकर आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने यूसुफ को जब मंगलवार को हिरासत में लिया, तो उसके समर्थन में कुछ लोग कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए बाहर निकले और रावजी बाजार पुलिस थाने पहुंच गए।

चश्मदीदों के मुताबिक मामले में 100 से ज्यादा लोग सड़क पर उतर गए और उन्होंने पुलिस-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर जुलूस निकाला। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल थीं। पुलिस अधीक्षक महेशचंद्र जैन ने बताया, "हमने इन लोगों को फौरन खदेड़ दिया था और रावजी बाजार क्षेत्र में फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं। मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। उन्होंने बताया कि घटना के वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और इसमें पुलिस कर्मियों पर पत्थर फेंकते दिखाई दिए लोगों की पहचान की कोशिश की जा रही है। जैन ने बताया, वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि ए पत्थर काफी दूरी से फेंके गए थे। इनसे कोई भी पुलिस कर्मी चोटिल नहीं हुआ है।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रावजी बाजार क्षेत्र में लोगों द्वारा कर्फ्यू के उल्लंघन पर संबद्ध धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इससे पहले, शहर के चंदन नगर इलाके में सात अप्रैल को कर्फ्यू का उल्लंघन कर बाहर घूम रहे लोगों ने विवाद के दौरान एक पुलिस आरक्षक पर पथराव किया था। "कोविड-19 योद्धाओं" पर हमले के एक अन्य मामले में टाटपट्टी बाखल में स्वास्थ्य कर्मियों पर एक अप्रैल को पथराव किया गया था जिससे दो महिला डॉक्टरों के पैरों में चोटें आई थीं। यह दल कोरोना वायरस संक्रमण के एक मरीज के संपर्क में आए लोगों को ढूंढने गया था।

नई दिल्ली में कोविड-19 के लॉकडाउन में बड़े मंगल पर कनाट प्लेस स्थित हनुमान मन्दिर में रहा सन्नाटा

महाराष्ट्र के कराड में टमाटर में तिरंगा वायरस की अफवाह के बीच कीमतों में भारी गिरावट के बाद फेंकती किसान।

पवार ने उद्धव को अर्थव्यवस्था की बहाली के तौर तरीके सुझाए

भाषा। मुम्बई

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति को लेकर लंबी बातचीत की तथा उद्योगों को बहाल करने एवं धीरे धीरे स्थिति सामान्य करके राज्य की अर्थव्यस्था को फिर से पटरी पर लाने के तरीके सुझाए। दोनों नेताओं ने पिछले सप्ताह के आखिर में भी महाराष्ट्र में कोविड-19 की स्थिति तथा उसे नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा की थी जहां कई मंत्री मौजूद थे। मंगलवार की बैठक में पवार ने इस बात पर बल दिया कि कोविड-19 का निकट भविष्य में सफाया नहीं होगा। कोरोना वायरस अब जीवन का हिस्सा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए लोगों को उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जागरूक बनाया जाना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उद्योग अपना कामकाज बहाल करने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि श्रमिक कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते अपने मूल स्थानों को जा चुके हैं। पवार ने कहा कि ऐसे में श्रमिकों की व्यवस्थित वापसी की योजना तैयार करनी चाहिए ताकि महाराष्ट्र में औद्योगिक गतिविधियां फिर शुरू की जा सकें। राज्य में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। पवार ने इस बैठक के बाद ट्वीट किया, (मैंने) राज्य के माननीय मुख्यमंत्री से कोरोना वायरस की रफ्तार से उत्पन्न स्थिति, चुनौतियां, एहतियाती उपायों और विभिन्न वर्गों के लिए किए जाने वाले उपायों पर चर्चा की। मैंने परिवहन, शिक्षा, कृषि, उद्योग जैसे कई मुद्दों पर सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 लॉकडाउन से शैक्षणिक संस्थानों को राजस्व का घाटा हुआ है, जिससे उनके चरमराने की नौबत आ सकती है, ऐसे में यह सुनिश्चित करने के लिए एक अध्ययन दल बनाया जाए कि विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं संस्थानों को नुकसान नहीं हो तथा शिक्षण में विलंब न हो। राकांपा प्रमुख ने औद्योगिक क्षेत्र में बेरोजगार मराठी युवाओं को शामिल करने की योजना तैयार करने का आह्वान किया।

महाराष्ट्र से प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेनों की व्यवस्था पर पवार ने गोयल का आभार जताया

मुंबई। राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को उनके पैतृक राज्यों तक पहुंचाने के लिए ट्रेनों की सुविधा प्रदान करने के उनके आग्रह को स्वीकार करने पर मंगलवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल के प्रति आभार जताया। पवार ने नौ मई को गोयल के समक्ष प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे को उठाया था। राकांपा अध्यक्ष ने तब कहा था कि रेल मंत्री ने लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्यों के मजदूरों को उनके गंतव्यों तक पहुंचाने के लिए ट्रेनों की व्यवस्था करने का भरोसा दिलाया है। राकांपा नेता ने मंगलवार को ट्वीट किया, महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों से प्रवासियों को सुरक्षित उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए ट्रेनें मुहैया कराने के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी और रेल मंत्रालय का शुक्रिया।

क्विक न्यूज

डोडा के पृथक केंद्र से 3,600 से ज्यादा मजदूरों को छुट्टी दी गई

डोडा। जम्मू कश्मीर के डोडा से मंगलवार तक पृथक केंद्रों से 3,600 से ज्यादा मजदूरों को छुट्टी दी गई है। उनमें से कई ने दूरदराज के इलाकों में स्थित अपने गांव पहुंचने के बाद कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता पैदा करने का संकल्प लिया। अधिकारियों ने यहां बताया कि केंद्रशासित प्रदेश के बाहर से आए करीब 2500 लोग अब भी प्रशासन के पृथक केंद्रों में है। भद्रवाह विश्वविद्यालय परिसर से मंगलवार को सुबह 145 कामगारों को छुट्टी दी गई। उनकी जांच रिपोर्ट निगेटिव आई थी। इसके बाद पृथकवास से छुट्टी पाने वाले लोगों की संख्या 3,625 हो गई है। प्रशासन, विशेष रूप से केंद्र में तैनात कर्मचारियो के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मजदूरों ने कहा कि पहले उन्हे पृथकवास में जाने से डर लग रहा था। इसलिए उन्होंने उदासीनता और आक्रामक तरीके से व्यवहार किया, जिसके लिए उन्होंने माफी मांगी।भद्रवाह परिसर में कोविड केयर वेलनेस केंद्र के नोडल अधिकारी आरिफ हलीम खतीब ने कहा कि एक व्यक्ति ने इमारत की छत पर चढ़ कर खुदकुशी करने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि आज यही व्यक्ति रो रहा था और उसने कोरोना योद्धा बनने का संकल्प लिया। मेरे ख्याल से यह हमारे स्टाफ की उपलब्धि है।

आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सीआरपीएफ जवान घायल

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के नवाकदाल इलाके में मंगलवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियो के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बल के दो जवान घायल हो गए।पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया,जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई।पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान और कश्मीर पुलिस का एक कर्मी घायल हो गया।उन्होंने बताया कि मुठभेड़ देर रात करीब दो बजे शुरू हुई और उसके बाद करीब पांच घंटे तक कोई गोली नही चली। इसके बाद सुबह करीब आठ बजे एक बार फिर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो हुई।उन्होंने बताया कि एहतियात के तौर पर शहर में बीएसएनएल पोस्टपेड सेवा को छोड़ कर सभी मोबाइल इंटरनेट और सभी मोबाइल टेलीफोन सेवाएं बंद कर दी गई है। कश्मीर जोन पुलिस ने पहले ट्वीट किया था, श्रीनगर के नवाकदाल इलाके के कनेमजार में मुठभेड़ शुरू। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। विस्तृत जानकारी का इंतजार। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ जारी है और विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

अम्फान से जुड़े राहत अभियानों में शामिल हों भाजपा कार्यकर्ता: नड्डा

भाषा। नई दिल्ली

भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मंगलार को पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे महा चक्रवात अम्फान से प्रभावित होने वाले राज्यों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत से जुड़े अभयानों में शामिल हों तथा स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर काम करें। नड्डा ने एक बयान में कहा उन्होंने कि ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से राहत अभियान से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की।

उन्होंने कहा, महाचक्रवात अम्फान ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय को लेकर गृह मंत्रालय और एनडीएमए के साथ चर्चा की है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सभी भाजपा कार्यकर्ता प्रशासन के साथ तालमेल करके लोगों की सहायता करें। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण-दक्षिण पश्चिम दीघा से 670 किलोमीटर दूर स्थित यह चक्रवात उत्तरपश्चिम बंगाल की खाड़ी के पास उत्तर-उत्तरपूर्व दिशा की तरफ बढ़ेगा और बुधवार को अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान का रूप लेकर पश्चिम बंगाल-बांग्लादेश के तटों से टकराएगा।

छिंदवाड़ा में कमलनाथ व उनके सांसद बेटे के लापता होने के पोस्टर लगे

भाषा। छिंदवाड़ा

कोविड-19 के लिए लगे देशव्यापी लॉकडाउन के बीच मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ एवं उनके सांसद बेटे नकुलनाथ के लापता होने के पोस्टर लगे हैं और उनके इस गढ़ में इन दोनों नेताओं को लाने वाले व्यक्ति को 21,000 रूपए इनाम देने का ऐलान किया गया है।

मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से विधायक हैं, जबकि उनके बेटे नकुलनाथ वर्ष 2019 से छिंदवाड़ा लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। छिंदवाड़ा शहर के विभिन्न स्थानों पर इन दोनों नेताओं की फोटो लगे पोस्टरों में लिखा है, गुमशुदा की तलाश। छिन्दवाड़ा के विधायक एवं सांसद को इस संकट काल में छिन्दवाड़ा की जनता ढूंढ रही है। जो इन्हें छिंदवाड़ा लेकर लाएगा, उसे 21,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। साथ ही इन पोस्टरों में बॉलीवुड फिल्म दुश्मन का गाना लिखा है, चिट्ठी ना कोई सन्देश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। पोस्टर के सबसे नीचे लिखा है, प्रकाशक समस्त मतदाता छिंदवाड़ा विधानसभा एवं लोकसभा। इन पोस्टरों को मंगलवार सुबह देखने के बाद स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता छिन्दवाड़ा स्थित कोतवाली पुलिस थाने पहुंचे और वहां थाना प्रभारी विनोद कुशवाह को ज्ञापन देकर दोषियों के खिलाफ उचित कार्वाई करने की मांग की।

वहीं, कोतवाली थाना प्रभारी विनोद कुशवाह ने बताया कि शहर में सांसद और विधायक के पोस्टर लगे हुए हैं जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताते हुए ज्ञापन दिया है। मामले को संज्ञान में लेकर विस्तृत जाँच की जाएगी और नियमानुसार कार्वाई की जाएगी। इसी बीच, भाजपा नेता एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी भाजपा नेता पंकज चतुर्वेदी ने पीटीआईभाषा को भोपाल में बताया, कमलनाथ एवं नकुलनाथ इन दिनों कोरोना वायरस के खतरे के बारे में ढेर सारा ज्ञान तो दे रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इन दोनों नेताओं ने इस महामारी से परेशान लोगों के लिए कुछ काम नहीं किया है। समस्या यह है कि कमलनाथ आजकल कांग्रेस में चल रही अंदरूनी लड़ाई को लड़ने में व्यस्त हैं। इसलिए उन्हें छिन्दवाड़ा जाने का समय ही नहीं है। वे तभी अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं, जब चुनाव होते हैं। वहीं, मध्यप्रदेश कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेन्द्र सलूजा ने कहा, जो भाजपाई कमलनाथ व नकुलनाथ को छिन्दवाड़ा से लापता बता रहे हैं, वो यह बता दें कि इस महामारी में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी कितनी बार गए? कितने भाजपा के केंद्रीय मंत्री अपने इलाकों में गए? उन्होंने कहा, अभी लॉकडाउन चल रहा है। सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। कमलनाथ एवं नकुलनाथ अपने क्षेत्रों में जनता से सम्पर्क में हैं।

हमारे नेताओं के खिलाफ भाजपा का यह कुप्रचार है। सलूजा ने आगे कहा, शिवराज और उनके मंत्री तो प्रदेश के कोरोना वायरस प्रभावित एक भी रेड ज़ोन लि तक में नहीं गए। मालूम हो कि पिछले सप्ताह कांग्रेस मध्यप्रदेश युवक कांग्रेस के प्रवक्ता सैयद सउद्द हसन सहित कुछ कांग्रेस नेताओं ने भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के उनके निर्वाचन क्षेत्र से गायब होने के बारे में सोशल मीडिया फेसबुक में एक पोस्टर गुमशुदा की तलाश लगाया था और कहा कि जो लोग सांसद को भोपाल लेकर आते हैं और उन्हें जनता के काम में लगाते हैं उन लोगों को जनता दिल से शुभकामनाएं देगी।

न्यायालय ने एन-95 मास्क के मूल्य संबंधी याचिका पर केंद्र का जवाब पूछा

भाषा। मुंबई

बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार को एक जनहित याचिका पर जवाब देने को कहा जिसमें एन-95 मास्क की कीमतों पर नियंत्रण का अनुरोध किया गया है। सुचेता दलाल और अंजलि दमानिया द्वारा दाखिल याचिका में दावा किया गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान मास्क की कालाबाजारी रोकने के लिए कीमतों पर नियंत्रण जरूरी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर देसाई ने अदालत को बताया कि अग्रणी मोर्चे पर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी एन-95 मास्क की दिक्कत हो रही है। इसलिए इसकी कालाबाजारी या जमाखोरी को रोकने की जरूरत है।

हालांकि, महाराष्ट्र सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि वह एन-95 मास्क के अधिकतम बिक्री मूल्य को नियंत्रित करने संबंध में पहले ही केंद्र सरकार को पत्र लिख चुकी है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एस एस शिंदे की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह को इस संबंध में केंद्र सरकार से निर्देश लेने और शुक्रवार को अदालत को अवगत कराने के निर्देश दिए। याचिका के मुताबिक आवश्यक वस्तु कानून के तहत एन-95 मास्क को पहले ही जरूरी सामान घोषित किया गया है लेकिन राज्य में इसकी जमाखोरी, कालाबाजारी हो रही है और ज्यादा कीमतों पर इसकी बिक्री की जा रही। इसलिए जरूरी है कि सरकार इसके मूल्य को नियंत्रित करे।

पेज एक का शेष

श्रमिक ट्रेन...

यात्रियों को ही ट्रेन में सवार होने दिया जाए। ट्रेन में सवार होने और सफर के दौरान, सभी यात्रियों को सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा। एसओपी में कहा गया कि आगमन पर यात्रियों को गंतव्य राज्य या केंद्रशासित प्रदेश द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे एक अलग पत्र में उनसे प्रवासी मजदूरों को लाने-ले जाने के लिए रेलवे के साथ करीबी समन्वय कर और विशेष रेलगाड़ियां चलाने को कहा है। साथ ही कहा है कि महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों का खास ख्याल रखा जाए। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रशासनों को भेजे पत्र में कहा कि फंसे हुए कर्मियों के घर लौटने की सबसे बड़ी वजह कोविड-19 का खतरा और आजीविका गंवाने की आशंका है। उन्होंने पत्र में कहा, प्रवासी मजदूरों की चिंताओं को दूर करने के क्रम में, अगर निम्न कदमों को लागू किया जाता है तो मैं आभारी रहूंगा। गृह सचिव ने सुझाव दिया कि राज्यों एवं रेल मंत्रालय के बीच सक्रिय समन्वय के माध्यम से और विशेष रेलगाड़ियों का प्रबंध किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि साफ-सफाई, भोजन एवं स्वास्थ्य की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ठहरने की जगहों की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। भल्ला ने कहा कि बसों एवं ट्रेनों के प्रस्थान के बारे में और अधिक स्पष्टता होनी चाहिए क्योंकि स्पष्टता के अभाव में और अफवाहों के चलते श्रमिकों में बेचैनी देखी गई है। प्रवासी श्रमिकों के बीच महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों की खास जरूरतों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारी पैदल चल रहे मजदूरों को ठहरने के निर्धारित स्थानों पर या परिवहन के माध्यम उपलब्ध कराकर पास के बस अड्डे या रेलवे स्टेशन तक भेज सकते हैं, प्रवासियों के पते एवं फोन नंबर लिखें जो कि आगे संपर्कों का पता लगाने में मददगार साबित हो सकते हैं तथा ठहरने के स्थानों पर एनजीओ के प्रतिनिधियों को काम पर लगाया जा सकता है। भल्ला ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों या एनजीओ कर्मियों द्वारा ठहरने के स्थान पर लंबे समय तक पृथक-वास के लिए रोके जाने संबंधी धारणा को खत्म करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। प्रवासियों के परिवहन के लिए बसों की संख्या बढ़ाने का भी सुझाव दिया गया। गृह सचिव ने कहा कि इसके अलावा अंतरराज्यीय सीमा पर प्रवासी मजदूरों को ले जा रही बसों को जाने की अनुमति दी जाए, श्रमिक जहां हैं उन्हें वहीं रोकने के लिए खाने, स्वास्थ्य सुविधाओं एवं काउंसलिंग की व्यवस्था की जाए। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रशासनिक अधिकारियों को जहां जरूरत हो, वहां रेलवे से और ट्रेनें चलाने का अनुरोध करने का निर्देश देने को कहा और यह सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी प्रवासी मजदूर को अपने गंतव्य तक पहुचंने के लिए सड़कों या रेल की पटरियों पर पैदल न चलना पड़े। इस बीच, रेलवे ने मंगलवार को कहा कि ऐसी ट्रेनों के परिचालन के लिए गंतव्य राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं है। एसओपी जारी होने के कुछ घंटे बाद रेलवे के प्रवक्ता राजेश दत्त बाजपेई ने कहा, 'श्रमिक विशेष ट्रेनों को चलाने के लिए उन राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है जहां यात्रा समाप्त होनी है।' अधिकारियों ने कहा कि रेलवे को अगले सप्ताह में ऐसी 300 ट्रेन चलाए जाने और शेष प्रवासी श्रमिकों को उनके घर पहुंचाए जाने की उम्मीद है। गौरतलब है कि गत एक मई से रेलवे ने 1,565 प्रवासी श्रमिक ट्रेनों का परिचालन किया है और 20 लाख से अधिक प्रवासियों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाया है।

सड़कों-हाईवे...

को सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक, हादसों में 180 प्रवासी मजदूरों की मौत हुई और 694 गंभीर रूप से जख्मी हुए। इसी पूरे हुए एक अध्ययन के मुताबिक, पिछले दो महीनों में एक सड़क दुर्घटना में मरने वालों का आंकड़ा कोरोना संक्रमण के मुकाबले दस गुना ज्यादा घातक साबित हुआ है। पिछले दो माह के दौरान सड़क हादसों में हुई मृत्यु दर 32 फीसदी रही जो कि 2019 में 30 फीसदी थी। सड़क और राजमार्ग सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले स गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) और अन्य संगठनों ने प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की मांग की है जिनमें वाहनों के लिए प्रतिबंधित समर्पित लेन की पहचान करना भी शामिल है। सुरक्षा विशेषज्ञों ने किओस्क, खाने-पीने व चिकित्सा सुविधाओं समेत मोटर वाहन प्रणाली की तैनाती पर भी जोर दिया है ताकि बूढ़ों- बच्चों व अन्य जरूरतमंद लोगों को कुछ दूरी तक पहुंचाया जा सके। तात्कालिक आधार पर पूरी की जाने वाली उनकी सबसे महत्वपूर्ण मांग लंबी दूरी के हाईवे और सड़कों पर केवल प्रशिक्षित चालकों को ही वाहन चलाने की अनुमति देना है। इसके अलावा विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि स्पीड सीमा के उल्लंघन होने पर वाहन मालिकों और चालकों के खिलाफ महामारी कानून एवं मोटर वाहन कानून के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। सेव लाइफ फाउंडेशन के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी (सीईओ) पीयूष तिवारी ने बताया कि पैदल यात्रियों को मौत की नींद सुलाने वाले सड़क हादसों के पीछे चालकों का थका होना और वाहनों की तेज रफ्तार मुख्य वजह हैं। सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों के रोड सेफ्टी नेटवर्क ने केंद्रीय सड़क परिवहन-राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को अपनी सिफारिशों का पुलिंदा सौंप दिया है। इसमें मांग की गई है कि लॉकडाउन पूरी तरह खत्म होने तक देश भर की सभी सड़कों पर पैदल यात्रियों व साइकिल सवारों के लिए तत्काल अस्थायी लेन चिह्नित की जाएं। अराइव सेफ के हरमन सिंह सिद्धू गडकरी से आग्रह किया है कि वे जितनी जल्द संभव हो उतनी जल्दी एक लेन को वाहन मुक्त घोषित करने के निर्देश जारी करें।

देश में...

में 138, उत्तर प्रदेश में 118, तमिलनाडु में 81 और आंध्र प्रदेश में 50 लोगों की मौत हुई है। वहीं, कर्नाटक और पंजाब में मृतक संख्या 37-37 और तेलंगाना में 35 हो गई है। जम्मू-कश्मीर में बीमारी के कारण 15 लोगों की जान गई है। हरियाणा में 14 जबकि बिहार में नौ और केरल तथा ओडिशा में चार-चार लोगों की मौत हुई है। झारखंड, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में तीन-तीन लोगों की जबकि असम में दो लोगों की मौत हुई है। मंत्रालय की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार मेघालय, उत्तराखंड और पुडुचेरी में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, 70 प्रतिशत से अधिक मौतें मरीजों में पहले से मौजूद अन्य बीमारियों के चलते हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह तक अद्यतन डेटा के मुताबिक देश में संक्रमण के सर्वाधिक 35,058 मामले महाराष्ट्र में हैं। इसके बाद 11,760 मामले गुजरात में, 11,745 मामले तमिलनाडु में, दिल्ली में 10,054, राजस्थान में 5,507, मध्य प्रदेश में 5,236 और उत्तर प्रदेश में 4,605 मामले हैं। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के मामले बढ़कर 2,825, आंध्र प्रदेश में 2,474 और पंजाब में 1,980 हो गए हैं।

सड़क हादसों...

गई। इस दुर्घटना की पुष्टि करते हुए भागलपुर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) सुजीत कुमार ने दुर्घटना स्थल से नौ शव निकाले गए हैं। पुलिस की प्रारंभिक छानबीन में पता चला है कि प्रवासी मजदूर कटिहार की ओर से कहीं से लोहे की छड़ों से लदे ट्रक में सवार हो गए थे। एक दिन पहले सोमवार को भी बिहार में अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में छह प्रवासी मजदूर मारे गए। इसके अलावा, महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में मंगलवार की तड़के ट्रक की चपेट में आने से तीन प्रवासी मजदूरों और एक बस चालक की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। एडिशनल एसपी नुरुल हसन ने बताया कि कोल्हान गांव में यह दुर्घटना तड़के करीब साढ़े तीन बजे हुई जब बस सोलापुर से नागपुर रेलवे स्टेशन जा रही थी, जहां मजदूर झारखंड में अपने मूल स्थानों तक पहुंचने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सवार होने वाले थे। उत्तर प्रदेश के महोबा में टायर फ्टने से मिनी ट्रक पलट गया। हादसे में तीन महिलाओं की मौत हो गई और 17 लोग घायल हो गए। महोबा के पुलिस अधीक्षक एमएल पाटीदार ने कहा कि घटना सोमवार देर रात उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के कमलपुरा गांव में उस समय हुई जब मिनी ट्रक मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक कोल्हू से सामग्री ले जा रहा था। सभी 22 श्रमिक दिल्ली से आ रहे थे।

मुंबई ने...

धरी की धरी रह जा रही हैं। एक दिन पहले ही सोमवार को गाजियाबाद के रामलीला मैदान में भी हजारों की संख्या में श्रमिक ट्रेनों से घर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने पहुंच गए थे। आज दिल्ली के पचकुइंया तथा गाजीपुर बॉर्डर पर भटक रहे श्रमिकों की भारी भीड़ देखी गई। उधर, हरियाणा के यमुनानगर के मानकपुर लक्कड़ मंडी में जिला प्रशासन ने यूपी व बिहार के सैकड़ों मजदूरों को रोका हुआ है। मंगलवार को फिर से मजदूरों के सब्र का बांध टूट गया और वे घर जाने की मांग करते हुए यमुनानगर के पौंटा साहिब नेशनल हाईवे पर आ गए। उन्होंने 20 मिनट हाइवे जाम रखा। इस दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया, जिसके बाद हाईवे खोला जा सका। यमुनानगर से यूपी की सीमा लगती है। पंजाब से आए बहुत से प्रवासी पैदल यूपी में प्रवेश करने के लिए यमुनानगर पहुंच रहे हैं। बांद्रा में दोपहर तक स्टेशन के बाहर अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ था। पुलिस लगातार लोगों से घर जाने की अपील कर रही थी। स्टेशन पर पहुंचे लोगों में बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चे भी थे। रेलवे ने कहा कि लेकिन कई ऐसे लोग स्टेशन के समीप रोड और पुल पर इकट्ठा हो गये जिन्होंने पंजीकरण नहीं कराया था और जिन्हें अधिकारियों ने ट्रेन से जाने के लिए नहीं बुलाया था। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी रवींद्र भाकर ने कहा, 'राज्य मशीनरी द्वारा पात्र यात्रियों को चेक किया गया और उन्हें ट्रेन में सवार होने दिया गया। ट्रेन करीब 12 बजे उन 1700 श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को लेकर बांद्रा टर्मिनल से रवाना हुई जो इस यात्रा के हकदार थे।' रेलवे के अधिकारी के अनुसार स्टेशन के बाहर जुटी भीड़ को पुलिस ने वहां से हटा दिया। एक महीने पहले भी मुंबई के बांद्रा स्टेशन के बाहर हजारों लोग जुटे थे और घर भेजने की मांग करने लगे थे। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज कर लोगों को भगाना पड़ा था। इस मामले में भीड़ को उकसाने के आरोप में एक पत्रकार समेत 6 लोगों पर केस भी दर्ज हुआ था। राज्य में 20 लाख ऐसे मजदूर हैं, जो अपने गृह राज्य जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चित बंगाल के हैं। अब तक करीब 3 लाख मजदूरों को महाराष्ट्र सरकार ने उनके राज्यों में भेजा है। उन मजदूरों का कोई रिकॉर्ड नहीं है जो निजी वाहन से या पैदल चले गए हैं। इसकी पुष्टि राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख की ओर से की गई है। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जनता से अपील की है कि वे संक्रमित होकर अपने गांव-घर न जाएं।

चक्रवाती तूफान...

उसके बगल में पूर्वी-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर प्रति घंटे 240 से 250 किलोमीटर की रफ्तार वाली तूफानी हवाओं की स्थिति बन रही है। विभाग ने पश्चिम बंगाल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और आगाह किया है कि कोलकाता, हुगली, हावड़ा, दक्षिण और उत्तर 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर जिलों में बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि कई स्थानों पर रेल एवं सड़क मार्ग बाधित हो सकते हैं, बिजली एवं संचार के खंभे उखड़ सकते हैं और सभी प्रकार के कच्चे घरों को अत्यंत नुकसान होगा। मौसम विभाग ने तैयार फसलों, बाग-बगीचों को भारी नुकसान होने की आशंका जताई है।

उप्र कांग्रेस...

उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। एसपी ग्रामीण (पश्चिम), आगरा रवि कुमार ने समाचार एजेंसी को बताया कि दोनों नेता बिना अनुमति बसों को आगे ले जाने की जिद पर अड़े थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। मंगलवार को आगरा में उत्तर प्रदेष कांग्रेस के प्रमुख लल्लू और अन्य पार्टी नेताओं-कार्यकर्ताओं ने आगरा में राजस्थान सीमा पर ऊंचा नंगला इलाके में धरना-प्रदर्शन किया था। यहां उन्होंने दावा किया कि प्रशासन उनकी 500 बसों को नोएडा-गाजियाबाद जाने की इजाजत नहीं दे रहा है। यहां घंटों चले हंगामे के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को हिरासत में ले लिया गया। इससे पहले, इस मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा व उत्तर प्रदेष सरकार के बीच बड़ी राजनीतिक जंग छिड़ गई, क्योंकि प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार को पत्र लिखा था कि आगरा प्रशासन बसों को शहर में प्रवेश करने और नोएडा/गाजियाबाद की यात्रा करने की अनुमति नहीं दे रहा है। कांग्रेस ने दावा किया कि उसने 1000 बसों की पेशकश की है, ताकि फंसे हुए प्रवासी कामगारों को उनके संबंधित गांव/घर और कस्बों तक पहुंचाया जा सके। उधर, उत्तर प्रदेश भाजपा और योगी सरकार ने दावा किया है कि कांग्रेस द्वारा साझा की गई बसों की सूची में बाइक, ऑटो-रिक्शा, ट्रैक्टर और यहां तक कि कारों के नंबर शामिल हैं। यह सरासर धोखा है। सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि बसों का ब्योरा मांगने के बावजूद कांग्रेस ने चार दिन तक यूपी सरकार को सूची नहीं सौंपी। मंगलवार को राज्य सरकार ने कांग्रेस से गाजियाबाद और नोएडा में 500 बसें भेजने को कहा, लेकिन गलत जानकारी पेश की गई। हालांकि, प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्य सरकार को पत्र लिखा और दावा किया कि बसों को आगरा से नोएडा या गाजियाबाद तक नहीं जाने दिया जा रहा है। इस संबंध में योगी सरकार और प्रियंका गांधी के बीच कई खत लिखे जाने और उनके जवाब दिए जाने की बात सामने आई और इस राजनीति बढ़ती गई, लेकिन मजदूरों की समस्या जस की तस बरकरार है।

सपा नेता...

सुनील कुमार (28) की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि इस मामले में दिवाकर के बेटे सचिन की तहरीर पर सर्मेंद्र, जितेंद्र, रामेंद्र, उपेन्द्र, ज्ञानेंद्र, गजेन्द्र तथा दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनमें से जितेंद्र और सर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के वीडियो में ये दोनों राइफल लिए देखे गए हैं। पुलिस ने दोनों राइफल भी बरामद कर ली हैं। प्रसाद ने बताया कि बाकी आरोपियों को पकड़ने को पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं। दिवाकर वर्ष 2017 में चंदौसी विधानसभा सीट से सपा के उम्मीदवार थे, मगर इसी दौरान गठबंधन होने से यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई थी।

उधर खुला...

कर दिल्ली से नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव आदि षहरों को जाने वाले वाहन चालकों ने भी बढ़ाई। जांच का काम सख्ती से हुआ तो वाहन रुकते चले गए। पुलिस ने मंगलवार सुबह ट्वीट कर कहा कि नोएडा में बिना ई-पास प्रवेष नहीं कर सकते, इसलिए बिना पास वाले लोग डीएनडी, कालिंदी कुंज या सेक्टर 15 प्रवेष द्वार की तरफन आएं, लेकिन षाम तक जाम से निजात नहीं मिली। कई जगह वाहनों की एक किलोमीटर से भी लंबी लाइनें लग गईं। आईटीओ से लक्ष्मी नगर की तरफ जाने वाले मार्ग के पास यमुना पुल पर वाहनों की जांच के लिए पुलिस ने बैरिकेड लगाए हुए थे। इन बैरिकेड से होकर एक समय में एक वाहन निकल सकता था। वाहन पास की जांच किए जाने से और वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण यमुना पुल पर वाहनों की रफ्तार थम गई। ऐसे में जाम लगना शुरू हो गया था। हालत यह रही कि यमुना पुल से लेकर विकास मार्ग पर आइटीओ की रेड लाइट तक वाहनों की कतार लग गई। यही हाल डीएनडी समेत अन्य बॉर्डर सड़कों का रहा। वाहनों के जाम, बाजारों में दुकानों पर भीड़ देख मंगलवार को सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोग सब्र और समझदारी से काम लें। यदि नियमों का पालन नहीं करेंगे तो घातक कोरोना घरों तक आ जाएगा।

बेटी के पिता बने बोल्ट

किंग्स्टन। जमैका के महान फर्राटा धावक उसेन बोल्ट पहली बार पिता बन गए है। उनकी पार्टनर केसी बेनेट ने बेटी को जन्म दिया है। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने सोशल मीडिया पर बोल्ट को बेटी के जन्म के लिए बधाई दी। होलनेस ने ट्विटर पर लिखा, हमारे महान फर्राटा धावक उसेन बोल्ट और केसी बेनेट को बेटी के जन्म पर बधाई। स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार इस जोड़े की बेटी का जन्म रविवार को हुआ। इसके अलावा अन्य जानकारी अभी उपलब्ध नही है। तैंतीस साल के बोल्ट ने मार्च में सोशल मीडिया पर खुलासा किया था कि बेनेट बेटी को जन्म देने वाली हैं।

वित्तीय परेशानी झेल रही लंबी दूरी की धावक प्राजक्ता को मिली मदद

नागपुर। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के कारण बेहद ही खराब वित्तीय स्थिति का सामना कर रही लंबी दूरी की भारतीय धावक प्राजक्ता गोडबोले को आखिर राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी से मदद मिली। प्राजक्ता की परेशानी की खबर पीटीआई-भाषा ने जारी की थी। चौबीस साल की प्राजक्ता नागपुर में सिरासपेठ झुग्गी में अपने माता-पिता के साथ रहती है। उनके पिता लकवाग्रस्त है जबकि लॉकडाउन के कारण उनकी मां बेरोजगार हो गई है।

चेरिटी के लिए फुटबॉल मैच खेलेंगे मैड्रिड, बायर्न और इंटर मिलान

मैड्रिड। रीयाल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख और इंटर मिलान इटली और स्पेन में चिकित्सा सुविधाओं के लिए पैसा जुटाने के इरादे से अगले साल मैत्री फुटबॉल मैचों की श्रृंखला खेलेंगे। तीन राउंड रोबिन मैचों को यूरोपियन सोलिडेरिटी कप नाम दिया गया है और कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहे हजारों चिकित्साकर्मियों और सहयोगियों को इन मैचों के टिकट मिलेंगे।

लॉकडाउन के दौरान तकनीकों से रूबरू हुए हॉकी खिलाड़ी

बेंगलुरू। भारतीय महिला और पुरूष हॉकी टीमें सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कई नई तकनीकें सीख गई है जिनकी जरूरत उन्हें कोरोना लॉकडाउन के दौरान इंडोर अभ्यास में पड़ रही है। दोनों टीमें यहां भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र में है चूंकि मार्च से ही देशव्यापी लॉकडाउन के कारण खेल बंद है।

मैनचेस्टर ने प्रशंसकों से स्टेडियमों से दूर रहने को कहा

लंदन। मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रीमियर लीग के मैच बहाल होने पर अपने प्रशंसकों को स्टेडियमों से दूर रहने को कहा है। क्लब बुधवार से छोटे समूहों में अभ्यास शुरू करेगा।

थ्रोडाउन विशेषज्ञ की सीख से हम तेज गेंदबाजी के खिलाफ बेहतर हुए : कोहली

भाषा। नई दिल्ली

● डी राघवेंद्र की साइडआर्म से थ्रो करते हुए 150-155 किमी प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार हासिल करने से बल्लेबाजी सुधरी

भारतीय कप्तान विराट कोहली का मानना है कि थ्रोडाउन विशेषज्ञ डी राघवेंद्र की साइडआर्म से थ्रो करते हुए 150–155 किमी प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार हासिल करने से भारतीय बल्लेबाजों को हाल के वर्षों में तेज गेंदबाजी के खिलाफ सुधार करने में काफी मदद मिली। साइडआर्म एक क्रिकेट उपकरण है जो लंबे चम्मच की तरह होता है और इसके एक हिस्से को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि इससे गेंद को पकड़ा जाए और तेज गति से फेंका जाए। कोहली ने बांग्लादेश के स्टार बल्लेबाज तमीम इकबाल से इंस्टाग्राम लाइव सत्र के दौरान कहा, मेरा मानना है कि इस भारतीय टीम ने 2013 से तेज गेंदबाजी का सामना करते हुए जो सुधार दिखाया है वह रघु (राघवेंद्र) के कारण है। उन्होंने कहा, खिलाड़ियों के फुटवर्क, बल्ले की मूवमेंट को लेकर उसे अच्छी समझ है। उसने अपने कौशल में इतना इजाफा किया है कि साइडआर्म के साथ आसानी से 155 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंक सकता है। नेट पर रघु का सामना करने के बाद जब आप मैच में जाते हो तो आपको महसूस होता है कि गेंद खेलने के लिए आपके पास काफी समय है। यह हैरानी भरा नहीं है कि राघवेंद्र वर्षों से भारतीय क्रिकेट टीम के सहयोगी स्टाफ के अहम सदस्य हैं। कोहली ने कहा कि वह कभी भी अपने ऊपर संदेह नहीं करते और बेहद दबाव भरे अंतरराष्ट्रीय मैचों में बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भी ऐसा ही होता है। भारतीय कप्तान ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैच के दौरान मैं कभी अपने ऊपर संदेह नहीं करता। प्रत्एक व्यक्ति की कमजोरियां होती हैं। नकारात्मक पक्ष होते हैं। इसलिए दौरों पर अभ्यास के दौरान अगर आपका सत्र अच्छा नहीं रहा तो आपको लगता है कि आप लय में नहीं हो। लक्ष्य का पीछा करने में माहिर कोहली ने कहा कि बचपन में भारतीय टीम के मैचों को देखकर वे सोचते थे कि वह टीम की जीत में मदद कर सकते थे। ईमानदारी से कहूं तो जब मैं बच्चा था और भारतीय टीम के मैच देखता था तो उनके हारने के बाद सोते सामय सोचता था कि मैं मैच जीत दिला सकता था। अगर मैं 380 रन के लक्ष्य का पीछा कर रहा हूं तो मैं कभी महसूस नहीं करता कि इसे हासिल नहीं किया जा सकता। 2011 में होर्बाट में क्वालीफाई करने के लिए हमें 40 ओवर में 340 रन बनाने थे। ब्रेक के समय मैंने सुरेश रैना से कहा कि इस मैच को हम दो बीस ओवर के मैच की तरह लेंगे। 40 ओवर लंबा समय है। पहले 20 ओवर खेलते हैं और देखते हैं कि कितने रन बनते हैं और फिर दूसरा टी20 मैच खेलते हैं। खेल के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक कोहली ने कहा कि अपनी जरूरतों के अनुसार उन्हें बल्लेबाजी के प्रति अपने रवैया में बदलाव लाना पड़ा जिसमें गेंद को हवा में मारने की जगह जमीनी शॉट खेलना शामिल है।

खिलाड़ियों को इंग्लैंड दौरे के लिए बाध्य नही करेंगे : होल्डर

लंदन। वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर ने कहा है कि वह कोविड–19 महामारी के बीच अपने खिलाड़ियो को तीन टेस्ट मैचों के इंग्लैंड के दौरे पर जाने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। वेस्टइंडीज को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चार जून से इंग्लैंड में टेस्ट श्रृंखला खेली थी लेकिन कोरोना वायरस महामारी के फैलने के कारण इस श्रृंखला को स्थगित करना पड़ा। इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) को हालांकि उम्मीद है कि वे जुलाई में इस श्रृंखला को आयोजित करके अपना सत्र शुरू कर सकते हैं। होल्डर ने बीबीसी रेडियो फाइव से कहा, कोई भी कदम उठाने हुए प्रत्एक खिलाड़ी को सहज होना चाहिए। स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर हमें इंग्लैंड में खेलने जाना है तो ऐसा करना सुरक्षित होना चाहिए। मेरे नजरिए से देखा जाए तो निश्चित तौर पर मैं किसी को भी कहीं भी जाने के लिए बाध्य नहीं करूंगा।

विश्वास सबसे बड़ी बात है, खिलाड़ियों को कोचों से असुरक्षा पर बात करने में मदद मिलती है : बांगड़

नई दिल्ली। भारत के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगड़ का कहना है कि कोचों और खिलाड़ियो के बीच मजबूत रिश्ते के लिए आपसी विश्वास का होना बेहद जरूरी है ताकि खिलाड़ी अपनी असुरक्षाओ पर कोचो से बात कर सकें। उन्होंने स्टार स्पोर्टस पर क्रिकेट कनेक्टेड शो मे कहा , विश्वास बहुत जरूरी है। मानसिक अनुकूलन कोच हो सकता है या तकनीकी कोच। कोच और खिलाड़ी के बीच ऐसा संबंध होना चाहिए कि खिलाड़ी अपनी असुरक्षाओं पर कोच से बात कर सके और उसे इत्मीनान रहे कि कोच उन दोनों की बात को बाहर नही जाने देगा। मानसिक अनुकूलन कोचों के बारे में उन्होंने कहा , कोच मानसिक अनुकूलन का भी काम करते है क्योंकि वे खिलाड़ियों के साथ काफी समय बिताते है और खिलाड़ी उन पर भरोसा करते है। बांगड़ 2014 से 2019 के बीच भारत के बल्लेबाजी कोच रहे।

घरेलू अंपायरों के इस्तेमाल की सिफारिश से भारतीय मैच अधिकारियों की बढ़ेगी चुनौती

नई दिल्ली। आईसीसी (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) क्रिकेट समिति ने कोविड -19 महामारी को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय मैचों में घरेलू अंपायर रखने की सिफारिश की है जो भारतीय मैच अधिकारियो के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। देश के कई मौजूदा और पूर्व मैच अधिकारियों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय मैचों खासकर टेस्ट मैच में कम अनुभव के कारण यह भारत के घरेलू अंपायरों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। पिछले साल आईसीसी के एलीट पैनल के अंपायरों से भारतीय अंपायर एस रवि को बाहर कर दिया गया। इसके बाद इसमे कोई भी भारतीय अंपायर नही है। टेस्ट मैच के लिए अंपायरों को इसी सूची से चुना जाता है। इससे नीचे की श्रेणी मे आने वाले आईसीसी के अंतरराष्ट्रीय पैनल के अंपायरों में चार भारतीय है जिसमें से सिर्फ नितिन मेनन (तीन टेस्ट , 24 एकदिवसीय और 16 टी 20 अंतरराष्ट्रीय) के पास टेस्ट मैचों का अनुभव है। इनके अलावा सी शमशुद्दीन (43 एकदिवसीय , 21 टी 20 अंतरराष्ट्रीय), अनिल चौधरी (20 एकदिवसीय , 20 टी 20 अंतरराष्ट्रीय) और वीरेन्द्र शर्मा (दो एकदिवसीय और एक टी 20) को टेस्ट मैचों का अनुभव नही है। अनुभव नही होने के बाद भी ए अंपायर जनवरी मे इंग्लैड के खिलाफ घरेलू टेस्ट श्रृंखला मे अंपायरिंग कर सकते है। दो टेस्ट और 34 एकदिवसीय में अंपायरिंग करने वाले पूर्व अंतरराष्ट्रीय अंपायर हरिहरन ने पीटीआई - भाषा को बताया , यह एक बड़ी चुनौती है , लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा अवसर है। विभिन्न प्रारूप मे अलग - अलग तरह का दबाव होता है। टेस्ट में पास के क्षेत्ररक्षकों द्वारा दबाव बनाया जाता है जबकि सीमित ओवरों के क्रिकेट में दर्शकों का शोरगुल अंपायरों के काम को मुश्किल बनाता है। सिर्फ अंपायरिंग फैसले ही नही , आक्रामक अपील और खराब रोशनी जैसी अन्य चीजे मुश्किल स्थिति पैदा कर सकती है। ऐसे मे तटस्थ अंपायरों को स्थानीय अंपायरों की तुलना में निष्पक्ष फैसला लेने की संभावना अधिक होती है। मैचों में दो तटस्थ अंपायरों को रखने का नियम 2002 से लागू हुआ था। इससे पहले 1994 से लेकर 2001 तक एक स्थानीय और एक तटस्थ अंपायर रहता था। आईसीसी, स्थानीय एलीट और अंतरराष्ट्रीय पैनल के रेफरी और अंपायरो मे से नियुक्ति करेगी। जिस देश मे एलीट पैनल के मैच अधिकारी नही है वहां अंतरराष्ट्रीय पैनल के मैच अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। भारत में सिर्फ जवागल श्रीनाथ एलीट पैनल के मैच रेफरी है जबकि इस सिफारिश को मंजूरी मिलने के बाद अनिल चौधरी , शम्सुद्दीन और नितिन मेनन स्वदेश मे टेस्ट मैचों में अंपायरिंग कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय समिति के एक मौजूदा अंपायर ने कहा कि सिर्फ घरेलू मैचों में अंपायरिंग करने से उनका काम मुश्किल होगा लेकिन वह इस चुनौती का लुत्फ उठाऐंगे।

भारतीय टीम में चयन से पहले द्रविड़ भाई की बातों से मेरी हिम्मत बनी रही : मयंक

बेंगलुरू। लंबे समय तक इंतजार के बाद भारतीय टीम में जगह बनाने वाले मयंक अग्रवाल ने कहा कि महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ की प्रेरणास्पद बातो ने नकारात्मक विचारों को उनके जेहन में फटकने भी नही दिया। मयंक ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ 2018-19 की श्रृंखला में मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर टेस्ट क्रिकेट मे पदार्पण किया। उसने ईएसपीएन क्रिकइन्फो पर संजय मांजरेकर को एक वीडियोकास्ट में कहा , मै रन बना रहा था। रणजी सत्र और भारत ए के लिए भी काफी रन बनाए थे।मैने राहुल भाई से बात की। मैने बताया कि टीम मे नही चुने जाने से निराश हो रहा हूं। मुझे अच्छे से याद है कि उन्होंने कहा था कि मयंक ए चीजे तुम्हारे हाथ मे नही है। तुमने मेहनत की और यहां तक पहुंचे। चयन तुम्हारे हाथ में नही है। मै पूरी तरह से उनसे सहमत हूं। ए बातें सैद्धांतिक रूप से समझ मे तो आती है लेकिन व्यवहारिक तौर पर इन्हे समझना मुश्किल होता है। उन्होने कहा था कि आने वाला समय पिछले से अलग नही होगा। अगर नकारात्मक सोच के साथ खेलोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। मुझे अभी भी उनकी बात याद है जो मेरे लिए प्रेरणा बनी। जब मै टीम मे चुना गया तो इतना खुश था। मैने उन्हे फोन करके धन्यवाद दिया।

आईओसी ने महासंघों को ओलंपिक क्वालीफाइंग टूर्नामेंटों की तारीख तय करने को कहा

भाषा। लुसाने

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने सभी अंतरराष्ट्रीय महासंघों से तोक्यो ओलंपिक के क्वालीफायर टूर्नामेंटों की तारीखों को अंतिम रूप देने और कोविड–19 महामारी के बीच टूर्नामेंटों को रद्द करने सहित सभी तरह की संभावनाओं के लिए आपात योजना मसौदा बनाने में मदद करने को कहा है।

पिछले महीने आईओसी ने तोक्यो ओलंपिक के क्वालीफिकेशन समय के लिए 29 जून 2021 की समय सीमा तय की थी। कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल होने वाले तोक्यो ओलंपिक को अगले साल के लिए स्थगित किया गया है। आईओसी ने 15 मई के संवाद में कहा, अंतरराष्ट्रीय महासंघों के कैलेंडर में अनिश्चितता को देखते हुए कुछ प्रतियोगिताओं की तारीखों और स्थान पर अब भी फैसला किया जाना बाकी है, हम आपको पूर्व में ही धन्यवाद देते हैं कि आप प्रतियोगिताओं की तारीख और स्थल की पुष्टि होने पर हमें सूचित करेंगे जिससे कि इन्हें जल्द से जल्द क्वालीफिकेशन प्रणाली में शामिल किया जा सके। आईओसी ने कहा, संशोधित क्वालीफिकेशन प्रणाली बनने पर आईओसी के खेल संचालन मैनेजर आपके साथ मिलकर आपात योजना पर काम करना जारी रखेंगे जिससे कि ओलंपिक क्वालीफिकेशन प्रतियोगिताओं के नहीं होने की स्थिति में इसे लागू किया जा सके। आईओसी को उम्मीद है कि योजना जुलाई तक तैयार कर ली जाएगी। हम चाहते हैं कि जुलाई तक यह योजना तैयार हो जाए और फिर वैश्विक स्थिति के आधार पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि इन आपात योजनाओं को लागू करना जरूरी है या नहीं और इसे पहले से सहमत व्यक्तिगत क्वालीफिकेशन प्रणाली में औपचारिक रूप से शामिल किया जाए या नहीं।

रोनाल्डो जुवेंटस के अभ्यास केंद्र पहुंचे

भाषा। तूरिन

करिश्माई फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो 10 सप्ताह के अंतराल के बाद मंगलवार को इटली के सिरि ए क्लब जुवेंटस के अभ्यास केन्द्र पहुंचे। पुर्तगाल का 35 साल का यह खिलाड़ी खुद ही जीप चलाकर जुवेंटस प्रशिक्षण केन्द्र पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पांच बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर रहे इस खिलाड़ी की यहां पहुंचने के बाद चिकित्सा जांच हुई। चिकित्सा और शारीरिक जांच के बाद वह टीम के अन्य खिलाड़ियों के साथ अभ्यास के लिए पहुंचे। जुवेंटस के खिलाड़ियों ने चार मई को व्यक्तिगत अभ्यास शुरू किया था। इसीदिन रोनाल्डो लॉकडाउन के दौरान पुर्तगाल स्थित अपने घर में समय बिताने के बाद टीम के गृह–शहर तूरिन पहुंचें। वह यहां पहुंचने के बाद दो सप्ताह तक पृथकवास में रहे। रोनाल्डो ने लीग में अपना पिछला मुकाबला आठ मार्च को खेला था। इस मैच में उनके गोल की मदद से टीम ने इंटर मिलान को 2–0 से हराया था। इटली में कोरोना वायरस महामारी की खराब स्थिति के कारण इस मैच के बाद सिरि ए को स्थगित कर दिया गया था। इटली इस महामारी से सबसे बुरी तरह प्रभावित देशों में है जहां कोरोना वायरस के संक्रमण में आने से 32,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। लीग को उम्मीद है कि वे 13 जून से प्रतियोगिता को फिर से शुरू कर पाएंगे लेकिन इतालवी फुटबॉल महासंघ (एफआईजीसी) की नई घोषणा से उसके प्रयासों को झटका ला है। एफआईजीसी ने कहा कि सरकार के दिशानिर्देशों के मुताबिक सिरी ए सहित उसकी सभी प्रतियोगिताएं 14 जून तक निलंबित रहेंगी।

लेवरक्युसेन ने बुंदेसलीगा में ब्रेमेन को हराया

ब्रेमेन। बायर्न लेवरक्युसेन ने बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग में सोमवार को वर्डर ब्रेमेन को 4-1 से हराया जिसके साथ कोरोना वायरस के कारण निलंबन के बाद दोबारा शुरू हुई लीग का पहला दौरा पूरा हुआ। दो महीने के निलंबन के बाद दोबारा शुरू लीग ने तीन दिन में एक दौर के मैच पूरे किए। वर्डर के खाली स्टेडियम मे गोल करने के बाद लेवरक्युसेन के कुछ खिलाड़ी समूह मे एकत्रित हो गए जबकि लीग ने न्यूनतम शारीरिक संपर्क के लिए कड़े दिशानिर्देश जारी किए है। वर्डर की टीम अपने एक खिलाड़ी के बिना उतरी थी जिसे पृथक रखा गया है क्योंकि उसके संपर्क मे आया एक व्यक्ति कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाया गया है। वर्डर ने हालांकि शुक्रवार को कहा था कि खिलाड़ी परीक्षण मे नेगेटिव पाया गया है। मैच के दौरान पहले तीन गोल सिर्फ पांच मिनट के भीतर हुए। केई हावर्ट्ज ने 28वे मिनट में हेडर से गोल दागकर लेवरक्युसेन को बढ़त दिलाई लेकिन वर्डर ने थियोडोर गेबरे के गोल से बराबरी हासिल कर ली। हावर्ट्ज ने इसके बाद फ्री किक पर हेडर से एक और गोल दागकर अपनी टीम को 2-1 से आगे किया। दूसरे हाफ मे मिशेल वाइसर और केरेम डेमेरबे ने एक-एक गोल और दागकर लेवरक्युसेन की 4-1 से जीत सुनिश्चित की।

अमेरिकी कंपनियों को चीन से वापस लाने के लिए कांग्रेस में विधेयक पेश

वाशिंगटन। अमेरिकी कंपनियों को अपने विनिर्माण संयंत्र चीन से वापस अपने देश लाने में मदद के लिए एक प्रभावशाली सांसद ने कांग्रेस मे एक विधेयक पेश किया है। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते आने वाले दिनो में बड़ी संख्या मे अमेरिकी कंपनियां चीन से बाहर निकलेंगी। अमेरिकी सांसद मार्क ग्रीन द्वारा पेश किए गए विधेयक द ब्रिंग अमेरिकन कंपनी होम एक्ट मे इन कंपनियो को वापस लागने की पूरी लागत और चीन आयात पर लगने वाले आयात शुल्क को कवर करने के लिए कहा गया है। ग्रीन ने कहा, हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अमेरिका में निवेश आकर्षित करना जरूरी है। लेकिन अमेरिकी कंपनियों के लिए अपने देश आने मे एक सबसे बड़ी बाधा लागत है। कई कंपनियो के लिए ए बहुत खर्चीला और जोखिम भरा है, खासतौर से वैश्विक आर्थिक अनिश्चिता के दौर मे। चीन ने साफ कर दिया है कि वह भरोसेमंद साझेदार नही है।

सरकारी परियोजनाओं का अनुबंध कार्य पूरा करने की समय सीमा तीन से छह महीने तक बढ़ी

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 संकट को देखते हुए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) समेत सभी सरकारी परियोजनाओ के अनुबंध संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए समयसीमा छह महीने तक बढ़ा दी है। ए वे परियोजनाएं है जिन्हें फरवरी 2020 या उसके बाद पूरी होनी थी। मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला व्यय विभाग ने फरवरी मे कहा था कि चीन में कोरोना वायरस महामारी फैलने को मानवीय नियंत्रण से बाहर आपात स्थिति माना जाएगा। विभाग ने अब उन कंपनियों को राहत दी है जिन्हें केंद्र सरकार से ठेका प्राप्त है। विभाग ने हाल मे एक कार्यालय ज्ञापन मे कहा कि इस संकट से परिवहन, विनिर्माण और वस्तुओ और सेवाओ की आपूर्ति बाधित हुई है। इसमें कहा गया है, लोगों और सामानों की आवाजाही पर गृह मंत्रालय और संबंधित राज्य और केंद्र शसित प्रदेशों की तरफ से समय-समय पर लगाई गई पाबंदियों से अनुबंध बाध्यताओ के तहत वस्तुओं की आपूर्ति, कामकाज और परामर्श सेवा को पूरा करना मुश्किल हुआ है। देश और विदेश मे लॉकडाउन के कारण इन पाबंदियों को देखते हुए सभी पक्षो के लिए अनुबंध संबंधी कार्यों को पूरा करना संभव नही हो सकता है। उसने कहा कि इसीलिए सरकारी विभाग से संबद्ध उन सभी निर्माणाकार्य अनुबंध, वस्तु, सेवा अनुबंध और पीपीपी-अनुबंधों को पूरा करने के लिए कम-से-कम तीन महीने और अधिकतम छह महीने का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है, जिन्हे इस साल फरवरी या उसके बाद पूरा किया जाना था। इसके लिए ठेकेदारा या संबद्ध कंपनियो को कोई जुर्माना नही देना होगा।

चालू वित्त वर्ष में निर्यात में 20 प्रतिशत कमी के आसार: फियो

कोलकाता। भारतीय निर्यात संगठनो के महासंघ (फियो) ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण चालू वित्त वर्ष में देश का निर्यात 20 प्रतिशत घट सकता है। फियो महानिदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अजय सहाय ने कहा कि इस समय परिदृश्य काफी निराशाजनक है और निर्यात में गिरावट के साथ आयात भी घटेगा। उन्होंने कहा, हमारा अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान निर्यात में 20 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है। मूल्य के हिसाब से यह करीब 50 से 60 अरब डॉलर होगा। हालांकि सहाय ने कहा कि इससे व्यापार संतुलन को लेकर कोई खासा दबाव नही होगा क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण निर्यात और आयात दोनों में गिरावट आने का अनुमान है। उन्होंने पीटीआई भाषा से कहा, हालांकि निर्यात में गिरावट के कारण रोजगार सृजन पर असर पड़ेगा और लोगों की नौकरियां जाने का कारण भी बन सकता है। सरकार के प्रोत्साहन पैकेज बारे में सहाय ने कहा कि निर्यातकों को वैश्विक बाजारों में अपनी प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने के लिए और मदद की जरूरत है, क्योंकि चीन अपना उत्पादन भी शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज निर्यात के बारे में एक भी शब्द नही कहा गया है। मात्र एक उपाय किए गए है जिसमें सरकार ने एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) के लिए कर्ज सहायता योजना का लाभ देने का फैसला किया है।

शेयर बाजारों में तीन दिन से जारी गिरावट थमी

● बढ़त के साथ बंद

भाषा। मुंबई

कोविड–19 के संभावित वैक्सीन के सफल परीक्षण से उत्साहित वैश्विक बाजारों के मजबूत संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में तीन दिन से जारी गिरावट का रुख मंगलवार को थम गया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के रुख के साथ बंद हुए। भारती एयरटेल और आईटीसी में अच्छा लाभ दिखा। उतार–चढ़ाव भरे कारोबार में 700 से ज्यादा अंक ऊपर नीचे होने के बाद 30 प्रमुख शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 167.19 अंक यानी 0.56 प्रतिशत बढ़कर 30,196.17 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 55.85 अंक यानी 0.63 प्रतिशत की बढ़त के साथ 8,879.10 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल भारती एयरटेल का शेयर सबसे अधिक लाभ में रहा। कंपनी का शेयर 11 प्रतिशत तक चढ़ गया। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक एयरटेल के प्रति उपयोक्ता औसत राजस्व (एआरपीयू) में बढ़ोत्तरी से उसके शेयर में उछाल देखा गया। ओएनजीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईटीसी, पावरग्रिड और एनटीपीसी में भी अच्छा लाभ रहा। वहीं दूसरी तरफ इंडसइंड बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टुब्रो और भारतीय स्टेट बैंक के शेयर नीचे रहे। सेंसेक्स में शामिल कुल 30 कंपनियों में से 22 के शेयर लाभ में और आठ हानि में रहे। बीएसई पर दूरसंचार कंपनियों के शेयर में सबसे अधिक 10.41 प्रतिशत तक की तेजी देखी गई। इसके बाद प्रौद्योगकी, बिजली, यूटिलिटी और वाहन क्षेत्र में 2.49 प्रतिशत तक की बढ़त रही। मध्यम पूंजी वाली कंपनियों (मिडकैप) 0.52 प्रतिशत और छोटी पूंजी वाली कंपनियों (स्मॉलकैप) सूचकांक में 0.20 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेस में शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, अमेरिका में कोविड–19 वैक्सीन के सफल परीक्षण से दुनियाभर के शेयर बाजारों में उम्मीद जगी है।। भारतीय बाजारों की शुरुआत भी सकारात्मक रही।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 25 पैसे की तेजी के साथ बंद

मुंबई। रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 25 पैसे की तेजी के साथ 75.66 के स्तर (अनंतिम) पर बंद हुआ। कोरोना वायरस की वैक्सीन के शुरुआती परीक्षण में सफलता की खबर से दुनिया भर मे निवेशकों की धारणाएं मजबूत हुईं, जिसका सकारात्मक असर रुपए पर भी देखने को मिला। विदेशी मुद्रा कारोबारियो ने कहा कि कोविड-19 की वैक्सीन के परीक्षण में उत्साहजनक परिणाम के अलावा घरेलू शेयर बाजार में तेजी और विदेश में डॉलर के कमजोर होने से स्थानीय मुद्रा को मजबूती मिली। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 75.71 पर खुला और फिर अमेरिकी मुद्रा के खिलाफ 25 पैसे की बढ़त दर्ज करता हुआ 75.66 के स्तर पर बंद हुआ। रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 75.91 पर बंद हुआ था।

अमेरिकी कंपनियों को चीन से वापस लाने के लिए कांग्रेस में विधेयक पेश

वाशिंगटन। अमेरिकी कंपनियो को अपने विनिर्माण संयंत्र चीन से वापस अपने देश लाने मे मदद के लिए एक प्रभावशाली सांसद ने कांग्रेस मे एक विधेयक पेश किया है। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते आने वाले दिनो में बड़ी संख्या में अमेरिकी कंपनियां चीन से बाहर निकलेंगी। अमेरिकी सांसद मार्क ग्रीन द्वारा पेश किए गए विधेयक द ब्रिंग अमेरिकन कंपनी होम एक्ट मे इन कंपनियो को वापस लागने की पूरी लागत और चीन आयात पर लगने वाले आयात शुल्क को कवर करने के लिए कहा गया है। ग्रीन ने कहा, हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अमेरिका में निवेश आकर्षित करना जरूरी है। लेकिन अमेरिकी कंपनियो के लिए अपने देश आने मे एक सबसे बड़ी बाधा लागत है। कई कंपनियो के लिए ए बहुत खर्चीला और जोखिम भरा है, खासतौर से वैश्विक आर्थिक अनिश्चिता के दौर मे। चीन ने साफ कर दिया है कि वह भरोसेमंद साझेदार नही है। अमेरिका को फिर से विकसित करने और चीन पर निर्भरता कम करने के लिए, आइए हम अवसर के द्वार खोले और हमारे देश मे ही निवेश को प्रोत्साहित करें।

टाटा पावर का शुद्ध लाभ चौथी तिमाही में दो गुना बढ़कर 475 करोड़ रुपए रहा

नई दिल्ली। टाटा पावर का एकीकृत शुद्ध लाभ जनवरी-मार्च तिमाही मे एक साल पहले की इसी तिमाही की तुलना मे दो गुना बढ़कर 475 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने एक बयान मे कहा कि एक साल पहले 2019-20 की इसी तिमाही मे कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ 172 करोड़ रुपए रहा था।

देश में 1,043 मेगावाट सौर, पवन ऊर्जा क्षमता का इजाफा

नई दिल्ली। देश मे इस साल जनवरी-मार्च में ग्रिड से जुड़ी करीब 715 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता सृजित हुई है। यह पिछले साल की इसी तिमाही के 2,163 मेगावाट के मुकाबले 67 प्रतिशत कम है। एक रिपोर्ट मे यह कहा गया है।

एसोचैम का अंतरराज्यीय आवागमान की अनुमति देने का आग्रह

नई दिल्ली। उद्योग संगठन एसोचैम ने मंगलवार को राज्यो की सीमाओसे प्रतिबंध हटाकर लोगों को एक राज्य दूसरे राज्य में आने जाने में राहत देने का आग्रह किया है। उद्योग मंडल ने राज्यो से कहा है कि उन्हे लॉकडाउन चार के दौरान राज्यों के बीच निजी वाहनो से आवागमन मे ढील दी जानी चाहिए।

बिहार में 14 लाख नए लाभार्थियों के लिए 2,770 टन अनाज आवंटित: पासवान

नई दिल्ली। केंद्र ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत बिहार में 14.04 लाख नए लाभार्थियों को मंजूरी दी है और उनके लिए 2,770 टन खाद्यान्न का आवंटन किया है। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नए 14.04 लाख लाभार्थियों को इस महीने से एनएफएसए के तहत खाद्यान्न पात्रता मिल जाएगी। एनएफएसए के तहत, केंद्र प्रति माह प्रति व्यक्ति 2-3 रुपए की अत्यधिक रियायती दर पर 5 किलोग्राम गेहूं अथवा चावल उपलब्ध करता है।

2020–21 में 20 अरब डॉलर चालू खाते का अधिशेष होने का अनुमान

भाषा। मुंबई

कोरोना संकट के बीच आयात में लगातार गिरावट से चालू वित्त वर्ष में भारत के पास चालू खाते में 20 अरब डॉलर या जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) का 0.7 प्रतिशत अधिशेष हो सकता है। एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। देश का चालू खाता प्राय: घाटे में बना रहता है। पिछली बार देश में चालू घाटे के अधिशेष की स्थिति 2006–07 की पहली तिमाही में थी। विदेशी ब्रोकरेज कंपनी बार्कलेज ने मंगलवार को एक विश्लेषण में कहा कि उस समय भी कारण कच्चे तेल का सस्ता होना था। वास्तव में आर्थिक वृद्धि की बिगड़ती रफ्तार के साथ निर्यात–आयात व्यापार 2019 से संतुलित हो रहा था। देश भर में 25 मार्च से लॉकडाउन (बंद) के बाद से निर्यात और और आयात दोनों अप्रैल में अबतक के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए। रिपोर्ट के अनुसार बंदरगाहों के लगभग पूर्ण रूप से बंद होने के कारण अप्रैल महीने में जहां निर्यात 60 प्रतिशत घटा वहीं आयात में 59 प्रतिशत की गिरावट आई। इसके कारण अप्रैल में व्यापार घाटा चार साल में सबसे कम रहा। बार्कलेज के अनुसार, हमारा अनुमान है कि व्यापार घाटा नीचे बना रहेगा और 2020–21 में यह 103 अरब डॉलर या जीडीपी का 3.7 प्रतिशत रह सकता है।

भारत का डब्ल्यूटीओ के तहत विकासशील, अल्पविकसित देशों में ब्रांडबैंड ढांचे, डिजिटल कौशल बढ़ाने पर जोर

नई दिल्ली। भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के तहत ई- वाणिज्य के क्षेत्र मे बाध्यकारी नियमों पर बातचीत के बजाय विकासशील और अल्पविकसित देशों में डिजिटल कौशल और ब्रांडबैंड ढांचागत सुविधाओ के क्षेत्र में क्षमता निर्माण पर जोर दिए जाने की वकालत की है। भारत का कहना है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से डिजिटल अर्थव्यवस्था की तरफ दुनिया का झुकाव बढ़ा है। डब्ल्यूटीओ सामान्य परिषद की पिछले सपताह कोविड-19 व्यापार संबंधी उपायो को लेकर हुई विशेष वर्चुअल बैठक मे भारत ने कहा कि विकसित और विकासशील देशों के बीच डिजिटल क्षेत्र में बड़ा अंतर है। भारत ने कहा कि दुनिया की करीब आधी आबादी की तीव्र गति के ब्राडबैड तक पहुंच नही है। इन देशों की आनलाइन प्लेटफार्म तक भी पहुंच नही है।

एफपीआई ने मार्च तिमाही में भारतीय बाजारों से निकाले 6.4 अरब डालर, मई में की वापसी

भाषा। नई दिल्ली

भारत में जब कोरोना वायरस महामारी का प्रसार शुरु हुआ तब मार्च में समाप्त तिमाही के दौरान अनिश्चितता को देखते हुए विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार से 6.4 अरब डालर की पूंजी निकाल ली, हालांकि, इसके बाद अप्रैल और मई के दौरान स्थिति मे सुधार देखा गया। भारतीय पूंजी बाजार मे निवेश करने वाले विदेशी पोटफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने इससे पहले दिसंबर 2019 में समाप्त तिमाही के दौरान 6.3 अरब डालर का शुद्ध निवेश किया था। मार्निंगस्टार की एक रिपोर्ट मे यह जानकारी दी गई है। इस साल जनवरी माह मे एफपीआई भारतीय बाजारों में शुद्ध लिवाल बने रहे, उन्होने 1.71 अरब डालर की लिवाली की, उसके बाद फरवरी मे 26.50 करोड़ डालर की खरीदारी उन्होंने की। लेकिन मार्च 2020 मे उन्होंने बिकवाली की राह पकड़ ली और कुल मिलाकर 8.4 अरब डालर की परिसंपत्तियो की शुद्ध बिकवाली उन्होंने की। विदेशी निवेशकों ने जनवरी- मार्च तिमाही की शुरुआत सतर्कता के साथ की। इस दौरान चीन और ईरान के बीच भू-राजनीतिक तनाव चल रहा था वही अमेरिका और चीन के बीच व्यापार संबंधो में तेजी से बदलाव देखा जा रहा था।हालांकि, उन्होंने अपनी जोखिम खपाने की स्थिति को मजबूत किया क्योंकि ए चिंताएं धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी। जनवरी से मार्च तिमाही के दौरान एफपीआई भारतीय पूंजी बाजार में शुद्ध विक्रेता रहे और उन्होने 6.4 अरब डालर की बिकवाली कर डाली।

डब्ल्यूएचओ चीन के हाथ की कठपुतली है: ट्रंप

भाषा। वाशिंगटन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) पर एक बार फिर सोमवार को हमला बोला और कहा कि संयुक्त राष्ट्र का यह स्वास्थ्य निकाय चीन के हाथ की कठपुतली है। ट्रंप ने दावा किया कि अगर उन्होंने चीन से यात्रा पर प्रतिबंध नहीं लगाए होते तो कोरोना वायरस से देश में और लोगों की मौत हुई होती जिसका स्वास्थ्य एजेंसी ने विरोध किया था। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा, वे (डब्ल्यूएचओ) चीन के हाथ की कठपुतली हैं। सही ढंग से कहा जाए तो वे चीन केंद्रित हैं। लेकिन वे हैं चीन के हाथ की कठपुतली ही।

ट्रंप ने एक सवाल के जवाब में कहा, मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत खराब काम किया है। अमेरिका उन्हें हर साल 45 करोड़ डॉलर देता है। चीन उनको साल में 3.8 करोड़ डॉलर का भुगतान करता है। ट्रंप ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जनवरी अंत में चीन से यात्रा पर प्रतिबंध लगाए जाने के खिलाफ था। उन्होंने कहा, डब्ल्यूएचओ इसके खिलाफ था। वे मेरे प्रतिबंध लगाने के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था कि आपको इसकी जरूरत नहीं है, ए बहुत ज्यादा है और बेहद सख्त है लेकिन वे गलत साबित हुए। ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एवं पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन भी इस प्रतिबंध के खिलाफ थे। उन्होंने कहा, सुस्त जो बाइडेन ने भी यही बात कही थी। उन्होंने कहा कि मैं विदेशी लोगों से नफरत करता हूं। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि मैंने कहा था कि चीन से आने वाले लोग देश में प्रवेश नहीं कर सकते। आप अब बहुत जल्दी हमारे देश में प्रवेश नहीं कर सकते। और बाइडेन ने कहा कि मैं विदेशियों से नफरत करता हूं। ट्रंप ने कहा, अगर मैंने प्रतिबंध नहीं लगाया होता, तो इस देश ने हजारों और लोगों को गंवा दिया होता। यह बहुत महत्त्वपूर्ण प्रतिबंध था। लोग प्रतिबंध के बारे में बात करना पसंद नहीं करते लेकिन यह बहुत महत्त्वपूर्ण था। राष्ट्रपति ने दावा किया कि उन्हें छोड़कर कोई नहीं चाहता था कि यह प्रतिबंध लगाया जाए।

कोविड-19 से निपटने में संगठन की भूमिका की जांच की मांग के आगे झुका डब्ल्यूएचओ

जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने में संगठन की भूमिका की जांच की ज्यादातर सदस्य देशों की मांग सोमवार को मान ली। इस वायरस से पूरी दुनिया में 3,00,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और वैश्विक अर्थव्यस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। अफ्रीकी, यूरोपीय और अन्य देशों के गठबंधन कोविड-19 से निपटने में डब्ल्यूएचओ की भूमिका की स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। इसका उद्देश्य वायरस की उत्पत्ति के स्थल जैसे कुछ विवादित मुद्दों को छोड़कर इसकी रोकथाम के लिए डब्ल्यूएचओ द्वारा अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के समन्वय से मिले सबक की समीक्षा करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उनके पास कोरोना वायरस के चीन की एक प्रयोगशाला में उत्पन्न होने का सबूत है, जबकि वैज्ञानिक समुदाय का कहना है कि अभी तक के सभी साक्ष्य यही कहते हैं कि वायरस जानवरों से मनुष्यों में सीधे आया है। ट ने सोमवार को डब्ल्यूएचओ पर निराशाजनक काम करने का आरोप लगाया और कहा कि वह संगठन को दिए जाने वाले 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर को घटाकर 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर करने पर विचार कर रहे हैं। ड ब्ल्यूएचओ महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयसस ने कहा कि वह उचित समय देखकर जल्द से जल्द कोविड-19 से निपटने में डब्ल्यूएचओ की भूमिका की स्वतंत्र जांच शुरु करेंगे।

कोरोना वायरस से बचने के लिए मलेरिया की दवाई ले रहा हूं: ट्रंप

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोमवार को कहा कि वह कोरोना वायरस से बचने के लिए मलेरिया की दवाई हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन ले रहे हैं। ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, मैं करीब डेढ़ सप्ताह से यह (हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन) ले रहा हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें कोविड-19 के कोई लक्षण नहीं है।अमेरिका में पिछले तीन महीने में इस महामारी से 90,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। ट्रम्प ने कहा कि इस संबंध में उन्होंने अपने चिकित्सकों से सलाह ली थी लेकिन व्हाइट हाउस के चिकित्सक ने इस पर कोई खास जोर नहीं दिया।उन्होंने कहा, व्हाइट हाउस के चिकित्सक ने दवा लेने की सलाह नहीं दी। मैंने उनसे पूछा था कि उनका इस बारे में क्या विचार है? उन्होंने कहा कि क्या आप दवाई लेना चाहते हैं। मैंने कहा कि हां मैं दवाई लेना चाहता हूं। ट्रम्प ने कहा कि वह रोज मलेरिया की एक गोली लेते हैं।उन्होंने कहा, मैं रोज एक गोली लेता हूं। कुछ समय बाद मैं इसे लेना बंद कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि इसका इलाज मिले या इसका टीका बने और यह एक दिन जरूर होगा। मुझे लगता है कि बहुत जल्द ऐसा होगा। ट्रम्प के दवाई लेने की जानकारी देने के कुछ देर बाद ही व्हाइट हाउस के डॉक्टर सीन पी. कॉनले ने कहा कि राष्ट्रपति एकदम स्वस्थ हैं और उनमें कोविड-19 के कोई लक्षण नहीं हैं।

भारत, इजराइल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सहमत

भाषा। यरूशलम

यहूदी देश में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद इजराइल और भारत के विदेश मंत्रियों ने पारस्परिक रूप से लाभकारी भागीदारी के लिए बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत और विस्तारित करने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया है।

इजराइल की नई सरकार ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में रविवार को शपथ ग्रहण की और इसके साथ ही देश के इतिहास में सर्वाधिक लंबे राजनीतिक गतिरोध पर विराम लग गया। इस गतिरोध के चलते देश को 500 से अधिक दिन तक कार्यवाहक सरकार के नेतृत्व में काम करना पड़ा और एक के बाद एक तीन आम चुनावों का सामना करना पड़ा जिनमें किसी को स्पष्ट जनादेश नहीं मिला। इजराइली संसद नेसेट में विश्वासमत के दौरान नई सरकार के पक्ष में 73 तथा विपक्ष में 46 वोट पड़े। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को अपने नवनियुक्त इजराइली समकक्ष गाबी अश्केनजी को बधाई दी जो इजराइली रक्षा बलों के पूर्व प्रमुख हैं। जयशंकर ने हिब्रू में ट्वीट किया, इजराइली विदेश मंत्री के रूप में पदभार संभालने पर माजाल तोव (बधाई) गाबी अश्केनजी। हमारी बहुआयामी और पारस्परिक लाभ वाली भागीदारी को मजबूत करने के लिए मैं आपके साथ मिलकर काम करने को आशान्वित हूं। अश्केनजी ने जयशंकर का धन्यवाद व्यक्त किया और दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। इजराइली विदेश मंत्री ने सोमवार को हिन्दी और अंग्रेजी में ट्वीट किया, धन्यवाद डॉ. जयशंकर। मैं भी भारत और इजराइल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत और विस्तारित करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने को आशान्वित हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने नेतन्याहू को रिकॉर्ड पांचवीं बार सरकार का गठन करने पर रविवार को पहले-पहल बधाई दी थी।

संयुक्त राष्ट्र की टीम ने इराक में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ नए सबूत हासिल किए

भाषा। संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र की एक जांच टीम ने कहा है कि उसने इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के खिलाफ इराक में सबूतों के नए स्रोत एकत्र करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिनमें 20 लाख से अधिक कॉल रिकॉर्ड शामिल हैं, जिससे 2014 में यज़ीदी अल्पसंख्यकों विरोधी अपराधों को अंजाम देने वालों के खिलाफ मामले मजबूत होंगे। जांच टीम ने जून 2014 में तिकरित एयर अकादमी के निहत्थे कैडेटों और सैन्य कर्मियों की सामूहिक हत्याओं और 2014 से 2016 तक मोसुल में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों द्वारा किए गए अपराधों की जांच में भी प्रगति की बात कही है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सौंपी गई एक रिपोर्ट में, जांच टीम ने कहा कि वह कानून के लंबित मुद्दे को लेकर इराक की सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रही है, ताकि देश को इस्लामिक स्टेट के युद्ध अपराधों, मानवता विरोधी अपराधों और नरसंहार के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिल सके। यह रिपोर्ट द एसोसिएटेड प्रेस के पास भी उपलब्ध है। रिपोर्ट में कहा गया है, आने वाले छह महीनों में, टीम कोशिश करेगी कि सरकार इस अवसर का इस्तेमाल करे, ताकि टीम द्वारा एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर कार्यवाही शुरू की जा सके। इस्लामिक स्टेट समूह का कभी इराक और सीरिया दोनों देशों के एक तिहाई हिस्से पर कब्जा था, लेकिन उसे करारी हार का सामना करना पड़ा है। वह खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है, लेकिन उसके लड़ाके अभी भी हमले करते रहे हैं।

आतंकवादी समूह के लड़ाकों और समर्थकों के अत्याचार ने उस क्षेत्र में जख्म के गहरे निशान छोड़े हैं। इराक के यज़ीदी अल्पसंख्यक की हजारों महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया था और उन्हें गुलाम बना लिया गया था, जबकि पुरुषों को मार डाला गया था।

न्यूयॉर्क में जून की शुरुआत में गतिविधियों हो सकती हैं बहाल: मेयर डी ब्लासियो

न्यूयॉर्क । कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित न्यूयॉर्क के मेयर डी ब्लासियो ने कहा कि जून की शुरुआत में ही कुछ गतिविधियों को बहाल किया जा सकता है।अमेरिका में न्यूयॉर्क में कोविड-19 के सबसे अधिक 1,91,073 मामले हैं और इससे 15,983 लोगों की जान गई है। डी ब्लासियो ने कहा, इस समय जून से पहले चीजें सामान्य होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए जून की शुरुआत में ही किसी भी चीज में ढील दी जा सकती है। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रियू क्यूमो ने कहा कि उद्योग एवं संस्थाओं को दोबारा खोलने के लिए सात मापदंड पूरे करने होंगे।ए सात मापदंड, अस्पातल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में गिरावट, मृत्यु दर में कमी, प्रति एक लाख व्यक्ति पर दो नए अस्पताल, आईसीयू की सुविधा, आदि हैं। ब्लासियो ने कहा कि कुछ मापदंडों में प्रगति है लेकिन अस्पतालों में बेड और आईसीयू बेड की मांग पूरी करने के लिए हमें अभी और मेहनत करनी होगी। पर हम उसके काफी करीब हैं। उन्होंने कहा, लेकिन अगर सवाल यह है कि क्या हम सात मापदंडों को पूरा कर पाएंगे? तो जवाब है, हां। कब? जून की शुरुआत में।

मॉस्को में लेनिनग्राद्स्की रेलवे स्टेशन पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सेनीटाइजेशन करते संघीय स्टेट सेंटर के कर्मचारी

न्यूयॉर्क में कोरोनोवायरस के प्रसार से खुद को बचाने के लिए ब्रूकलिन के डोमिनोज़ मैदान में घास पर चिह्नित कर एक निर्दिष्ट सर्कल में बैठे हुए लोग

गुतारेस ने संरा महासभा के लिए विश्व नेताओं के पूर्व रिकॉर्ड किए संदेशों के इस्तेमाल का सुझाव दिया

भाषा। संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने सुझाव दिया है कि सितंबर में होने वाले वार्षिक आमसभा के सत्र को अलग प्रारूप में आयोजित किया जाए, जैसे कि विश्व नेताओं के पहले से रिकॉर्ड संदेशों का इस्तेमाल किया जाए। उनका कहना है कि इसकी संभावना बेहद कम है कि कोविड-19 महामारी के बीच राष्ट्रों और सरकारों के प्रमुख एक हफ्ते के लिए न्यूयॉर्क की यात्रा कर सकेंगे।

संयुक्त राष्ट्र इस साल अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और सितंबर में होने वाली वार्षिक आम सभा में 193 सदस्य देशों के नेता, मंत्री, कूटनीतिज्ञ न्यूयॉर्क में संरा मुख्यालय में मीडिया कर्मियों और हजारों नागरिक संस्थाओं के सदस्यों के साथ जुटते हैं।अमेरिका में न्यूयॉर्क कोविड-19 महामारी का केंद्र है। राज्य में संक्रमण के 3,56,278 मामले सामने आ चुके हैं जबकि 28,302 लोगों की जान जा चुकी है। गुतारेस ने 18 मई को आम सभा के 74वें सत्र के अध्यक्ष तिज्जानी मुहम्मद बांदे को लिखे पत्र में कहा कि चिकित्सकों का मानना है कि आने वाले महीनों में कोविड-19 महामारी का चक्र दुनिया भर में अलग-अलग गंभीरता स्तर के साथ चलता रहेगा। इस कारण कुछ जगहों पर अंतरराष्ट्रीय यात्रा पाबंदियों को बरकरार रखने की जरूरत होगी तथा सामाजिक दूरी के उपायों को बरकरार रखने के साथ ही ज्यादा भीड़-भाड़ से भी बचना होगा।

उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क की यात्रा करने और यहां से लौटने के बाद कई यात्रियों को पृथक-वास में भी रहना होगा। गुतारेस ने पत्र में कहा, ऐसे में इस बात की संभावना बेहद कम है कि सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रमुख या सरकारों के प्रमुख सितंबर में न्यूयॉर्क की यात्रा कर सकें। उन्होंने पत्र में कहा इसलिए, आप अनुशंसा कर सकते हैं कि आम सभा 75वें सत्र की आम चर्चा के लिए अलग प्रारूप पर विचार करे, जैसे राष्ट्राध्यक्षों, सरकार के प्रमुखों, मंत्रियों द्वारा उपलब्ध कराए गए पूर्व रिकॉर्डेड संदेशों का इस्तेमाल किया जाए जबकि महासभा सभागार में सभी सदस्य राष्ट्रों के न्यूयॉर्क स्थिति प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य को भौतिक रूप से वहां रहने दिया जाए।

चीन में कोविड-19 के 23 नए मामले

भाषा। बीजिंग

चीन में कोरोना वायरस के 23 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से एक मामला वुहान का है, जो इस महामारी का पहला केंद्र था। 1.12 करोड़ की आबादी वाले इस शहर में अब बड़े पैमाने पर लोगों की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग (एनएसची) ने कहा कि सोमवार को देश में कोरोना वायरस के लक्षण वाले छह मामले सामने आए, जबकि 17 बिना लक्षण वाले मामले सामने आए। लक्षण वाले छह पुष्ट नए मामलों में एक वुहान से है और दो जिलिन प्रांत से हैं। दोनों मामले संक्रमण के स्थानीय प्रसार के हैं। स्थानीय स्वास्थ्य आयोग ने बताया कि हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में कुल सात मामले हैं, जहां पिछले साल दिसंबर में वायरस उभरा था।

वुहान शहर में 285 से अधिक बिना लक्षण वाले मामले हैं, जिसकी वजह से अधिकारियों को स्थानीय आबादी की सामूहिक जांच शुरू करनी पड़ी। शहर में 76 दिनों तक लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसे पिछले महीने हटाया गया था। शहर में अभी बड़े पैमाने पर कोविड-19 की जांच चल रही है। एनएचसी ने कहा कि बिना लक्षण वाले सभी 17 नए मामले स्थानीय प्रसार के हैं। इन नए मामलों को मिलकार अब बिना लक्षण वाले कुल 389 मामले हो गए हैं, जिनमें 29 विदेशों से आए हुए हैं। इन सभी को चिकित्सा निगरानी में रखा गया है।

पाकिस्तान में कारोना के 1,841 नए मामले, 36 मौतें: स्वास्थ्य मंत्रालय

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,841 नए मामले सामने आए, जबकि 36 मौतें हुई हैं। संक्रमण के इन नए मामलों के साथ देश में संक्रमितों की कुल संख्या 44,000 के करीब पहुंच गई, जबकि मृतकों की संख्या 939 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। राजधानी इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के मामले 1,000 के पार हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में भी संक्रमण का बढ़ना जारी है। अब तक सिंध में 17,241 मामले, पंजाब में 15,976, खैबर-पख्तूनख्वा में 6,230, बलूचिस्तान में 2,820, इस्लामाबाद में 1,034, गिलगित-बाल्तिस्तान में 550 और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 115 मामले सामने आए हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, अब तक 4,00,292 जांच की गई हैं, जिनमें 12,957 पिछले 24 घंटों में की गई हैं। संक्रमण की लगातार बढ़ती संख्या और प्रतिबंधों में ढील देने के मद्देनजर कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने वाली है। पाकिस्तान ने लॉकडाउन में ढील देना शुरू कर दिया है और अपनी घरेलू हवाई सेवाओं को आंशिक रूप से फिर से शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कुल 12,489 मरीज अब तक वायरस से उबर चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 36 मौतें होने से मरने वालों की संख्या 939 पर पहुंच गई।

तालिबान और अफगानिस्तान सुरक्षा बलों की लड़ाई में नागरिकों की मौतें बढ़ रही हैं: संयुक्त राष्ट्र

काबुल। संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को अफगानिस्तान में हिंसा को तुरंत कम करने का आह्वान किया और कहा कि तालिबान और अफगानिस्तान सुरक्षा बलों की लड़ाई में असैन्य नागरिकों की मौतें बढ़ रही हैं। अफगानिस्तान में स्थित संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (यूएनएएमए) ने एक बयान में इस्लामिक स्टेट समूह द्वारा दावा किए गए घातक हमलों को लेकर चिंता व्यक्त की।

राजधानी के एक प्रसूति अस्पताल में पिछले हफ्ते एक भयानक हमले की जिम्मेदारी किसी भी समूह द्वारा नहीं ली गई है, लेकिन अमेरिका ने कहा कि यह अफगानिस्तान के आईएस संबद्ध समूह ने किया है, जो देश के अल्पसंख्यक शियाओं को निशाना बनाते हुए उन पर हमले करते रहते हैं और पहले भी कई बार हमले किए हैं। तालिबान ने प्रसूति अस्पताल के हमले में शामिल होने से इनकार किया, जिसमें 24 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें दो शिशु और कई माताएं शामिल थी। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में अप्रैल में 208 असैन्य नागरिकों की हत्या के लिए तालिबान को दोषी ठहराया गया, जबकि अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बलों की कार्वाई में इसी महीने में 172 नागरिक मारे गए।

नेपाल ने भारत से सीमा विवाद के बीच नया मानचित्र स्वीकृत किया

भाषा। काठमांडू

● लिपुलेख, कालापानी को किया शामिल

भारत के साथ सीमा विवाद के बीच नेपाल के कैबिनेट ने एक नया राजनीतिक मानचित्र स्वीकार किया है जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाली क्षेत्र में दर्शाया गया है। विदेश मंत्री प्रदीप कुमार गयावली ने इस कदम की घोषणा से हफ्तों पहले कहा था कि कूटनीतिक पहलों के जरिए भारत के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के प्रयास जारी हैं। नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के सांसदों ने कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को नेपाल की सीमा में लौटाने की मांग करते हुए संसद में विशेष प्रस्ताव भी रखा था। लिपुलेख दर्रा नेपाल और भारत के बीच विवादित सीमा, कालापानी के पास एक दूरस्थ पश्चिमी स्थान है। भारत और नेपाल दोनों कालापानी को अपनी सीमा का अभिन्न हिस्सा बताते हैं। भारत उसे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा बताता है और नेपाल इसे धारचुला जिले का हिस्सा बताता है। गयावली ने कहा कि भूमि प्रबंधन मंत्रालय जल्द ही नेपाल का आधिकारिक मानचित्र सार्वजनिक करेगा। उन्होंने सोमवार को ट्विटर पर कहा, मंत्री परिषद ने नेपाल के सात प्रांतों, 77 जिलों और लिमपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी समेत 753 स्थानीय स्तर के प्रशासनिक संभागों में नेपाल का मानचित्र प्रकाशित किया जाने का फैसला लिया है। गयावली ने भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा को पिछले हफ्ते तलब किया था और उत्तराखंड में धारचुला के साथ लिपुलेख को जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग के निर्माण के खिलाफ विरोध जताने के लिए कूटनीतिक नोट सौंपा था। भारत ने कहा था कि उत्तराखंड के पिथौड़ागढ़ जिले में हाल में उद्घाटित सड़क मार्ग पूरी तरह उसकी सीमा के भीतर आता है। नेपाल के वित्त मंत्री एवं सरकार के प्रवक्ता युवराज खाटीवाड़ा ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने देश के नए राजनीतिक मानचित्र क स्वीकृत किया है।संस्कृति, पर्यटन एवं नागर विमानन मंत्री योगेश भट्टाराय ने कहा कि कैबिनेट के फैसला स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हालांकि, सत्तारूढ़ पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थाई समिति के सदस्य गणेश शाह ने कहा कि यह नया कदम नेपाल और भारत के बीच ऐसे समय में अनावश्यक तनाव पैदा करेगा जब देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है।

गुतारिस ने अफगान राष्ट्रपति गनी और अब्दुल्ला के बीच समझौते की सराहना की

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके प्रतिद्वंद्वी अब्दुल्ला अब्दुल्ला के बीच हुए समझौते पर खुशी जताते हुए कहा कि यह एक ऐसा कदम है जिससे देश के लंबे समय से चल रही अशांति को समाप्त कर शांति समझौते के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। समझौते के अनुसार अशरफ गनी राष्ट्रपति बने रहेंगे जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी अब्दुल्ला की टीम की मंत्रिमंडल में आधी हिस्सेदारी होगी। अब्दुल्ला कार्यकारी प्राधिकरण के साथ राष्ट्रीय सुलह समझौता उच्च परिषद (एचसीएनआर) के प्रमुख होंगे। समझौते के अनुसार तालिबान के साथ होने वाली शांति वार्ता एचसीएनआर के तहत अब्दुल्ला के नेतृत्व में होगी। अब्दुल्ला ने गनी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार में मुख्य कार्यकारी के रूप में सेवा दी थी।महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुतारेस को उम्मीद है कि गनी और अब्दुल्ला के बीच हुए इस समझौते से व्यापक शांति समझौते की दिशा में प्रयास किया जा सकता है।

बलूचिस्तान में दो आतंकी हमले में सात पाकिस्तानी सैनिकों की मौत

भाषा। कराची

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दो अलग अलग आतंकी हमलों में सात पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। मंगलवार को जारी एक आधिकारिक वक्तव्य में यह जानकारी दी गई। पाकिस्तानी फौज के मीडिया विभाग अंतर-सेवा जन संपर्क (आईएसपीआर) ने कहा कि आंतकियों ने सोमवार रात को पीर गैब क्षेत्र में फ्रंटियर कोर के एक वाहन को आईईडी विस्फोट से उड़ा दिया जिससे पाकिस्तानी सेना के छह सैनिकों की मौत हो गई। बलूचिस्तान के कैच इलाके में एक अलग घटना में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक अन्य सैनिक की मौत हो गई। घटना तड़के हुई जब सुरक्षा बल के जवान सीमा पर बाड़ लगाने का काम कर रहे थे। संसाधन संपन्न बलूचिस्तान पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है और इसकी सीमा अफगानिस्तान और ईरान से लगती है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे गरीब प्रांत है।

पाक अदालत ने दरगाह पर हमले के मामले में दो आतंकवादियों को मौत की सजा सुनाई

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में आतंकवाद रोधी एक अदालत ने सिंध प्रांत स्थित एक दरगाह पर हमले के मामले में सोमवार को दो आतंकवादियों को मौत की सजा सुनाई। इस हमले में 82 लोग मारे गए थे। पुलिस के अनुसार, नादिर अली और फुरकान की पहचान सीसीटीवी फुटेज के जरिए प्रत्यक्षदर्शियों तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट मुश्ताक अली जोखिओ ने की थी। दोनों आतंकवादियों को सिंध प्रांत के सेहवान शरीफ क्षेत्र में 2017 में हुए हमले के मामले में दोषी पाया गया। सेहवान शरीफ स्थित लाल शाहबाज कलंदर दरगाह पर 16 फरवरी 2017 को हुए आतंकी हमले में 82 लोग मारे गए थे और सैकड़ों अन्य घायल हुए थे।

विश्व में करीब 13 प्रतिशत संग्रहालय शायद दोबारा कभी नहीं खुल पाएं

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी ने आगाह करते हुए कहा कि हो सकता है विश्व में 13 प्रतिशत संग्रहालय कभी दोबारा ना खुलें।वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण विश्वभर में करीब 90 प्रतिशत संग्रहालय अभी बंद हैं। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस (सोमवार को) पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) और अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय परिषद (आईसीओएम) द्वारा जारी किए दो अध्ययनों में कहा गया है कि कोविड-19 का संग्रहालयों पर काफी असर पड़ा है, करीब 90 प्रतिशत या 85,000 से अधिक संस्थान लंबे समय से बंद हैं। वहीं अफ्रीका और छोटे द्वीपों पर स्थित विकासशील देशों (एसआईडीएस) में केवल पांच प्रतिशत ही दर्शकों को ऑनलाइन सामग्री मुहैया करा सकते हैं। एजेंसी ने एक बयान में कहा, विश्वभर में करीब 13 प्रतिशत संग्रहालय शायद कभी दोबारा नहीं खुलेंगे। दोनों अध्ययन संग्रहालय और संग्रहालय संस्थानों पर कोविड-19 के प्रभाव का आकलन करने के लिए किए गए।

‘अभिनय के प्रति प्रेम के कारण ही फिल्म व्यवसाय का हिस्सा हूं’

हाल ही में नेटफ्लिक्स पर **मनोज वाजपेयी** का एक शो ‘मिसेज़ सीरियल किलर’ नंबर एक पर ट्रेंड कर रहा है। **पायनियर संवाददाता मुस्बा हाशमी** के साथ एक विशेष बातचीत में उन्होंने इस रोल को स्वीकार करने के बारे में बताया। अन्य बातों के अलावा उन्होंने बताया कि वो निर्देशक के अनुसार चलते हैं और इंडस्ट्री में अब तक के अपने अनुभव के बारे में भी जानकारी साझा की......

■ नेटफ्लिक्स पर चलने वाले आपके शो ‘मिसेज़ सीरियल किलर’ में आपकी भूमिका क्या है?

मैं इसमे मृत्युंजय मुखर्जी का चरित्र निभा रहा हूं। वो अपने अतीत से आशंकित रहते हैं। वो चिकित्सा विज्ञान के छात्र रहे हैं और अपने क्षेत्र में एक विशेषज्ञ हैं। वो अपनी पत्नी से प्यार करते हैं लेकिन अतीत की कुछ बातें हैं जिनके कारण वो भयभीत और आशंकित से रहते हैं। ये शो एक धैर्यवान पारिवारिक व्यक्ति जो मस्तिष्क से विचित्र भी हैं की कहानी को बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है।

■ आपको इस भूमिका में ऐसा क्या आकर्षक लगा कि आपने रोल स्वीकार किया?

मेरा चरित्र और पूरी स्क्रिप्ट बहुत ही सुगठित ढंग से लिखे गए हैं। ये महत्वपूर्ण है कि मैंने ये रोल केवल शिरीश के कारण ही स्वीकार किया था।

हम पहले एक फिल्म कृति में काम कर चुके थे और वो अच्छी रही थी। हम और अधिक आपसी सहयोग चाहते थे और जब वो इस फिल्म के लिए मुझसे अंतिम समय पर संपर्क करने आए तो मैंने तुरंत ही इसके लिए स्वीकृति दे दी। तब मुझे पता नहीं था कि लोगों को ये इतना अच्छा लगने वाला है।

■ आपकी फिल्म नंबर एक पर ट्रेंड कर रही है? ये जानकर आपको कैसा लगता है?

बहुत अच्छा लगता है। ये जानकर कि रिलीज़ के दूसरे ही दिन ये नंबर एक पर ट्रेंड कर रही थी, मुझे वास्तव में काफी अच्छा लगा। हमारी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। ये जानकर कि एक फिल्म जिसके बारे में दो तीन साल पहले सोचा गया था। लेकिन अब उसे इतने अच्छे ढंग से बनाया गया है कि वो चार्ट में नंबर एक पर ट्रेंड कर रही है।

■ क्या आपको लगता है कि कोरोना बंदी के बाद भी ओटीटी प्लेटफॉर्म और अधिक लोकप्रिय होने वाला है?

कोरोना महामारी के कारण हुई बंदी से ओटीटी प्लेटफॉर्म को बहुत प्रोत्साहन मिला है। कभी सोचा नहीं था कि महामारी के कारण लोगों को घर के भीतर सिमट कर रह जाना पड़ेगा। और अब तो लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाले शोज़ में विशेष रुचि ले रहे हैं बल्कि कह सकते हैं कि ये हमारी कल्पना से भी अधिक है। बंदी के बाद से ही लोगों के पास मनोरंजन के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म से अच्छा दूसरा कोई माध्यम दिखाई नहीं देता। अब वे इसके इतने प्रेमी हो गए हैं कि इसपर उपलब्ध सारी सामग्री को देख डालते हैं। बल्कि अब वे कंटेंट के भूखे से हो चले हैं। मुझे लगता है कि लॉकडाउन के बाद भी उनकी ये आदत जाने वाली नहीं है। अब लोग देखने योग्य हर कार्यक्रम को देखते हैं और लॉकडाउन के बाद भी भविष्य में फिल्म निर्माण के लिए दर्शकों का ये उत्साह बहुत सहायक सिद्ध होने वाला है।

> **आप किसी भी चीज़ या व्यक्ति को दिल से न लगाइये। मैं इस सिद्धांत को वर्षों से पालन करता आ रहा हूं। मैं अपनी आलोचना को भी मस्तिष्क में नहीं पालता क्योंकि इससे मेरे प्रदर्शन में अंतर आ सकता है। अपनी सफलता को भी मैं सिर नहीं चढ़ने देता। मैं वो करता रहता हूं जो मुझे करना होता है और हर दिन अपनी कला में और अधिक परिपक्वता लाने के लिए जो मिलता है उसे सीखने का प्रयास करता हूं।**

■ क्या कोई नया रोल लेने से पहले आप पर कुछ दबाव होता है क्योंकि अब आप स्वयं में भी एक ब्रांड बन गए हैं?

जो मैं कहने जा रहा हूं वो पूरी विनम्रता से कहूंगा। आप इसे किसी प्रकार भी गर्व या घमंड जैसा कुछ न समझना। मैंने सदा से चरित्र को ध्यान में रखकर ही अपनी भूमिका का निर्वाह किया है और निर्देशक के निर्देशों के अनुसार अभिनय करके भूमिका के साथ पूरा न्याय करने का प्रयास किया है। इस व्यवसाय में मैं अभिनय के प्रति अपने प्रेम के कारण ही हूं। मैं बस भूमिका के साथ न्याय करने पर अपना पूरा ध्यान लगाता हूं उस समय मैं दर्षकों के बारे में भी नहीं सोचता। मैं उन कलाकारों में से हूं जो और अधिक की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने ऊपर ही दबाव बढ़ा लेता हूं।

■ क्या आप निर्देशक के निर्देशों पर चलने वाले अभिनेता हैं या फिर आप अपने ढंग से काम करने की स्वतंत्रता को मानते हुए काम करते हैं?

मैं फिल्म के जॉनर के अनुसार कई प्रकार के निर्देशकों के साथ काम करता रहता हूं। मैं सदा से ही स्क्रिप्ट और निर्देषक के अनुसार काम करता हूं। जब मैं अतानु मुखर्जी की फिल्म ‘रुख’ जैसी फिल्म में काम करता हूं या फिर भोंसले जैसी फिल्म में नए निर्देशक देवाशीष मखीजा के साथ काम करता हूं तो हम निर्माणपूर्व प्रक्रिया पर बहुत ध्यान से निर्णय करते हैं।

उस समय हमें फिल्म की छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं। इसके लिए जरूरी वर्कशॉप करते हैं चरित्र के बारे में अधिक से अधिक विवरण एकत्र करते हैं। ये वास्तव में स्क्रिप्ट आधारित फिल्में हैं और जॉनर के अनुसार देखें तो भी ये स्वतंत्र फिल्में होती हैं। लेकिन जब हम सत्यमेव जयते या अहमद खान हेतु मिलाप जावेरी के लिए काम करते हैं तो मुझे पता करना होता है कि कहानी का क्षेत्र कहां है। उनका काम लोगों को उत्तेजित करना होता है तो अब ये जानने के बाद मेरा भी काम आसान हो जाता है क्योंकि मुझे उनकी अपेक्षाओं के बारे में पता रहता है। ऐसा समय भी आता है जब मिलाप या अहमद मुझसे मेरे प्रदर्शन में सुधार चाहते हैं क्योंकि वे मेरे प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं होते। वे चाहते हैं कि मैं अपने चरित्र को थोड़ा अधिक मनोरंजक बनाऊं तो उनकी ये बात मुझे भी स्वीकार करनी पड़ती है। मैं अभिनेता हूं और मेरा काम निर्देशक की कल्पना को साकार करना बल्कि और अधिक आगे ले जाना होता है। मैं उनसे तर्क नहीं कर सकता।

■ क्या इस इंडस्ट्री में आपने कोई सीख प्राप्त की?

आप किसी भी चीज़ या व्यक्ति को दिल से न लगाइये। मैं इस सिद्धांत को वर्षों से पालन करता आ रहा हूं। मैं अपनी आलोचना को भी मस्तिष्क में नहीं पालता क्योंकि इससे मेरे प्रदर्शन में अंतर आ सकता है। अपनी सफलता को भी मैं सिर नहीं चढ़ने देता। मैं वो करता रहता हूं जो मुझे करना होता है और हर दिन अपनी कला में और अधिक परिपक्वता लाने के लिए जो मिलता है उसे सीखने का प्रयास करता हूं। हमारी इंडस्ट्री में कोई भी शत्रुता या मित्रता स्थायी नहीं होती। कोई भी अभिनेता अपनी पिछली फिल्म जितना ही अच्छा या बुरा होता है।

■ फिल्म इंडस्ट्री में आते समय क्या आपने किसी विशेष जॉनर वाली फिल्मों में ही काम करने के बारे में सोचा था?

जब मैंने पदार्पण किया था उस समय कला फिल्मों की अवधारणा अपने अवसान पर थी और टीवी में भी अच्छी वृद्धि देखी जा रही थी। मेरे मन-मस्तिष्क में एक ही बात थी कि मुझे अच्छी फिल्में ही करनी हैं और अपने चरित्र को सही ढंग से निभाना है। मैं कुछ नया करना चाहता था क्योंकि थियेटर करते समय मैंने कुछ नया सीखा था। हम सभी - इरफान, कुमुद मिश्रा संजय मिश्रा, निर्मल पांडे कुछ अलग करना चाहते थे। कुछ वर्षों के संघर्ष के बाद मुझे सत्या फिल्म में काम करने का अवसर मिला और इस फिल्म ने मेरे कॅरियर और जीवन में व्यापक बदलाव ला दिया। इसने कहानी कहने के ढंग में भी अंतर ला दिया था। सत्या, शूल, कौन जैसी राम गोपाल वर्मा की फिल्मों ने सबकुछ बदल कर रख दिया। बाद में दूसरे निर्देशक हमारे लिए अलग प्रकार की भूमिकाएं लेकर आए। आज फिल्मों की विषय सामग्री में जो बदलाव देखा जा रहा है उसके लिए हमें शेखर कपूर, मणिरत्नम और राम गोपाल वर्मा को पूरा श्रेय देना चाहिये।

भारत में जाति या धर्म से ऊपर उठ पाना नामुमकिन है : सुदीप शर्मा

भाषा। नई दिल्ली

वेब सीरिज पाताल लोक के लेखक-रचयिता सुदीप शर्मा ने कहा कि वह अपने शो में कई कोणों को तलाशना चाहते थे लेकिन सबसे महत्त्वपूर्ण भारत की धार्मिक एवं जातिगत समस्याओं को तलाशना और दर्शाना था। पाताल लोक एक थ्रिलर है जिसमें एक पत्रकार की हत्या के प्रयास की गुत्थी को दिल्ली का नाकाम समझे जाना वाला पुलिसकर्मी सुलझाने की कोशिश करता है। पिछले हफ्ते अमेजन प्राइम पर रिलीज हुए इस शो को देश में जाति, वर्ग, लिंग और धार्मिक समीकरणों पर परतदर एवं पैनी नजर डालने और कैसे ए सारे समीकरण इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी (जयदीप अहलावत) और उसके सहयोगी इमरान अंसारी (इश्वाक सिंह) की जांच के केंद्र में रहे चार संदिग्धों की किस्मत को निर्धारित करते हैं,यह दिखाने के लिए काफी तारीफ मिल रही है। शर्मा ने एक साक्षात्कार में पीटीआई-भाषा से कहा, हम भारत में इन विभाजनों को गहराई से देखना चाहते थे जो साथ-साथ चलते हैं चाहे बात वर्ग की हो या जाति, भाषा, धर्म या लिंग की। जाति एवं धर्म दो प्रमुख फॉल्टलाइन हैं। उन्हें अलग यह बनाता है कि सामाजिक आर्थिक दर्जे से आप अपने वर्ग से ऊपर उठ सकते हैं लेकिन देश में जाति या धर्म से ऊपर उठ पाना नामुमकिन है। नौ कड़ियों वाली सीरिज पाताल लोक लंबी कहानी कहने वाले शर्मा के लिए अलग तरह की कामयाबी है। उन्हें एनएच10 , उड़ता पंजाब और सोनचिरैया जैसी कहानियों के लेखन का श्रेय प्राप्त है। उन्होंने कहा कि शो पर काम करना कई लघु कहानियां लिखने के बाद एक उपन्यास खत्म करने के बराबर था। शर्मा ने कहा कि इस तरह के फॉर्मेट ने उन्हें अपने हिसाब से पात्रों को और उनकी पृष्ठभूमि को चुनने की आजादी दी जिनमें चार संदिग्ध - हथोड़ा त्यागी, कबीर एम, चीनी और टोपे सिंह के पात्र भी शामिल थे। यह सीरिज नीरज कबी के पात्र संजीव मेहरा जो कि एक प्रसिद्ध खोजी पत्रकार है, के जरिए मीडिया को भी आलोचनात्मक दृष्टि से देखती है जो टीआरपी ला पाने में नाकामयाब होता है और ऐसा मान लेता है कि अपने उदारवादी विचारों से समझौता किए बिना मीडिया जगत में जगह बनाना असंभव है।

शिल्पा शेट्टी ने ‘गोरे-गोरे मुखड़े पे...’ किया डांस

भाषा। मुंबई

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने गोरे गोरे मुखड़े पे गाना पर डांस किया जो वायरल हो गया है। शिल्पा लॉकडाउन में रहने के बाद भी लगातार अपने वीडियो से खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। शिल्पा अपने टिकटॉक वीडियो से खूब धमाल मचा रही हैं। उनके वीडियो इंटनेट पर छाए हुए हैं। हाल ही में शिल्पा का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शिल्पा ‘गोरे-गोरे मुखड़े पे काला-काला चश्मा’ गाना पर जबरदस्त अंदाज में डांस करती नजर आ रही हैं। शिल्पा शेट्टी के इस वीडियो को फैन्स खूब पसंद कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस वीडियो में शिल्पा शानदार डांस तो कर ही रही हैं, लेकिन साथ ही अपने काले चश्मे के साथ स्टंट भी कर रही हैं। शिल्पा शेट्टी का यह टिकटॉक वीडियो खूब देखा जा रहा है। जल्द ही शिल्पा शेट्टी ‘हंगामा 2’ और ‘निकम्मा’ के जरिए एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आने वाली हैं. जहां ‘हंगामा 2’ में वह परेश रावल और मीजान जाफरी के साथ दिखाई देंगी तो वहीं निकम्मा में वह अभिमन्यु दसानी और शर्ली सेतिया के साथ अहम भूमिका निभाती दिखाई देंगी।

अमिताभ-आयुष्मान की गुलाबो सिताबो का टीजर रिलीज

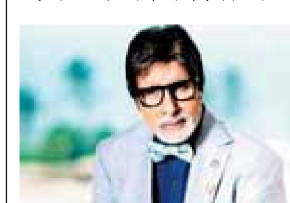

भाषा। मुंबई

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की फिल्म ‘गुलाबो सिताबो’ का टीजर रिलीज कर दिया गया है। कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन के कारण फिल्म ओटीटी (ओवर द टॉप) प्लेटफार्म पर रिलीज की जायेगी।‘गुलाबो-सिताबो’ 12 जून को अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ होगी। फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर ‘गुलाबो सिताबो’ का टीजर रिलीज कर दिया है। गौरतलब है कि अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना पहली बार साथ काम कर रहे हैं। फिल्म 17 अप्रैल को रिलीज़ होनी थी जो कि कोरोना वायरस की वजह से टल गई थी। ‘गुलाबो सिताबो’ एक किराएदार और मकान मालिक के बीच लगातार चलने वाली लड़ाई की मजेदार कहानी है। इस फिल्म में आयुष्मान किराएदार बने हैं और अमिताभ बच्चन मकान मालिक। फिल्म की कहानी की पृष्ठभूमि लखनऊ की है।

अनिल कपूर ने सोशल मीडिया पर बतायी अपनी लवस्टोरी

भाषा। मुंबई

बॉलीवुड के मिस्टर इंडिया अनिल कपूर ने अपने प्रशंसकों के बीच सोशल मीडिया पर अपनी लवस्टोरी शेयर की है। अनिल कपूर और उनकी पत्नी सुनीता कपूर बॉलीवुड में पसंदीदा कपल्स में से एक हैं। 19 मई को अनिल कपूर और सुनीता कपूर की शादी की सालगिरह है, जिसे लेकर अनिल काफी एक्साइटेड भी नजर आ रहे हैं। सालगिरह के जश्न से पहले अनिल कपूर ने सुनीता कपूर के साथ अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने सुनीता कपूर को कैसे प्रपोज किया था। अनिल ने वीडियो में कहा कि मैंने करियर और प्यार में से अपने प्यार को चुना। लोग वेभडग एनिवर्सरी मनाते हैं, जबकि वे प्रपोजल एनिवर्सरी मनाते हैं। अनिल कपूर ने सुनीता कपूर के साथ शेयर किये अपने वीडियो में कहा, कि 17 मई की रात, यह एक लंबी लव स्टोरी की शुरुआत थी। मैंने एक जरूरी फिल्म साइन की थी, जो कि मेरे करियर के लिए बड़ा स्टेप था और 18 मई को भी मैंने एक बड़ा कदम उठाया। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड सुनीता को प्रपोज किया और उनके मेरी पत्नी बनने के बारे में पूछा। हे भगवान, मैं बहुत तनाव में था। मैं इस चीज को बार-बार आगे बढ़ा रहा था और तब समय आ गया जब मुझे अपने करियर और प्यार को चुनना था। और मैंने प्यार चुना और उन्हें 18 मई को प्रपोज कर दिया। अनिल कपूर ने अपने वीडियो बताया, ल्ललोग शादी की सालगिरह मनाते हैं और प्रपोज एनिवर्सरी भी मनाते हैं। हम अपने आप को भूलने नहीं देते कि हम कितने भाग्यशाली हैं।

लॉकडाउन में अरशद ने घटाया छह किलो वजन

भाषा। मुंबई

बॉलीवुड में अपने कॉमिक अभिनय के लिये मशहूर अरशद वारसी ने लॉकडाउन के दौरान अपना छह किलो वजन कम कर लिया है। अरशद ने ट्विटर पर वजन कम करने और डायट प्लान के बारे में बताया। अरशद ने लिखा, ल्लएक महीने के लिए बहुत सख्त डाइट पर था। जीरो कार्ब्स, रुक-रुक कर कार्डियो और वेट ट्रेभनग, 30 दिनों में छह किलोग्राम कम, चार और कम करने योजना। मैंने कार्ब्स लिया और हे भगवान, यह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चीज है। अब मुझे फिट रहने का अन्य जरिया ढूंढ़ना है। अरशद के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए रवीना टंडन ने भी बताया कि उन्होंने भी इसी नियम का पालन किया, लेकिन वह असफल रहीं। रवीना ने लिखा, कैसे, मैं भी ऐसी ही कोशिश की। वजन का कांटा डेढ़ किलो के बाद नीचे ही नहीं गयाङ्क रवीना को अपना फिटनेस रुटीन बताते हुए अरशद , एक विशेष प्रकार का कार्डियो व्यायाम, बीच में रुक-रुक कर ट्रेडमील पर कीटो और इस पर मैं कोई दौड़ नहीं लगाता हूं। यह मेरा आविष्कार है, आपको एक वीडियो भेजता हूं, कोशिश करें, आपको यह पसंद आएगा।

आलिया ने कोरोना वॉरियर्स को भेजा सरप्राइज गिफ्ट

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट ने कोरोना वॉरियर्स का हौंसला बढ़ाते हुये उन्हें सरप्राइज गिफ्ट भेजा है। वैश्विक महामारी जूझ रहे कोराना संक्रमितों की भजदगी बचाने के लिए कोरोना वॉरियर्स अपनी जान लगा रहे हैं। उनके दिन-रात काम करने और लोगों को बीमारी से जंग के जज्बे को देख आलिया ने अनोखे तरीके से उनका मनोबल बढ़ाया है। आलिया ने कोरोना वॉरियर्स को अपनी तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट भेजा है। इस गिफ्ट के साथ एक स्पेशल मैसेज भी है। मुंबई के एक हॉस्पिटल में काम करने वाले एक डॉक्टर ने आलिया के सरप्राइज और थैंक्यू नोट को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। डॉ. श्रीपद गंगापुरकर ने अपने ट्वीटर पर एक तस्वीर शेयर कर आलिया को अपनी ओर से थैंक्यू कहा है। श्रीपद ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें गिफ्ट हैंपर में चॉकलेट बार, स्वीट बन, ड्रिंक के साथ स्नैक्स नजर आ रहा है। साथ ही एक पेपर पर थैंक्यू नोट भी लिखा हुआ है। बॉक्स में चिपके नोट पर आलिया ने मैसेज भेजा है कि, थैंक्यू आप जो कुछ भी कर रहे हैं लोगों को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए। आप असली हीरो हैं। डॉक्टर श्रीपद ने आलिया भट्ट के इस मनोबल सरप्राइज के बदले अपनी ओर से भी एक मैसेज देते हुए लिखा है कि, ल्लधन्यवाद आलिया भट्ट इस स्वीट सरप्राइज के लिए। कोरोना वायरस महामारी के खतरनाक समय के बीच आपका ये गिफ्ट बेहद खास है।

रेसलर हल्क के दीवाने थे रणवीर सिंह

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह बचपन में रेसलर हल्क होगन के दीवाने थे। रणवीर भसह सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी एक्टिव हैं। रणवीर ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर बचपन की एक फोटो शेयर किया है। तस्वीर में रणवीर रेसलर हल्क होगन की तरह पोज देते नजर आ रहे हैं। तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रणवीर हल्क होगन के कितने बड़े फैन हैं। रणवीर ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ल्लआप क्या करेंगे, जब हल्कमेनिया का खुमार आप पर चढ़ जाएगा। वह समय जब डब्लूडब्लूएफ भजदगी हुआ करती थी। पोस्टर मेरी दीवार पर हुआ करता था।